PERFECT 7

FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

सितम्बर 2022 / Issue-2

यूपीएससी और राज्य आधारित पीसीएस परीक्षाओं के लिए उपयोगी

सागरीय पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है धारणीय तटीय प्रबंधन

दक्षिण एशिया में भारत के क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड का केंद्र बनता बांग्लादेश

अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता भारत: स्टार्टअप्स तथा निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष तक पहुंच

सीआरपीएफ का नक्सल विरोधी ऑपेरशन ऑक्टोपस और वामपंथी उग्रवाद पर बढ़ता नियंत्रण

भारत में पशुधन संरक्षण की आवश्यकता: चुनौतियां और समाधान

भारत में जल संकट तथा मिशन अमृत सरोवर

साइबर सुरक्षा के लिए भारत की नई तैयारी और उसके पहलू

dhyeyaias.com

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Offline & Online

COMPREHENSIVE

UPPSC PRELIMS TEST SERIES 2023

Period :
October 2022 to May 2023

TOTAL TEST : 30

(13 Sectional with Current Affairs + 9 GS Full Test + 4 CSAT + 1 Full Current Affairs + 1 Government Schemes & Policies + 1 UP Special + 1 Economic Survey & Budget 2023)

Starting From **9th OCT.**

40% discount for those who are opting for both IAS & PCS test series (40% will be of combined fee of IAS and PCS Test Series).

Note : *Dhyeya Students will be eligible for one fee discount offer only. If he/she takes advantage of being Dhyeya Student, he/she will not be eligible for taking the benefit of 40% discount offer and vice versa.*

Visit Website

Fee Structure:
Offline : Rs. 10,000/-
Online : Rs. 6,000/-

For Dhyeya Students -
Offline Fee - 8,000/-
Online Fee - 4,800/-

Scholarship Test
Only for Offline Students
9th October, 2022

Scholarship Criteria
Rank-1-5 : 100% Discount | Rank-6-10 : 75% Discount
Rank-11-15 : 50% Discount | Rank-16-20 : 25% Discount

Registration Fee For Scholarship Test - Rs. 50/-

FACE TO FACE CENTRES
Delhi (Mukherjee Nagar) Ph: 9289580074 / 75 | Delhi (Laxmi Nagar) Ph: 9205212500 / 9205962002 | Greater Noida Ph: 9205336037 / 38 | Prayagraj Ph: 0532-2260189/8853467068 | Lucknow (Aliganj) Ph: 0522-4025825/9506256789 | Lucknow (Gomti Nagar) Ph: 7234000501/ 7234000502 | Lucknow (Alambagh) Ph: 7518373333/7518573333 | Kanpur Ph: 7887003962/7897003962 | Gorakhpur Ph: 0551-2200385/7080847474

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Offline & Online

COMPREHENSIVE ALL INDIA IAS PRELIMS TEST SERIES 2023

Period :
September 2022 to May 2023

TOTAL TEST : 27

(15 Sectional with Current Affairs + 5 GS Full Test + 4 CSAT + 1 Full Current Affairs + 1 Government Schemes & Policies + 1 Economic Survey & Budget 2023)

Starting From **25th SEPT.**

40% discount for those who are opting for both IAS & PCS test series (40% will be of combined fee of IAS and PCS Test Series).

Note : *Dhyeya Students will be eligible for one fee discount offer only. If he/she takes advantage of being Dhyeya Student, he/she will not be eligible for taking the benefit of 40% discount offer and vice versa.*

Visit Website

Fee Structure:
Offline : Rs. 11,000/-
Online : Rs. 7,000/-

For Dhyeya Students -
Offline Fee - 8,800/-
Online Fee - 5,600/-

Scholarship Test
Only for Offline Students
25th September, 2022

Scholarship Criteria
Rank-1-5 : 100% Discount | Rank-6-10 : 75% Discount
Rank-11-15 : 50% Discount | Rank-16-20 : 25% Discount

Registration Fee For Scholarship Test - Rs. 50/-

FACE TO FACE CENTRES
Delhi (Mukherjee Nagar) Ph: 9289580074 / 75 | Delhi (Laxmi Nagar) Ph: 9205212500 / 9205962002 | Greater Noida Ph: 9205336037 / 38 | Prayagraj Ph: 0532-2260189/8853467068 | Lucknow (Aliganj) Ph: 0522-4025825/9506256789 | Lucknow (Gomti Nagar) Ph: 7234000501/ 7234000502 | Lucknow (Alambagh) Ph: 7518373333/7518573333 | Kanpur Ph: 7887003962/7897003962 | Gorakhpur Ph: 0551-2200385/7080847474

Director's Message

Mr. Vinay Kumar Singh

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

Yours very truly,

Vinay Kumar Singh
CEO and Founder

Mr Q H Khan

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Yours very truly,

Q H Khan
Managing Director

प्रस्तावना

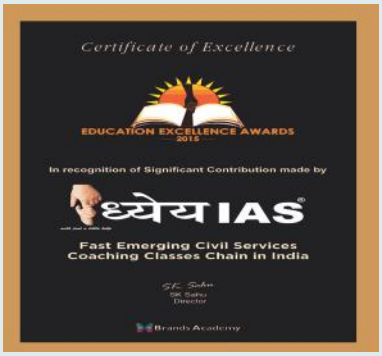

समसामयिक मुद्दे अथवा करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट 7 मैगजीन को विद्यार्थी जगत के समक्ष माह में दो बार रखा जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के तथ्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट 7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कंटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, पेपर 4 के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों के जीवन और भूमिकाओं पर, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर की कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक माह के 14 सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें सर्वाधिक जोर पर्यावरण पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था के मुद्दे शामिल हैं। शब्दावली और अन्य आयामों का एक छोटा खंड भी परफेक्ट 7 मैगजीन का पार्ट होगा।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ाने के लिए ब्रेन-बूस्टर्स को 7 ग्राफिक्स के जरिये, विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैश्विक संस्थाओं एवं संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में सम्मिलित है। इस मैगजीन को केवल तथ्यों या केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का विजन यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। हमें उम्मीद है कि परफेक्ट 7 अपने नए रूप में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और इसके साथ ही आप सभी के सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। धन्यवाद

विनय कुमार सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7 TEAM

प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
	:	बाघेन्द्र सिंह
संपादक	:	विवेक ओझा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
	:	सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक	:	अमन कुमार
प्रकाशन प्रबंधन	:	डॉ.एस.एम. खालिद
संपादकीय सहयोग	:	हरि ओम पाण्डेय
	:	सन्तोष सिंह
	:	शिव वरदान
	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
	:	लोकेश शुक्ल
मुख्य समीक्षक	:	ए.के. श्रीवास्तव
आवरण सज्जा	:	अरूण मिश्र
एवं विकास	:	पुनीष जैन
टंकण	:	सचिन
	:	तरून
कार्यालय सहायक	:	राजू
	:	राहुल

साभार : PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण, डाउन टू अर्थ, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली, योजना, कुरुक्षेत्र, द प्रिंट

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR	: 9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR	: 9205274743
LAXMI NAGAR	: 9205212500, 9205962002
ALLAHABAD	: 0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ)	: 0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW (GOMTINAGAR)	: 7234000501, 7234000502
GREATER NOIDA	: 9205336037, 9205336038
KANPUR	: 7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR	: 8599071555
SRINAGAR (J&K)	: 9205962002

PERFECT 7
FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

विषय सूची

समसामयिकी लेख 1-15
- सागरीय पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है धारणीय तटीय प्रबंधन
- दक्षिण एशिया में भारत के क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड का केंद्र बनता बांग्लादेश
- अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता भारत: स्टार्टअप्स तथा निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष तक पहुंच
- सीआरपीएफ का नक्सल विरोधी ऑपेरशन ऑक्टोपस और वामपंथी उग्रवाद पर बढ़ता नियंत्रण
- भारत में पशुधन संरक्षण की आवश्यकता: चुनौतियां और समाधान
- भारत में जल संकट तथा मिशन अमृत सरोवर
- साइबर सुरक्षा के लिए भारत की नई तैयारी और उसके पहलू

राष्ट्रीय मुद्दे 16-22
अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे 23-27
पर्यावरण मुद्दे 28-31
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मुद्दे 32-36
आर्थिक मुद्दे 37-40
कला संस्कृति 41-42
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 43-47
समसामयिक घटनाएं एक नजर में 48
ब्रेन-बूस्टर 49-55
प्रारम्भिक परीक्षा विशेष 56-64
समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 65-67
व्यक्ति विशेष 68

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

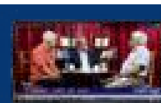

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

सागरीय पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है धारणीय तटीय प्रबंधन

भारत में धारणीय तटीय प्रबंधन न केवल समुद्री पर्यावरण के सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत आवश्यक है। भारत जैसे देश जिसके पास एक लंबी तट रेखा है, उसके लिए सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट तो और भी जरूरी हो जाता है। भारत में तटीय सुरक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 10 सितंबर को भारत के पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट का भुवनेश्वर में उद्घाटन किया। यह सम्मेलन इस रूप में महत्त्वपूर्ण है कि इसने संवेदनशीलता के साथ इस बात पर विचार किया कि भारत के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले तटीय समुदाय के लोगों को जलवायु परिवर्तन की मार से कैसे बचाया जा सकता है? तटीय समुदाय जलवायु परिवर्तन के विनाशक प्रभावों से कैसे बच सकते हैं?इसके लिए तटीय प्रबंधन की जरूरत पर बल दिया गया। जिस तरह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं भारतीय तटों को क्षतिग्रस्त कर देती हैं, उससे पूरा कोस्टल इकोसिस्टम प्रभावित हो जाता है। ये तो सर्वविदित ही है कि भारतीय तट, भारत के समुद्री व्यापार, ब्लू इकॉनमी के विकास और भारतीय नौसेना की ताकत के प्रयोगशाला के रूप में अत्यधिक महत्त्व रखते हैं।

भारत में धारणीय तटीय प्रबंधन का औचित्यः

- सतत विकास, समावेशी विकास, अल्प कार्बन अर्थव्यवस्था के साथ महासागरीय अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकॉनमी के विकास की दृष्टि से भारत में धारणीय तटीय प्रबंधन सबसे बड़ी जरूरतों में से एक के रूप में दिखता है। यही कारण है कि भारत के पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट में 13 राज्यों (9 राज्य एवं 4 केन्द्रशासित प्रदेश) को एक मंच पर लाया गया और एक एकीकृत तटीय सुरक्षा प्रबंधन रणनीति पर संवाद को बढ़ावा दिया गया है। इन भारतीय तटीय राज्यों में तटीय जैव विविधता, समुद्री जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से जुड़े अनुकूलन, कटौती के मुद्दे और तटीय प्रदूषण निवारण जैसे मुद्दों पर आपसी सहयोग हेतु चर्चा की गई है। इसके साथ ही **एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलियेंस ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज नामक 6 वर्षीय प्रोजेक्ट** जो 2019 से 2024 तक चलाया जा रहा है, को और मजबूती से क्रियान्वित करने की बात की गई है। भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यूएनडीपी की मदद से इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित कर रहा है।
- इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले और सबसे अधिक असुरक्षित जनसंख्या विशेषकर महिलाओं और बच्चों को जलवायु परिवर्तन के आघातों से बचाना है। वैसे भी भारतीय तट रेखा का रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्त्व है। तटीय क्षेत्रों में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत निवास करती है।
- इस प्रोजेक्ट के तहत पारिस्थितिकी अवसंरचनाओं में निवेश किया जाना है ताकि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से निपटा जा सके। विशेषकर चक्रवात और तूफानों से निपटने के लिए क्षमता निर्माण भी इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। इस प्रोजेक्ट के जरिए तटीय क्षेत्रों की आजीविका संरक्षण पर बल दिया गया है। इसमें कोस्टल जोन के प्लानिंग और गवर्नेंस को सही दिशा में चलाने के लिए काम करने की तैयारी हो रही है। इस प्रोजेक्ट का जितना बेहतर क्रियान्वयन होगा, उससे उतना ही भारत के **नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (2008)** में निर्धारित जलवायु प्राथमिकताओं की उपलब्धि में योगदान हो सकेगा। इसके साथ ही भारत के **नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन (2015)** के लक्ष्यों को भी हासिल करना आसान हो सकेगा।
- इस प्रोजेक्ट को ग्रीन क्लाइमेट फंड का वित्तीय समर्थन प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड को दुनिया भर के 194 देशों की सरकारों ने स्थापित किया है और उसका मुख्य उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं को मदद देना है। यह एक ऐसा ग्लोबल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तत्वावधान में कार्य करता है तथा जलवायु परिवर्तन कटौती और अनुकूलन के लिए वित्तीय मदद देता है।

भारत में धारणीय तटीय प्रबंधन की दिशा में किये गए उपाय और पहलः

- भारत में धारणीय तटीय प्रबंधन के लिए

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कई प्लान और स्कीम इस दिशा में चलाये गये हैं। जैसे- नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स जिसके जरिए तटीय क्षेत्रों में आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर काम किया जाता है। इसके अलावा कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैन्ग्रोव एंड कोरल रीफ प्रोग्राम के जरिए तटीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों और मैंग्रोव के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कार्य किया जाता है। इसके साथ ही 'डेवलपमेंट ऑफ वाइल्डलाइफ हैबिटेट फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन द कंट्री नामक स्कीम' के जरिए भी धारणीय तटीय प्रबंधन को मजबूती मिली है।

- भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को भी संचालित किया है जिसमें उसे वर्ल्ड बैंक की सहायता मिली है। यह प्रोजेक्ट गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2010 से 2020 तक चलाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य तटीय और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना है। इसके साथ ही भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए 87 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन के साथ 'नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम' के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2019- 20, 2020-21 और 2021-22 के लिए इस मामले में बजटीय समर्थन क्रमशः 75 करोड़, 61 करोड़ और 22 करोड़ था।

भारतीय तटरेखा की सुरक्षा समय की मांग:

- भारत के पास 7516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है जो अक्सर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते संवेदनशील मानी गई है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिन्द महासागर सहित मुख्यभूमि और द्वीपों से घिरी है। वस्तुओं, स्वर्ण, नारकोटिक्स, विस्फोटकों अथवा गोला बारूद की तस्करी और घुसपैठ की घटनाओं से तटीय क्षेत्र कई अवसरों पर असुरक्षित हुआ है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और खाड़ी देशों के साथ भारतीय तटों की भौगोलिक निकटता ने भारतीय तटों को संवेदनशील क्षेत्र बना दिया है। भारत के पश्चिमी तट खाड़ी देशों के निकट स्थित हैं। गुजरात और संयुक्त अरब अमीरात के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर से भी कम है। इस नजदीकी से भारत के पश्चिमी तट से खाड़ी और पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार होता आया है लेकिन इसमें होने वाले पायरेसी (Piracy) से भारत समेत कई राष्ट्रों के हित प्रभावित होते रहते हैं।
- इन तटीय राज्यों में स्थित महत्त्वपूर्ण सामरिक बंदरगाहों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, ऊर्जा परियोजनाओं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की गैर-राज्य अभिकर्ताओं जैसे - आतंकी संगठनों, उग्रवादी समूहों, अलगाववादी गुटों से सुरक्षा, प्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रीय हितों से जुड़ा है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों की सुरक्षा भारत के लिए अति महत्त्वपूर्ण है।

भारत में तटीय सुरक्षा के लिए किए गए उपाय:

- भारत में तटीय सुरक्षा के उद्देश्य से तटीय सुरक्षा स्कीम चरण-1 और स्कीम चरण-2 के जरिए तटीय क्षेत्रों में गश्त लगाने, निगरानी करने और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के प्रयास किए गए हैं। इसके तहत तटीय क्षेत्रों में अवैधानिक तरीके से आवागमन को रोकने और आपराधिक गतिविधि को नियंत्रित करने हेतु तटीय पुलिस स्टेशन, आउटपोस्ट और जांच चौकियों को स्थापित किया गया है।
- भारतीय नौसेना ने मुंबई हमले के बाद मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में ज्वाइंट ऑपरेशंस सेंटर खोले हैं। सभी तटीय सुरक्षा अभियानों को इन केंद्रों द्वारा समन्वित किया जाता है। स्टेट मरीन पुलिस, आसूचना ब्यूरो और अन्य खुफिया एजेंसियों के द्वारा सुरक्षा प्रयासों में मजबूती लाने का काम किया जा रहा है।
- इंडियन कोस्ट गार्ड को मजबूती देने, फिशरमैन वॉच ग्रुप्स के गठन, प्रमुख बंदरगाहों में वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणालियों को लगाने की दिशा में भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विचार किया गया है।
- सागरीय सुरक्षा के मामलों के प्रबंधन के लिए एक शीर्षस्थ निकाय के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में रडारों को लगाया जा रहा है। वर्तमान में 34 से अधिक रडार स्टेशन भारत के मुख्यभूमि पर कार्यशील हैं जबकि 40 कोस्ट गार्ड स्टेशन भी सक्रिय होकर सुरक्षा दायित्व निभा रहे हैं। नियमित अंतराल पर भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, कोस्टल पुलिस, कस्टम्स और अन्य संस्थाओं के ज्वाइंट ऑपरेशनल अभ्यास संपन्न कराए जा रहे हैं।
- तटीय सुरक्षा के लिए नावों का पंजीकरण, नावों पर ट्रांसपोंडर लगाना, मछुआरा बायोमेट्रिक पहचान पत्र की व्यवस्था, तटीय मानचित्रण, सिंगल प्वाइंट मूरिंग की सुरक्षा, सागर प्रहरी बल का गठन जैसे कार्य तटीय सुरक्षा के लिए किए गए हैं।

दक्षिण एशिया में भारत के क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड का केंद्र बनता बांग्लादेश

बांग्लादेश के संदर्भ में अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' को सफल बनाने के लिए भारत लगातार सक्रियता से कार्य कर रहा है। इसको और मजबूती देने के लिए हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत यात्रा पर आयीं। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा हर बार कई मायनों में उपलब्धिपूर्ण होती है क्योंकि इस दौरान कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक संवाद के साथ समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। हाल के वर्षों में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक दूसरे के प्रति आपसी विश्वास बढ़ा है। सितंबर माह में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत के साथ कुछ महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

कॉम्प्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के जरिये आर्थिक संबंधों को नई ऊर्जाः

शेख हसीना की इस यात्रा के दौरान जिन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत के साथ समझौते किये गए हैं, वे इस बात के सूचक हैं कि बांग्लादेश भी भारत के साथ अपने संबंधों को नई ऊर्जा देने की मंशा रखता है। वस्तुतः भारत और बांग्लादेश के संबंध न केवल दोनों देशों के आपसी हितों के लिए जरूरी हैं बल्कि समूचे दक्षिण एशिया और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता, सुरक्षा और विकास के लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए यह तय किया है कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को जल्द से जल्द मूर्त रूप प्रदान किया जाए। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनो देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पहले कॉम्प्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही वह समझौता है जो व्यापारिक बाधाओं को दूर कर ट्रेड के मामलों में विश्वास बढ़ायेगा। दरअसल चीन, बांग्लादेश के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर बांग्लादेशी बाजारों में मजबूत पहुँच बनाना चाहता है जो भारत के आर्थिक हितों के लिहाज से चुनौतीपूर्ण है। वहीं इस बात का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है कि बांग्लादेश, भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर के साथ दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। यदि भारत का बांग्लादेश के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी सम्पन्न हो जाए तो भारत का बांग्लादेश को किया जाने वाला निर्यात भी बढ़कर 17 बिलियन डॉलर हो सकता है। भारत का यह भी प्रयास है कि वह अपने लगभग 450 वस्तुओं पर बांग्लादेशी इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी करने के लिए बांग्लादेश को तैयार करे।

सहयोग के नए बिंदुओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूतीः

दोनों देशों का मानना है कि कोविड महामारी और हाल के वैश्विक घटनाक्रम से सीख लेकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना होगा। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान सहयोग के महत्त्वपूर्ण बिंदुओं की तलाश की गई और दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि वे 'इनफॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी' और अंतरिक्ष सहयोग को मजबूती प्रदान करेंगे। इसके साथ ही दोनों देशों ने नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने पर भी आपसी सहमति बनाई है। गौरतलब है कि भारत, दुनिया के 17 देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर चुका है।

कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के जरिये अर्थव्यवस्था को मजबूतीः

भारत और बांग्लादेश का मानना है कि कनेक्टिविटी के विस्तार और सीमा पार व्यापार अवसंरचना के विकास से दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से और अधिक जुड़ेंगी एवं एक दूसरे को समर्थन दे पायेंगी। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार भी इसके जरिये तेजी से बढ़ेगा। बांग्लादेश के निर्यात के लिए आज भारत पूरे एशिया में सबसे बड़ा बाजार है। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच वस्तुओं और सेवाओं का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 बिलियन डॉलर है।

दोनों देशों के बीच पावर ट्रांसमिशन लाईनों को जोड़ने पर भी उपयोगी बातचीत चल रही है। इसमें रूपशा नदी पर रेलवे ब्रिज (5.13 किमी.) का उद्घाटन कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। यह ब्रिज भारत द्वारा बांग्लादेश को दिए लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत खुलना और मोंगला पोर्ट (64.7 किमी.) के बीच बनाई जा रही नई रेलवे लाईन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश के रेलवे सिस्टम के विकास और विस्तार के लिए भारत ने हर प्रकार का सहयोग जारी रखने की बात कही है।

भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा व्यापार पर सहयोगः

- प्रधानमंत्री शेख हसीना की इस बार की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने माना कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतें इस समय सभी विकासशील देशों के लिए चुनौती बन

रही हैं। इसी को ध्यान में रखकर भारत के सहयोग से निर्मित 'मैत्री थर्मल पावर प्लांट' की पहली यूनिट के अनावरण से बांग्लादेश में सस्ती बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी।

- भारत और बांग्लादेश में द्विपक्षीय स्तर पर कई ऊर्जा परियोजनाओं को चलाया जा रहा है जो आर्थिक के साथ ही सामरिक महत्त्व के भी हैं। भारत के एनटीपीसी के सहयोग से बांग्लादेश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट (1320 मेगावाट) लगाया गया जो अब कार्यशील हो चुका है। इसे बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पॉवर कंपनी के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित किया गया था। यह तापीय विद्युत स्टेशन बांग्लादेश के खुलना क्षेत्र में लगाया गया था।
- भारत बांग्लादेश मित्रता पाइपलाइन भी दोनों देशों के ऊर्जा संबंधों को दर्शाता है। यह 136 किमी. लंबी पाइपलाइन है जिसमें 130 किमी. बांग्लादेश के क्षेत्र में और 6 किमी. भारत के भू-भाग में है। इसके तहत पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से डीजल की आपूर्ति उत्तरी बांग्लादेश के पार्वतीपुर (जो दिनाजपुर जिले में स्थित है) को किया जाएगा। असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी द्वारा भारतीय भू-भाग वाले पाइपलाइन के निर्माण कार्य का वित्त-पोषण भी किया जाएगा। इस पाइपलाइन के जरिए पहले वर्ष भारत 2.5 लाख टन तेल की आपूर्ति बांग्लादेश को करेगा और इसके पूर्ण रूप से निर्मित हो जाने पर प्रति वर्ष 4 लाख टन तेल की आपूर्ति बांग्लादेश को की जाएगी। असम के नुमालीगढ़ के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के कारण बांग्लादेश और उत्तर-पूर्वी भारतीय राज्यों में विकास परियोजनाओं की प्रत्येक संभावना को खोजने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया गया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश ने 2021 तक इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था जिसे पूरा करने में भारत ने बांग्लादेश की मदद की। बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा में भारत प्रभावी भूमिका निभा रहा है।
- भारत ने बांग्लादेश को विद्युत आपूर्ति भी शुरू कर दी है। सीमा पार ऊर्जा व्यापार भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। बांग्लादेश को भारत की दक्षिण एशिया केंद्रित पड़ोसी प्रथम नीति, उसकी ऊर्जा कूटनीति और विस्तारित पड़ोसी प्रथम की नीति का एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ माना जाता है। सितंबर, 2019 में बांग्लादेश ने भारत के रिलायंस पावर के साथ 750 मेगावॉट बिजली खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के अंतर्गत अगले 22 वर्षों तक बांग्लादेश, भारत से बिजली खरीदेगा। रिलायंस पॉवर ने 2022 तक बांग्लादेश के नारायणगंज में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेश योजना तैयार की है। वर्ष 2020 में ही भारत ने बांग्लादेश के साथ एलपीजी खरीदने का समझौता भी किया है। इस प्रकार दोनों देश ऊर्जा संबंधों को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग से बांग्लादेश लाभान्वित हो सकता है। बांग्लादेश ने भारत के सौर ऊर्जा उद्योग में भी अपनी रुचि प्रदर्शित की है। कुछ समय पहले वर्ल्ड बैंक के प्रमुख निकाय अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने बांग्लादेश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता किया है जिसके तहत वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करेगा। इससे स्पष्ट है कि बांग्लादेश में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए बड़ी संभावना विद्यमान है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2019 में झारखंड के गोड्डा जिले में विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से 4 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को गठित करने की अनुमति दी थी। इससे उत्पादित समस्त बिजली का निर्यात बांग्लादेश को किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य 2022 तक हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट के लिए अधिकृत अडानी पॉवर ने इन संयंत्रों से उत्पादित शत-प्रतिशत बिजली बांग्लादेश को आपूर्ति करने के लिए पॉवर परचेज एग्रीमेंट को संपन्न कर लिया है। इस बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की यात्रा के दौरान अडानी पावर के प्रमुख ने ऊर्जा समझौतों पर उनसे चर्चा की थी।
- भारत और बांग्लादेश को अपने आपसी हितों के लिए सहयोग को लगातार बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा पैदा करने वाले कई तत्व मौजूद हैं। साथ ही चीन भी दक्षिण एशिया में अपनी विस्तारवादी मानसिकता से कोई समझौता नहीं करता दिखाई दे रहा है। इसलिए भारत और बांग्लादेश को पारस्परिक लाभ के लिए मिलजुलकर कार्य करना होगा। साथ ही बांग्लादेश को चीन के साथ आर्थिक संबंधों में अपनी आर्थिक संप्रभुता पर भी ध्यान रखना होगा ताकि दक्षिण एशिया में किसी देश की हालत श्रीलंका जैसी न हो।

अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता भारत: स्टार्टअप्स तथा निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष तक पहुंच

सन्दर्भ:

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र भी अब निजी क्षेत्र के लिए खोला जा रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र का यह निजीकरण; व्यावसायिक अंतरिक्ष परियोजनाओं, अंतरिक्ष पर्यटन तथा अंतरिक्ष अनुसंधान में वृद्धि करते हुए भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

परिचय:

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई कदम उठाये गए। इसका प्रभाव अंतरिक्ष क्षेत्र में भी देखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषित 'आत्मनिर्भर भारत विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज' (ANBSESP) के चौथे भाग में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजीकरण की बात की गई है। यह निजीकरण न सिर्फ अंतरिक्ष के क्षेत्र में नवीन अवसरों को जन्म देगा बल्कि अनुसंधान एवं विकास को भी गति प्रदान करेगा। हालांकि अंतरिक्ष एक महत्त्वपूर्ण रणनैतिक क्षेत्र है, अत: इसमें उठाये गए कदमों को स्पष्ट रूप से जनता के समक्ष रखना होगा।

भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र:

- भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) के गठन के साथ पड़ी। यह समिति डॉ. विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में बनाई गई थी। अत: उन्हें 'भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक' भी कहा जाता है। 1963 में थुंबा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे प्रक्षेपित किया गया।
- 1969 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति तथा अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र को पुनर्गठित कर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का निर्माण किया गया। इसका परिणाम 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट (सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान) के प्रक्षेपण से दिखा।
- वर्तमान समय में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम चंद्रमा, मंगल जैसे ग्रहों तक पहुंच चुका है तथा अब भारत विश्व के शीर्ष अंतरिक्ष उपलब्धियों वाले देशों में से एक बन गया है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मात्र दूरसंचार, कम्युनिकेशन, मौसम तथा रणनैतिक प्रयोग जैसे कार्यो तक सीमित नहीं है बल्कि यह अंतरिक्ष अनुसंधान तथा अंतरिक्ष पर्यटन में भी प्रगति कर रहा है।
- भारत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उपयोगी सभी यंत्रों जैसे-यान (पीएसएलवी, जीएसएलवी), उपग्रह (दूरसंचार, रणनैतिक) इत्यादि में महारत प्राप्त किया है। इसलिए वैश्विक अंतरिक्ष जगत के शीर्ष-5 देशों में भारत का स्थान है।
- अभी तक अंतरिक्ष क्षेत्र पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रणाधीन था परंतु अब धीरे-धीरे अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भी सहभागिता बढ़ाई जा रही है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से भारत को होने वाले लाभ:

लागत तथा व्यय में कमी:

- वर्तमान समय में अंतरिक्ष गतिविधियों तथा अनुसंधान एवं विकास में होने वाले व्यय का 95% से अधिक भाग इसरो तथा सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। निजी क्षेत्र के आने से यह व्यय कम होगा जिससे सरकार के संसाधनों पर दबाव कम होगा तथा इन संसाधनों का प्रयोग सरकार कल्याण-कारी योजनाओं में करके भारत को आत्मनिर्भर बनने हेतु मदद कर सकती है। 2016 से 2019 के आंकड़ों के अनुसार वेंचर कैपिटल की मदद से अंतरिक्ष स्टार्ट-अप 'हथेली के आकार' के सैटेलाइट से लेकर छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) को विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए AGNIKUL तथा SAKARUT जैसे स्टार्टअप प्रक्षेपण यान प्रमुख हैं।

नवाचार में वृद्धि:

- अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्टार्टअप्स तथा निजी क्षेत्र के आने से प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में वृद्धि होगी। उदाहरण स्वरूप एक निजी संस्था ध्रुव स्पेस उपग्रहों के लिए उच्च तकनीकी पर आधारित सोलर पैनल को विकसित करने पर कार्य कर रहा है।

विदेशी निर्भरता में कमी:

- निजी क्षेत्र के द्वारा निवेश, क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं विकास, वित्त

इत्यादि पर काम किया जाएगा जिससे भारत की विदेशी संस्थानों पर निर्भरता निरंतर कम होती जाएगी जो भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाएगी।

नए आयामों का सृजन:

- निजी क्षेत्र के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी जिससे अंतरिक्ष पर्यटन तथा अंतरिक्ष शिक्षा जैसे नवीन आयामों को बढ़ावा मिलेगा।

वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था भागीदारी में वृद्धि:

- वर्तमान समय में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग 450 बिलियन डॉलर है तथा 2040 तक इसके लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में मात्र 2% का भागीदार है। निजी क्षेत्र के आने से भारत की वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ेगी।

भारत की अंतरिक्ष आत्मनिर्भरता के समक्ष चुनौतियां (निजी क्षेत्रक के आने से होने वाली हानियां):

- अभी तक संसद द्वारा 2017 से लंबित पड़े अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक को पारित नहीं किया जा सका है। इस विधेयक में अंतरिक्ष अपराध, अंतरिक्ष में हुए हानि के लिए दायित्व तथा निजी क्षेत्र से संबंधित मामलों की बात की गई है परंतु इस विधेयक को अभी तक पारित न किए जाने से निजी क्षेत्र के 'स्पेस में दायित्व' को शामिल करने में कठिनता आएगी।
- वर्तमान समय में विभिन्न देशों के स्पेस गतिविधियों के कारण भारी मात्रा में अंतरिक्ष मलबों का निर्माण हो चुका है। लाभोन्मुख होने के कारण निजी क्षेत्र का ध्यान अंतरिक्ष से मलबा हटाने पर नहीं होगा। अत: यह अंतरिक्ष पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है।
- वर्तमान समय में एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के आने के कारण 'अंतरिक्ष युद्ध' जैसी स्थितियां बन रही हैं। अत: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है।
- अंतरिक्ष की महंगी प्रक्रियाओं के कारण इस क्षेत्र में एकाधिकार की संभावनाएं भी बन सकती हैं।

क्या आप जानते हैं?

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN&SPACe):

- इसका गठन 2020 में किया गया था।
- यह भारत में गैर-सरकारी निजी संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, उन्हें अधिकृत करने तथा उनकी निगरानी व पर्यवेक्षण करने के लिए एक स्वायत्त सिंगल विंडो वाली नोडल एजेंसी है।
- यह इसरो के नियंत्रण में कार्य करती है तथा इसरो की ही अंतरिक्ष संबंधी अवसंरचना व परिसर को साझा करती है। इसका निर्णय इसरो सहित अन्य अंतरिक्ष हितधारकों के लिए बाध्यकारी होता है।

अंतरिक्ष आधारित संचार नीति, 2020:

इस नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष संचार की बढ़ती आवश्यकता को पूर्ण करते हुए वाणिज्यिक सुरक्षा तथा सामाजिक संचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है तथा इसी दिशा में प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर भी जोर देना है।

आगे की राह:

- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को लागत प्रभावी बनाने के लिए सरकार को प्रारंभिक इनक्यूबेटर तथा अनुदान कार्यक्रम के माध्यम से नए स्टार्टअप को सहायता करनी होगी। यह न सिर्फ स्टार्टअप्स के साथ अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा बल्कि एकाधिकार की समस्या को भी कुछ हद तक समाप्त कर सकता है।।
- सरकार को जल्द से जल्द अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र के गतिविधियों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने होंगे तथा यह नियम बाह्य अंतरिक्ष अभिसमय के मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि सरकार अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक को पारित करे।
- सरकार को चाहिए कि आरंभ के कुछ वर्षों में परियोजनाएं पीपीपी माध्यम के द्वारा हो। हालांकि सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है तथा निजी कंपनियां भी प्रक्षेपण के लिए सरकार द्वारा निर्मित संरचनाओं का ही प्रयोग कर रही हैं।
- अंतरिक्ष के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा से संबंधित नीतियों को बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

21वीं शताब्दी में अंतरिक्ष तकनीकी हमारे पर्सनल स्पेस का अंग बनती जा रही है। अत: इस दिशा में ये कदम अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। अंतरिक्ष उपयोग के कुछ ऐसे क्षेत्र (जैसे अंतरिक्ष पर्यटन) हैं जिनके लिए निजी क्षेत्र सर्वोत्तम होगा। इसी के साथ- साथ कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे-स्पेस वार, नेविगेशन नियंत्रण, संचार, रणनैतिक गतिविधियां हैं जहां सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत होने की आवश्यकता है। अत: यह कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी न होकर एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा इनकी यही पारस्परिक निर्भरता भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोगी होगी।

सीआरपीएफ का नक्सल विरोधी ऑपेरशन ऑक्टोपस और वामपंथी उग्रवाद पर बढ़ता नियंत्रण

- हाल ही में झारखंड पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने तीन दिवसीय विशेष नक्सल विरोधी अभियान **'ऑक्टोपस'** चलाया जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किये गए। यह अभियान झारखंड के लातेहार के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में चलाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार की 106 लैंडमाइन्स, 360 से ज्यादा कारतूस, कोडेक्स वायर, अमोनियम नाइट्रेट, बम और विभिन्न प्रकार के विस्फोटक बरामद किए गए।
- झारखंड पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि बूढ़ा पहाड़ अत्यधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहां माओवादियों ने कदम-कदम पर लैंड माइंस बिछाए हुए हैं जिसके विस्फोट से अक्सर पूरा क्षेत्र थर्रा जाता है। इस क्षेत्र में माओवादियों ने पुलिस और लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया है। सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ की चारों ओर से घेराबंदी कर इस अभियान को अंजाम दिया।
- भारत के गृह मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो झारखंड के 23 जिलों में से 19 जिले वामपंथी उग्रवादी हिंसा से ग्रसित हैं और राज्य को नक्सली मुक्त बनाने के लिए अभी काफी प्रयास किया जाना शेष है।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड में माओवाद प्रभाव वाले 16 जिलों में रांची, खूंटी, बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। वहीं झारखंड में 8 अति माओवाद प्रभावित जिलों में चतरा, गिरिडीह, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। देश के अति माओवाद प्रभाव वाले 25 में से 8 जिले झारखंड के हैं।

देश में वामपंथी उग्रवाद की वर्तमान स्थिति:

- वामपंथी उग्रवाद में नक्सलवाद, माओवाद और उससे जुड़ी हिंसा शामिल है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 10 राज्यों के 46 जिलों में वामपंथी उग्रवाद और उससे जुड़ी हिंसा है। केंद्र सरकार ने राज्य सभा में भी यहीं आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। 2010 में 10 भारतीय राज्यों के 96 जिले इससे प्रभावित थे। पिछले दशक में वामपंथी उग्रवाद में उल्लेखनीय कमी आई है। 2021 में उग्रवाद के 505 मामले सामने आए जो 2009 के 2258 मामलों की तुलना में 77 प्रतिशत कम है। 2021 में उग्रवादी घटनाओं में 147 नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु हुई है जो 2010 में हुई 1005 मृत्यु के आंकड़े से 85 प्रतिशत कम है।
- पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने संसद में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में कमी का आंकड़ा साझा करते हुए यह भी बताया था कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम के तहत शामिल वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 2018 के 90 से घटकर 2021 में 70 हो गई। 2018 के पहले की बात करें तो इस स्कीम के अंतर्गत नक्सलवाद और माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में कमी इस बात का सूचक है कि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में समावेशी विकास के कार्यक्रमों को सफल बनाया जा रहा है लेकिन समय-समय पर कई अन्य नए क्षेत्रों में भी अनेक कारणों से वामपंथी उग्रवाद उभरता आया है। इसके चलते गृह मंत्रालय को नए जिलों को भी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची में शामिल करना पड़ता है। वहीं जिन जिलों में वामपंथी उग्रवादी हिंसा में बड़े पैमाने पर कमी आती है अथवा वहां इसका प्रभाव शून्य देखा जाता है तो उसे गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की सूची से बाहर भी कर देता है। जैसे- वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय ने 44 जिलों को इससे बाहर निकाल दिया था लेकिन इसके साथ ही 8 नए जिलों को शामिल भी करना पड़ा था।

फ्रंट आर्गेनाइजेशन एक चुनौती के रूप में:

- भारत सरकार ने गृहमंत्री के नेतृत्व में पिछले साल वामपंथी उग्रवाद के मुद्दे पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी जिसमें एक प्रमुख निष्कर्ष के रूप में यह सामने आया था कि जिन 10 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद है वहां फ्रंट ऑर्गनाइजेशन की भूमिका के चलते नक्सलवाद और माओवाद को मजबूती मिली है। इसीलिए समीक्षा बैठक में फ्रंट ऑर्गनाइजेशन के खिलाफ कठोर

कार्यवाही करने की बात की गई है। राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया कि वह अपने यहां जरूरी कानूनों के तहत फ्रंट ऑर्गनाइजेशन के खिलाफ कार्यवाही करें। वहीं केंद्र सरकार अवैधानिक क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत फ्रंट आर्गेनाइजेशन से निपट सकती है।

- **फ्रंट ऑर्गनाइजेशंस:** माओवादियों तथा नक्सलियों के उद्देश्य को पूरा करने में फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह संगठन मूल माओवादी पार्टी (सीपीआई-माओवादी) के सह-उत्पाद के रूप में होते हैं जो किसी भी वैधानिक दायित्व से बचने के लिए अपना एक पृथक अस्तित्व रखते हैं। फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस मुख्य रूप से माओवादी दल के लिए दुष्प्रचार अथवा भ्रामक सूचनाओं को फैलाते हैं और पेशेवर उग्रवादियों की भर्ती करते हैं जिससे भूमिगत आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सके। ये विप्लव (इंसरजेंसी) के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करते हैं, वैधानिक मामलों में कैडरों को सहायता करते हैं और भूमिगत कैडरों को सुरक्षित स्थल एवं शरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके अलावा फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस में कार्य करने वाले माओवादी विचारधारा में अंतर्निहित हिंसा का बौद्धिक स्तर पर महिमामंडन करते हैं। दूसरे शब्दों में यह संगठन शहरी समुदायों और मीडिया तक माओवादियों के दृष्टिकोण को पहुंचाने में और हिंसक रक्तपात को औचित्यपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार देश के 10 राज्यों में फ्रंट ऑर्गनाइजेशन मौजूद हैं जो विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सक्रिय हैं।

माओवाद और नक्सलवाद एक चुनौती के रूप में:

- माओवाद एक ऐसी विचारधारा है जो विधि द्वारा स्थापित शासन तंत्र को अन्याय, शोषण, दमन का मुख्य उपकरण मानता है और इसलिए यह सत्ता के हर प्रतीक का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखता है। जैसे- सरकारी वित्त से चलाए जाने वाले स्कूलों, चिकित्सालयों, सुरक्षा बलों के केंद्रों को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करना। इसके साथ ही पारंपरिक रूप से माओवाद को संसदीय शासन तंत्र में विश्वास भी नहीं है। इसलिए यह चुनावों का बहिष्कार करता रहा है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में चुनावों का न होने देना, चुनाव कर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों का अपहरण और हत्याएं इसकी कार्यप्रणाली में शामिल हैं।
- वहीं नक्सलवाद मूल रूप से देश की सामाजिक-आर्थिक विषमता, अपर्याप्त भूमि सुधार, विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक पिछड़ेपन और विकास परियोजनाओं के चलते आदिवासी समुदाय के लोगों के विस्थापन जैसी स्थितियों की देन मानता है। 2004 में सीपीआई (एम) के गठन के बाद से नक्सली भी बड़े स्तर पर माओवादी कार्यपद्धति से प्रभावित हुए और इन दोनों के कार्यप्रणाली में समानता देखने को मिली है।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने की केंद्र सरकार की रणनीति:

- केंद्र सरकार नक्सलवाद और माओवाद से निपटने के लिए एक समग्र नीति लागू कर रही है। इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षाबलों की तैनाती करने के साथ ही विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि माओवाद से प्रभावित अब केवल 10 राज्य- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं जो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न करते हैं। वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को अगर समझना है तो उसे वर्ष 2015 के 'नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म' के जरिए जाना जा सकता है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय वर्ष 2015 से नक्सलवाद से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसमें 4 बातों पर बल दिया गया है जो हैं:

1. सुरक्षा से संबंधित उपायों के साथ-साथ विकास के कार्यों पर बल।
2. स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों (Entitlement) को सुनिश्चित करने पर बल।
3. शासन प्रणाली में सुधार।
4. जन अवबोधन (पब्लिक परसेप्शन) प्रबंधन के लिए प्रभावी उपाय करना।

- वहीं गृह मंत्रालय के **समाधान रणनीति** के तहत कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण, सक्रिय खुफियातंत्र, कार्ययोजना के मानक, आधुनिक प्रोद्यौगिकी प्रयोग, प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना और नक्सलियों के वित्तपोषण को विफल करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बायोमेट्रिक समर्थित ड्रोंस और स्मार्ट गन के प्रयोग, वामपंथी उग्रवादियों के हथियारों की छानबीन के लिए ट्रैकर्स के उपयोग पर बल दिया है। इसके अलावा जिलेटिन स्टिक्स और विस्फोटकों के लिए यूनीक आइडेंटीफिकेशन नंबर की बात की गई है।
- गृह मंत्रालय ने इस बात पर भी गंभीरता से विचार करना शुरू किया है कि सीएपीएफ बटालियन के लिए कम से कम एक यूएवी (मानव रहित विमानों) और मिनी यूएवी की सुविधा (माओवादी क्षेत्रों के लिए) मिल सके। वामपंथी उग्रवाद निरोधी अभियानों के

लिए अधिक हेलीकॉप्टर समर्थन और ग्रेहाउंड (Greyhound) जैसे विशेष प्रशिक्षित बलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

- हाल के वर्षों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सोलर लाइट, 3 जी कनेक्टिविटी के साथ मोबाइल टॉवर्स और रोड रेल कनेक्टिविटी की सुविधा देने पर सक्रियता से काम किया गया है।
- वामपंथी उग्रवादी गुटों तक वित्त की पहुंच को रोकने के लिए 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA)' की समीक्षा कर उसमें संशोधन करने की बात भी हुई है। इसके साथ ही नक्सल और माओवाद विरोधी अभियानों के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन, सक्रिय खुफिया तंत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर भी कार्य किया जा रहा है।
- वामपंथी उग्रवाद (LWE) को कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर वित्त वर्ष 2021-22 तक 6,578 करोड़ रुपए जारी किए गये, जबकि वित्त वर्ष 2006-2007 से वित्त वर्ष 2013 तक 2,181 करोड़ रुपए ही जारी किए गए थे।
- नक्सल प्रभावित इलाकों के समावेशी विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधा देने के कार्य में पिछले कुछ वर्षों में तेजी आई है। केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई सारी योजनाएं चला रही है जिसमें स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम, रोड कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट स्कीम, जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और आर्थिक मदद जैसी योजनाएं शामिल हैं।
- उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 32 केंद्रीय और 9 जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। वहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों को 2017 से 2021 के बीच विभिन्न परियोजनाओं के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 207 एकलव्य आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी गई है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित अधिकांश जिलों में 1,258 बैंक शाखाएं और 1,348 एटीएम स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 4,903 नए डाकघर भी खोले गए हैं।

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA SUPER 50

Registration Fee : ₹100/-

Batch Duration November 2022- April 2023

Comprehensive Guidance Program
For Civil Services & State PCS Exams

For Admission in **Dhyeya Super 50** Batch
Entrance Exam Date

Prelims 9th October, 2022
Mains 16th October, 2022
Interview 27th, 28th, 29th Oct. 2022

Key Features :
- Special focus on UPSC CSE Prelims 2023
- NCERT Based Revision and Weekly Classes
- One-to-One Mentorship of every aspirant
- Weekly Current Affairs Classes / Editorial Discussion
- Regular Test and Performance Evaluation
- Special Focus on Answer Writing and Essay Writing skill

Lucknow (Aliganj) :
A-12 Sector-J Aliganj, Lucknow
Call : 9506256789, 7570009002

भारत में पशुधन संरक्षण की आवश्यकता: चुनौतियां और समाधान

सन्दर्भ:

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों का योगदान अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रहा है परन्तु पशुपालन (प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि) का आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। पशुधन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 4.11% तथा 8 करोड़ से अधिक किसानों की आजीविका का साधन है।

परिचय:

भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में लगभग 20.5 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर हैं। लघु कृषक परिवारों की आय में पशुधन का योगदान लगभग 16% है, जबकि ग्रामीण परिवारों की औसत आय में यह 14% का योगदान देता है। इसके साथ पशुधन दो-तिहाई ग्रामीण समुदाय को आजीविका प्रदान करता है। यह भारत में लगभग 8.8% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। पशुधन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 4.11% और कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 25.6% योगदान देता है। भारत विश्व में सर्वाधिक पशुधन (535.78 मिलियन) रखता है। भारत भैंसों की जनसंख्या तथा दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम वहीं बकरी, मछली उत्पादन, पोल्ट्री बाजार तथा जलीय कृषि के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है।

भारत में पशुधन का योगदान:

- वर्तमान समय में भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व का सर्वाधिक अग्रणी देश है। एफएओ के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2020-21 के दौरान लगभग 209 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया था।
- यद्यपि पशुधन क्षेत्रक के विकास से दूध, अंडे और मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में सुधार हुआ है तथापि विकसित देशों की तुलना में प्रति पशु उत्पादकता बहुत कम है। भारत सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वे (2021-2022) के अनुसार देश में दुग्ध उत्पादन 2014-15 की तुलना में लगभग 6.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 2020-21 में 209.96 मिलियन टन हो गया है।
- भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी भेड़ आबादी (74.26 मिलियन) वाला देश है। इसी के साथ भारत दुनिया का नौवां सबसे बड़ा ऊन (भेड़ों से प्राप्त) उत्पादक देश है। यह भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है।
- इसके साथ ही मांस उत्पादन तथा मत्स्य उत्पादन में भारत विश्व के शीर्ष देशों में आता है। पशुधन के द्वारा कृषकों को भी अपनी आय दोगुनी करने में सहयोग मिलता है जो कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 25.6% योगदान देता है।

पशुधन के क्षेत्र में चुनौतियाँ:

- **उत्पादकता की कमी:** भारत पशुधन क्षेत्र में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है परन्तु इसकी उत्पादकता कम है। उदाहरणस्वरूप- भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी भेंड़ आबादी रखता है परन्तु ऊन उत्पादन में यह 9वें स्थान पर है।
- **रोगग्रस्त पशुधन:** पशुधन क्षेत्र में अच्छी वृद्धि के बावजूद संक्रामक रोग पशुधन क्षेत्र के कुशल विकास में बाधक बन रहें हैं। संक्रामक बीमारियाँ जैसे- खुरपका, मुंहपका रोग (एफएमडी), गलाघोंटू, ब्रूसेलोसिस एवं लंगड़ा बुखार इत्यादि न सिर्फ पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं बल्कि इसके व्यापक नकारात्मक आर्थिक प्रभाव भी आते हैं। हाल ही में लम्पी वायरस से अनेकों पशुओं की आकस्मिक मृत्यु हुई है जो चिन्ता का विषय है।
- **जूनोटिक रोग:** पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले जूनोटिक रोग भी एक बड़ी समस्या है। पारंपरिक पशुपालन प्रणालियों तथा सीमित जैव सुरक्षा उपायों का पशुधन के साथ निकट संपर्क होने से मनुष्यों में प्राय: जूनोटिक रोग संचरण की संभावना बढ़ जाती है।
  - » आंकड़ों के अनुसार भारत में मवेशियों में अकेले एफएमडी के कारण लगभग 22 हजार करोड़ रूपये वार्षिक का आर्थिक नुकसान होता है।
- **पशु चिकित्सा के बुनियादी ढांचे में कमी:** भारत में पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे में कमी है तथा अभी भी अधिकांश भारतीय लोग पारम्परिक पशु चिकित्सा पर ही निर्भर हैं। राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रति एक से दो लाख पशुओं पर एक पशु चिकित्सक है तथा कई गांवों में अभी भी बुनियादी परीक्षण सुविधाओं और आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव है।
  - » फील्ड स्टाफ की कमी के कारण

टीकाकरण अभियान की प्रगति अत्यधिक मंद है।

- **टीकाकरण की व्यवहार्यता में कमी:** सरकार द्वारा रोगों के निदान के लिए टीकाकरण की योजनाएं आरम्भ की गई हैं। हालांकि परीक्षण सुविधाओं और आवश्यक बुनियादी ढांचे की पर्याप्त उपलब्धता न होना, यह न केवल पशुपालकों के लिए परेशानी की बात है बल्कि इससे जूनोटिक रोगों का खतरा भी पैदा हो गया है। यह बेहद चिंताजनक है क्योंकि जूनोटिक रोगों के मामले बढ़ रहे हैं जो मानव जाति के लिए भी घातक होते जा रहे हैं।
  - » कई बार पशुपालकों को लगता है कि टीकाकरण कराने से पशु का दूध कम हो जायेगा या गर्भपात हो जायेगा। यह धारणा भी शत-प्रतिशत टीकाकरण के मार्ग में बाधक है।
- **टीकों की गुणवत्ता में कमी:** टीकों की गुणवत्ता पशुओं के रोग की अन्य बड़ी समस्या है। वर्तमान में भारत में ब्रूसेलोसिस वैक्सीन आवश्यकता से 58 मिलियन वैक्सीन कम है। परीक्षणों से पता चला कि मौजूदा एफएमडी वैक्सीन के नमूने गुणवत्ता मानदंडों पर खरा नहीं उतरते हैं। इससे कृषकों में चिंता व्याप्त है क्योंकि दोषपूर्ण टीकाकरण से घातक संक्रामक बीमारियों का खतरा हो सकता है।

पशुधन क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार द्वारा किये गए प्रयत्न

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम:

- सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) योजना आरम्भ की।
- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य मवेशियों, भैंसों, भेंड़ों, बकरियों और शूकरों की आबादी का शत-प्रतिशत एफएमडी टीकाकरण तथा 4 से 8 महीने की उम्र के गो-जातीय मादा बछड़ों का शत प्रतिशत ब्रूसेलोसिस टीकाकरण करना है।
- इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत 2023-2024 तक 51 करोड़ से अधिक पशुओं का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- यह खुरपका, मुंहपका (एफएमडी) और ब्रूसेलोसिस को 2024 तक नियंत्रित करना और 2030 तक इसका पूर्णतः उन्मूलन करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए केंद्र सरकार ने पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के लिए 13,343 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया है।
- हालांकि 2030 तक शत-प्रतिशत टीकाकरण की राह पशु चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को देखते हुए मुश्किल प्रतीत होती है।

पशुओं की टैगिंग:

- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंर्तगत 'पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य सूचना तंत्र' के माध्यम से पशुओं की टैगिंग भी की जा रही है। हालांकि पशुपालक अपने पशुओं की टैगिंग कराने से कतरा रहे हैं।

आगे की राह:

- **बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता:** टीकाकरण की सफलता के लिए आवश्यक है कि बुनियादी पशु चिकित्सा में पर्याप्त सुविधाएं हों। इसके लिए ग्रासरूट लेवल पर कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। इसके साथ ही ये कुशल श्रमिक स्थानीय हों जिससे पशुपालकों के टीकाकरण के प्रति विश्वास को मजबूत किया जा सके। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को भी मजबूत करने की आवश्यकता है।
- **फंड की उपलब्धता:** केंद्र और राज्य सरकारों को पशु चिकित्सा के लिए अधिक फंड विनियोजित करना चाहिए जिससे राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की जा सके। इस सन्दर्भ में पशुपालन तथा पशु टीकाकरण के लिए राज्य और केंद्र सरकार को एकीकृत तरीके से काम करना चाहिए।
- **जागरूकता:** पशुपालन विभाग को समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए जिससे पशुपालकों के विश्वास में वृद्धि हो तथा पशुपालक इन बीमारियों से होने वाले नुकसान और टीकाकरण के लाभों से परिचित हों।
- **क्षतिपूर्ति:** दोषपूर्ण टीकों के कारण टीकाकरण के बाद अपने पशुओं को खोने वाले किसानों को क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। वर्तमान समय में इस सन्दर्भ में मुआवजे का प्रावधान नहीं है। इसके लिए पशुपालन विभाग को जमीनी स्तर पर वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने चाहिए।

इसके साथ ही टीकों की गुणवत्ता में सुधार, उत्कृष्ट पशुपालकों के सम्मान जैसे कार्यों को करने से पशुपालन की समस्या तथा पशुओ में उत्पन्न रोगों का समाधान किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

- यह ध्यान रखने योग्य है कि पशुधन न सिर्फ आय के साधन हैं बल्कि ये स्वयं में एक जीवित प्राणी हैं, अतः इनकी समस्याओं का निदान आवश्यक है। इस सन्दर्भ में सरकार, पशुपालकों तथा नागरिक समाज को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा जिससे पशु अधिकारों को बढ़ावा देकर 'बायोक्रेसी' को महत्त्व दिया जा सके तथा कृषि के सहयोगी गतिविधि के रूप में पशुपालन का महत्त्व स्थापित हो सके।

भारत में जल संकट तथा मिशन अमृत सरोवर

सन्दर्भः

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को यह निर्देश दिए गए हैं कि ये मंत्रालय अपनी बुनियादी संरचनाओं के लिए अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत देश के सभी जिलों में तालाबों से खुदाई की गई गाद का उपयोग करें।

परिचयः

वर्तमान विश्व में 'विकास तथा पर्यावरण संरक्षण' को एक साथ लाने की कवायद की जा रही है। इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा आरम्भ किया गया अमृत सरोवर मिशन एक बेहतर कदम सिद्ध हो सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव में आरम्भ किया गया यह मिशन न सिर्फ जल संरक्षण को बढ़ावा देगा बल्कि बुनियादी संरचनाओं में सहायक होकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

भारत में जल संकटः

- हाल के वर्षों में बढ़ते औद्योगिक विकास, गिरते भू-जल स्तर, आर०ओ० के बढ़ते घरेलू प्रचलन, तेजी से बढ़ते बोतल बंद पानी के उद्योग से जल संकट अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच चुका है। अधिकांश भू-जल गुणात्मक रूप से पीने की स्थिति में नहीं है।
- कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में जल की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता में 75% गिरावट आई है। 2021 में यह उपलब्धता 1486 घनमीटर रह गई है। यह स्थिति देश को अत्यधिक जल असुरक्षा वाले देशों की श्रेणी में शामिल करती है।
- फाल्कनमार्क वाटर स्ट्रेस इंडेक्स के अनुसार वर्तमान में 76% लोग जल अभाव का सामना कर रहे हैं।

भारत की बढ़ती जल असुरक्षा के लिए उत्तरदायी कारकः

भू-जल स्तर में गिरावटः

- 2007 से 2017 के मध्य भारत के भू-जल स्तर में 61% की गिरावट हुई है। इसका मुख्य कारण सिंचाई हेतु प्रयुक्त जल का पुनः भण्डारण न होने, कृषि हेतु नहर सुविधा में कमी, कृषि हेतु भूजल का अत्यधिक दोहन इत्यादि हैं। सरकारी अध्ययन के अनुसार देश का भू-जल स्तर 0.3 मीटर सालाना की दर से गिरता जा रहा है।

सतही जल का प्रदूषणः

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में 351 नदियां प्रदूषित हैं। इसके साथ ही भारत का 70% जल उपयोग के लिए ठीक नहीं है। इस स्थिति हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी कारक नदियों के जल में अनुपचारित अथवा अंशतः उपचारित औद्योगिक अपशिष्ट के छोड़ने से है। इसके अतिरिक्त कृषि अपवाह तथा सीवेज की समस्या भी सतही जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। यह सत्य है कि औद्योगिक विकास के लिये जल की उपलब्धता आवश्यक है, परन्तु जलसंकट सतत विकास के आयामों के विरुद्ध है।

जल निकायों का लुप्तीकरणः

- वर्तमान समय में भारत के जलीय निकाय जैसे-तालाब, झीलें, आर्द्रभूमियां तेजी से लुप्त हो रही हैं। तीव्र शहरीकरण, अनियोजित विकास, गाद, लवणता तथा अवैध बालू खनन जैसी घटनाओं के कारण भारत के जल निकायों का लगभग 2% भूमि उपयोग में आ चुका है।

अन्य कारकः

- औद्योगीकरण एवं उससे उत्पन्न हुए प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन से वर्षा में लगभग 6% की गिरावट हुई है जिससे जल संकट बहुत ही अधिक बढ़ा है जो व्यापक सामाजिक-आर्थिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है।

जल संकट के प्रभावः

सामाजिक प्रभावः

- जल की कमी से सफाई एवं स्वच्छता में बाधा।
- महिलाओं तथा बच्चों पर अधिक बोझ।
- अशुद्ध जल से शरणार्थी, गरीब, प्रवासी जनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव।
- अंतर्राज्यीय तथा ट्रांस - बॉउंड्री जल निकायों पर विवाद।

आर्थिक प्रभावः

- 2016 में विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार 2050 तक कृषि, मत्स्यियन जैसे क्षेत्रों में भारत को लगभग जीडीपी के 6% तक की हानि हो सकती है।
- नीति आयोग द्वारा भी यह उल्लेख किया

गया है कि देश के कई औद्योगिक केन्द्रों वाले शहरों में अगले वर्ष तक जल संकट उत्पन्न हो सकता है जो आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा।

पर्यावरणीय प्रभाव:

- लवणीय जल की मात्रा में वृद्धि।
- भूमिगत जल की गुणवत्ता में गिरावट।
- समुद्री तापन में में वृद्धि के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के कारकों में वृद्धि।

अमृत सरोवर मिशन के द्वारा जल संकट से निवारण:

अमृत सरोवर मिशन:

अमृत सरोवर मिशन का आरम्भ 24 अप्रैल, 2022 को जल संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था।

लक्ष्य:

यह मिशन आजादी के अमृत महोत्सव में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों के विकास तथा कायाकल्प हेतु, एक एकड़ या उससे अधिक आकार के 50,000 जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखता है।

मिशन की उपलब्धियां:

अब तक राज्यों द्वारा अमृत सरोवरों के निर्माण के लिये 12,000 से अधिक स्थलों को अंतिम रूप दिया जा चुका है जिनमें से 4,856 अमृत सरोवरों पर कार्य भी आरम्भ हो चुका है।

मिशन की गतिविधियां तथा जल संकट पर प्रभाव:

- अमृत सरोवर मिशन के द्वारा एक एकड़ या उससे अधिक आकार के 50,000 जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इससे न सिर्फ जलाशयों का निर्माण होगा बल्कि जलीय निकाय की संख्या में भी वृद्धि होगी। जल निकायों की संख्या में वृद्धि से जल संकट को कम करने में सहायता मिलेगी।
- इस मिशन के अंतर्गत मनरेगा, 15वां वित्त आयोग अनुदान, पीएमकेएसवाई तथा उप योजनाओं जैसे-वाटरशेड विकास घटक, हर खेत को पानी का प्रयोग किया जायेगा जिससे कृषि अपवाह में कमी, भूमिगत जल की सिंचाई हेतु कमी तथा उचित सिंचाई व्यवहार में वृद्धि होगी जो भूमिगत जल संरक्षण तथा सतही जल के प्रदूषण को कम करने में सहायक होगा।
- इस मिशन के अंतर्गत तकनीकी भागीदार भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) हैं। इससे इस मिशन के प्रशासनिक गुणवत्ता तथा तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी जो वैज्ञानिक विधि से जल संरक्षण के कार्य में सहायक होगा।
- इस मिशन के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास तथा कायाकल्प किया जायेगा ताकि जल संकट के क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सके।
- इस मिशन के अंतर्गत सार्वजनिक तथा गैर-सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा जिससे वित्तीयन का कार्य सरलता से हो सकेगा। इसके साथ ही यह प्रावधान है कि इस मिशन के अंतर्गत बनने वाले निकायों पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण होगा। इस प्रावधान से इन जलीय निकायों के जबरन अतिक्रमण का संकट भी कम हो जायेगा।

जल संकट से निदान हेतु सरकार द्वारा की गई अन्य पहल:

- **जल शक्ति अभियान:** यह जल संरक्षण हेतु आरम्भ किया गया महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत जल संकट से ग्रस्त जिलों और ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **कैच द रेन अभियान:** यह अभियान वर्षा जल का संचयन तथा संरक्षण के उद्देश्य को पूर्ण करता है।
- **जल जीवन मिशन:** इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- **राष्ट्रीय जल मिशन:** यह एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर केन्द्रित है जिसका उद्देश्य राज्यों के भीतर और अलग-अलग राज्यों में जल संरक्षण, तथा जल के समान वितरण को सुनिश्चित करने से है।
- **अटल भू-जल योजना:** यह योजना देश के सात राज्यों में जल संकट वाले निर्धारित क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसके तहत संधारणीय भू-जल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और मांग पक्ष संबंधी पहलुओं को महत्त्व दिया गया है।
- **समग्र जल प्रबंधन सूचकांक:** नीति आयोग द्वारा विकसित इस सूचकांक का उद्देश्य भारतीय राज्यों में प्रभावी जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मिशन अमृत सरोवर भारत में जल संकट को कम करने तथा जल संरक्षण को बढ़ाने में मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है। यह सतत आर्थिक विकास तथा 'पर्यावरण संरक्षण व आर्थिक विकास' में संतुलन बनाने वाला प्रयास है। हालांकि जल संरक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है लोगों के व्यवहार में परिवर्तन। अत: सरकार को अमृत सरोवर मिशन को स्वच्छ भारत मिशन की भांति एक जन-आंदोलन में परिवर्तित करने पर विचार करना चाहिए।

साइबर सुरक्षा के लिए भारत की नई तैयारी और उसके पहलू

सन्दर्भः

वर्तमान समय में इंटरनेट व्यक्ति के दैनिक जीवन का न सिर्फ एक अभिन्न अंग बन गया है बल्कि यह जीवन के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को भी प्रभावित कर रहा है। इस स्थिति में इंटरनेट (साइबर विश्व) कई प्रकार के अपराधों को उत्पन्न कर रहा है। इस सन्दर्भ में भारत के द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए नवीन तैयारियां की जा रही हैं।

परिचयः

इंटरनेट अब न केवल सूचना का स्रोत है बल्कि यह व्यापार, मनोरंजन, उत्पादक व्यवहार इत्यादि का माध्यम बन गया है। वर्तमान समय में यह संवाद तथा वित्तीय लेनदेन तक का माध्यम बन गया है, परन्तु इंटरनेट प्रसार बढ़ने के साथ ही साइबर अपराधों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। भारत साइबर हमलों का सामना करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल है। लॉकडाउन अवधि के दौरान इन घटनाओं में कई गुना वृद्धि हुई है। आईसीटी प्रणालियों की फिशिंग, मैपिंग और स्कैनिंग के मामलों में लगभग 3 गुना वृद्धि देखी गई है। भारत और चीन में जारी गतिरोध के बीच, चीन ने भारतीय साइबर स्पेस को निशाना बनाने की कोशिश की है। ऐसी परिस्थितियों में देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करना आवश्यक हो गया है।

साइबर हमलाः

साइबर अपराध ऐसे गैर-कानूनी कृत्य हैं जिन्हें कम्प्यूटर तथा साइबर स्पेस के प्रयोग से अंजाम दिया जाता है। फिशिंग, डाटा थेफ्ट, ट्रोजन हार्स, स्टाकिंग इत्यादि प्रमुख साइबर हमले हैं।

वर्तमान समय में साइबर हमले की तीन प्रमुख श्रेणियाँ हैं:

- वित्तीय साइबर हमला।
- सरकारों के विरुद्ध साइबर हमला।
- व्यक्ति विशेष के विरुद्ध साइबर हमला।

भारत में कुछ प्रमुख साइबर हमलेः

- LAZARUS हैकर समूह के द्वारा भारत, बांग्लादेश और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के वित्तीय संस्थाओं पर निरंतर साइबर हमले किये जा रहे हैं।
- महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी एक वक्तव्य में यह कहा गया है कि चीन के साथ गतिरोध बढ़ने पर भारत के साइबर स्पेस में हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक ऐसा ही चीन और ऑस्ट्रेलिया में व्यापार गतिरोध के उपरान्त ऑस्ट्रेलिया में साइबर हमलों में तेजी देखी गई थी। विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक चीन की हैकर कम्युनिटी में 3 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं।
- चेन्नई के छात्र ने आई.आर.सी.टी.सी की वेबसाइट पर बग (Bug) को चिन्हित कर देश की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) को सूचित कर लाखों रेल यात्रियों के डेटा की सुरक्षा की।
- 2019-20 के दौरान भारत में साइबर हमलों के कारण लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
- 2020 में बिग-बास्केट के लगभग 2 करोड़ उपभोक्ताओं का डाटा लीक हुआ था।

साइबर सुरक्षा क्या है?

साइबर सुरक्षा आपके इंटरनेट और नेटवर्क आधारित डिजिटल उपकरणों और अनधिकृत पहुंच तथा सूचना की सुरक्षा से संबंधित है।

साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों?

- साइबर सुरक्षा अब व्यक्तियों और परिवारों के साथ-साथ संगठनों सरकारों, शैक्षिक संस्थानों एवं हमारे व्यवसाय का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह हमारी वित्तीय लेनदेन के साथ सार्वजनिक जीवन तथा निजता को प्रभावित कर रहा है। डिजिटल भारत मिशन, कोरोना जन्य लॉकडाउन, ऑनलाइन बिजनेस इत्यादि के कारण अब निरंतर डिजिटल अधिकारों की बात की जा रही है। इस स्थिति में साइबर स्पेस का सुरक्षित रहना आवश्यक है।
- संकाय (Faculty), छात्र, कर्मचारियों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए इंटरनेट बहुत महत्त्वपूर्ण व लाभप्रद है। हालांकि ऑनलाइन अधिगम के साथ यह ऑनलाइन जोखिमों की चिंताओं को भी जन्म देता है।
- इसलिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को यह समझने की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी और आइडेंटिटी थेफ्ट से स्वयं को को कैसे बचाया जाए? ऑनलाइन व्यवहार और सिस्टम सुरक्षा के बारे में उपयुक्त जानकारी के साथ सुभेद्यता में कमी आती है तथा ऑनलाइन वातावरण सुरक्षित होता है।
- वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासन, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को देखते हुए साइबर स्पेस की सुरक्षा अनिवार्य हो गई है।

भारत में साइबर सुरक्षा हेतु किये गए उपायः

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम- 2000

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की

धाराएँ 43, 43ए, 66, 66बी, 66सी, 66डी, 66ई, 66एफ, 67, 67ए, 67बी, 70, 72, 72ए और 74 हैकिंग एवं साइबर अपराधों से संबंधित हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर में उपलब्ध रिकाड्र्स से छेड़छाड़, संचार यंत्रों की चोरी और दुरुपयोग, अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसार इत्यादि अपराधों के लिए दंड के प्रावधान का वर्णन किया गया है। इसके लिए आर्थिक दंड तथा कैद का प्रावधान किया गया है।

साइबर सुरक्षा नीति -2013:

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लाई गई एक नीतिगत रूपरेखा है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों से सुरक्षा करना है।
- यह साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध है। साइबर सुरक्षा नीति का उद्देश्य देश में एक सुरक्षित साइबर पर्यावरण बनाने के लिए आईटी सिस्टम में पर्याप्त सुदृढ़ता, साइबरस्पेस में लेन-देन करना तथा इस प्रकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में आईटी को स्वीकारना है।

भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In):

भारतीय प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 19 जनवरी 2004 में गठित यह एक सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में कार्यवाही करने के साथ ही देश भर में आई.टी. सुरक्षा के प्रभावी कार्यों को बढ़ावा देना है।

साइबर सुरक्षा के नए आयाम:

- पहले इंटरनेट की सुरक्षा का उल्लंघन अराजक तत्वों द्वारा किया जाता था परंतु अब राष्ट्र-राज्यों द्वारा अन्य देशों की साइबर सुरक्षा का उल्लंघन किया जा रहा है जिसे साइबर वार के नाम से जाना जाता है।
- पहले साइबर हमला मुख्य रूप से वित्तीय लेनदेन तक सीमित था परंतु वर्तमान समय में यह पर्सनल तथा नॉन-पर्सनल डाटा तक भी पहुंच चुका है। साइबर हमलों के क्षेत्र में विस्तार से व्यक्ति की निजता भी प्रभावित हो रही है जो भारत में अनुच्छेद-21 के अंतर्गत मूल अधिकार है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things-IoT) की अतिवैज्ञानिक तथा समावेशी प्रकृति के कारण साइबर स्पेस एक जटिल डोमेन में परिवर्तित हो गया है। इन तकनीकों के आने से साइबर सुरक्षा के लिए नवीन रणनीतियों को बनाने की आवश्यकता है।
- लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम, क्रिप्टोकरेंसी, ऑनलाइन लर्निंग तथा व्यापार के कारण भारी मात्रा में डाटा साइबर स्पेस में पहुंच चुका है। लॉकडाउन अवधि के दौरान इंटरनेट ट्रैफिक में लगभग 56% वृद्धि हुई है, अत: इन डाटा का स्थानीयकरण करना भी आवश्यक है।
- यही कारण है कि साइबरस्पेस के प्रति तेजी से बढ़ते जोखिमों, धमकियों, साइबर अपराधों में धोखाधड़ी तथा साइबर युद्ध जैसे परिदृश्य में साइबर सुरक्षा का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया है एवं 2013 की साइबर सुरक्षा नीति मौजूदा परिस्थितियों में कारगर साबित नहीं हो रही है। वर्तमान समय में भारत संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में 10वें स्थान पर आता है। कंज्यूमर टेक रिव्यू फर्म कंपेरिटेक (Comparitech) के अनुसार भारत दुनिया के सबसे कम साइबर-सुरक्षित देशों में से 15वें स्थान पर है। इस स्थिति में भारत को नवीन सुरक्षा आयामों को प्राप्त करने के लिए नवीन कदमों को उठाने की आवश्यकता है।

साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए क्या किया जा सकता है?

- सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि संसद पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को पारित करें तथा नॉन-पर्सनल डाटा बिल पर भी एक सुदृढ़ कानून की रूपरेखा तैयार करें।
- वर्तमान साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय केंद्र 'नेशनल क्रिटिकल इनफॉरमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर' जैसे संस्थानों में तकनीकी कुशल, मानव संसाधन तथा त्वरित साइबर सुरक्षा रिस्पांस सिस्टम को लाए जाने की आवश्यकता है।
- तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों में सुधार की आवश्यकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अनुप्रयोगों को पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करना चाहिए।
- इसके साथ ही साथ व्यापारिक संगठनों तथा आम जनमानस को जागरूक करने की आवश्यकता है। जागरूकता के लिए सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा दिवस मनाने की पहल आरंभ की गई है जो एक बेहतर कदम है। साथ ही इसे स्कूलों व कालेजों में पढ़ाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

वर्तमान समय में डाटा संपत्ति में परिवर्तित हो चुका है एवं देश की तकनीकी तथा आर्थिक संप्रभुता के लिए यह आवश्यक है कि देश के साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नये-नये वैज्ञानिक अनुप्रयोग सामने आ रहे हैं। इन अनुप्रयोगों से न सिर्फ लाभ होता है बल्कि साइबर सुरक्षा की चिंताएं भी सामने आती हैं। अत: सरकार, निजी क्षेत्र तथा तकनीकी रूप से सक्षम संगठनों एवं व्यक्तियों को एक साथ इस संकट के लिए सदैव तैयार रहना होगा।

1 बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए योजना

चर्चा में क्यों?

औषधि विभाग ने 'बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने' हेतु तीन राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह देश में बल्क ड्रग विनिर्माण को सहायता देने के लिए शुरू की गई एक पहल है। आवश्यक या सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) को बल्क ड्रग्स कहा जाता है। ये दवा के तत्व होते हैं जो चिकित्सीय प्रभाव या इच्छित औषधीय गतिविधि का प्रमुख स्रोत हैं।

योजना के बारे में:

- इस योजना को वर्ष 2020 में 3,000 करोड़ रुपये के वित्तीय राशि के साथ शुरू किया गया था जिसको 2025 तक पूर्ण करना है। प्रत्येक बल्क ड्रग पार्क के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों को अधिकतम 1,000 करोड़ रु. की धनराशि या कुल प्रोजेक्ट का 70% इसमें जो भी कम हो (वहीं उत्तर-पूर्वी राज्यों और पहाड़ी राज्यों को 90%) की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

इसका उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करके, बल्क ड्रग के विनिर्माण की लागत को कम करना है।
- इसके माध्यम से घरेलू थोक दवा उद्योग को प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना है।
- उच्च क्षमता वाले औषधि उद्योग के विकास हेतु केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत वर्ष 2008 में औषधि विभाग का गठन किया गया था।

नए प्रस्तावित बल्क ड्रग्स पार्क:

इस योजना के तहत 13 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके लिए विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन में नीति आयोग के सीईओ के अधीन एक सलाहकार समिति की सहायता ली गई थी। इन प्रस्तावों के आधार पर तीन राज्यों में बल्क ड्रग्स पार्कों का निर्माण किया जाएगा;

- हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के तहसील हरोली में 1402.44 एकड़ भूमि पर।
- गुजरात के भरूच जिले के जम्बूसर तहसील में 2015.02 एकड़ जमीन पर।
- आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के थोंडागी मंडल में 2000.45 एकड़ भूमि पर।

इन तीनों राज्यों को योजना के तहत अगले 90 दिनों में अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने, उसका मूल्यांकन करने और अंतिम अनुमोदन के लिए प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

भारत में औषधि उद्योग:

भारतीय औषधि उद्योग आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,75,040 करोड़ रुपये के दवाओं का निर्यात किया है। भारत जोकि बल्क ड्रग्स के निर्माण में एक प्रमुख केंद्र है, ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 33,320 करोड़ रुपये मूल्य की बल्क ड्रग्स/ड्रग इंटरमीडिएट्स का निर्यात किया है। हालांकि, भारत में कई देशों से दवाओं के विनिर्माण के लिए विभिन्न बल्क ड्रग्स/एपीआई का आयात भी किया जाता है। देश में बल्क ड्रग/एपीआई का अधिकांश आयात आर्थिक कारणों से किया जाता है क्योंकि उनकी लागत कम होती है।

योजना का लाभ:

- इससे देश के उत्पादन लागत में कमी आएगी और बल्क ड्रग के लिए अन्य देशों पर निर्भरता भी कम होगी।
- बल्क ड्रग के निर्माण में आत्म-निर्भर होने से नागरिकों हेतु किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुनिश्चित करने और दवाओं की निरंतर आपूर्ति बनाये रखने में आसानी होगी।
- यह योजना उद्योग को सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अभिनव तरीकों के जरिए, पर्यावरण के मानकों को पूरा करने में भी सहायता करेगी।
- यह योजना सहकारी संघवाद की भावना को दिखाती है जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारें स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए बल्क ड्रग पार्क विकसित करने के लिए प्रयास करेंगे।

2 नौसेना का नया ध्वज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा एक नए डिजाइन वाले नौसेना ध्वज को स्वीकार किया गया है। यह भारतीय नौसेना के इंडियन व्हाइट एनसाइन या निशान के रूप में भी जाना जाता है जिसका उपयोग भारतीय नौसैनिक जहाजों, तटीय प्रतिष्ठानों और नौसैनिक स्टेशनों पर पहचान के रूप में किया जाता है।

नए नौसेना निशान के बारे में:

भारतीय नौसेना का नया सफेद निशान नौसेना की राष्ट्रव्यापी उपस्थिति का प्रतीक है। अब उसमें दो प्रमुख घटक जुड़ गये है जिसमें ऊपर बाईं तरफ राष्ट्रीय ध्वज बीच में गहरा नीला स्वर्ण अष्टभुजाकार बना है। अष्टभुजाकार में दो दोहरे स्वर्ण अष्टकोणीय छोर बने हैं जिसमें स्वर्ण राष्ट्रीय चिह्न (अशोक का सिंहचतुर्मुख स्तम्भशीर्ष) स्थित है। वहां सुनहरे अक्षरों में भारतीय नौसेना का ध्येय-वाक्य 'शं नो वरुण:' लिखा है। डिजाइन के तहत अष्टभुजाकार के भीतर भारतीय नौसेना की कलगी, लंगर बना था जो औपनिवेशिक अतीत से जुड़ा था। इसके स्थान पर अब स्पष्ट लंगर बना है जो भारतीय नौसेना की दृढ़ता का प्रतीक है। न्यू नेवी एनसाइन ने सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर के आकार के रूप में एक अष्टकोण को स्वीकार किया गया है।

भारतीय नौसेना के ध्वज का इतिहास:

औपनिवेशिक युग का निशान: भारतीय नौसेना के निशान की उत्पत्ति औपनिवेशिक काल में हुई थी। 1934 में, नौसेना सेवा का नाम बदलकर रॉयल इंडियन नेवी (RIN) कर दिया गया था।

स्वतंत्र भारत में निशान में बदलाव:

- **1950 में बदलाव:** भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणराज्य बना। उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी में से उपसर्ग 'रॉयल' हटाकर इसे इंडियन नेवी के रूप में फिर से नाम दिया गया।
- **2001 में बदलाव:** भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के झंडों के साथ समानता बनाए रखने की आवश्यकता और सादगी के उद्देश्य से 2001 में नौसेना के ध्वज में सीमित परिवर्तन किया गया। 15 अगस्त, 2001 को भारत सरकार ने औपनिवेशिक अतीत के बोझ से छुटकारा पाने के क्रम में ध्वज में बदलाव किया और जॉर्ज क्रॉस को आईएन की शिखा (Naval Crest) के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जबकि तिरंगा अपने मूल स्थान पर बना रहा।

- **2004 में बदलाव:** 2004 में सेंट जॉर्ज क्रॉस को अशोक के प्रतीक के साथ वापस लाया गया था। 2001 में जोड़ा गया नौसेना शिखा तब हटा दिया गया था।
- **2014 में बदलाव:** 2014 में एक और बदलाव तब किया गया जब देवनागरी लिपि में अशोक चिन्ह के नीचे ध्वज पर 'सत्यमेव जयते' शब्द शामिल किया गया।

सेंट जॉर्ज क्रॉस:

- एक सफेद पृष्ठभूमि पर रेड क्रॉस को सेंट जॉर्ज क्रॉस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह नाम एक ईसाई योद्धा के नाम पर रखा गया है जिसे ईसाईयों के तृतीय धर्मयुद्ध (Third Crusade) में शामिल एक वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है।
- इसे इंग्लैंड और लंदन शहर द्वारा वर्ष 1190 में भूमध्य सागर में प्रवेश करने वाले अंग्रेजी जहाजों की पहचान करने के लिए स्वीकार किया गया था।
- अधिकांश राष्ट्रमंडल देशों ने अपनी स्वतंत्रता के समय रेड जॉर्ज क्रॉस को बरकरार रखा है। हालाँकि कई देशों जैसे-ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने नौसैनिक निशान से रेड जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया है।

3 राजपथ का नाम बदलकर कर्त्तव्य पथ किया गया

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राजपथ का नाम बदलकर कर्त्तव्य पथ कर दिया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए जो विविधता में एकता को दर्शाता है।

कर्त्तव्य पथ के बारे में:

ग्रैंड कैनोपी के नीचे नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के पूरे क्षेत्र को कर्त्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा। एनडीएमसी प्रस्ताव के अनुसार, कर्त्तव्य पथ में पूर्ववर्ती राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन शामिल हैं।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति:

जेट-ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति को 280 मीट्रिक टन वजन वाले ग्रेनाइट के एक अखंड ब्लॉक पर बनाया गया है। नेताजी की यह मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित की गई है, जहां पीएम मोदी द्वारा पराक्रम दिवस (23 जनवरी) पर होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया गया था। यह 28 फीट ऊंची विशाल नेताजी की मूर्ति भारत में सबसे ऊंची, अखंड, हस्तनिर्मित मूर्तियों में से एक है। मूर्ति के निर्माण में अरुण योगीराज की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।

कर्त्तव्य पथ के उद्घाटन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम:

एक भारत-श्रेष्ठ भारत और विविधता में एकता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए कर्त्तव्य पथ पर देश के सभी हिस्सों से आए 500 कलाकारों द्वारा एक सांस्कृतिक उत्सव का प्रदर्शन किया गया।

नेताजी की प्रतिमा के अनावरण के लिए पारंपरिक मणिपुरी शंख वाद्यम और केरल के पारंपरिक पंच वाद्यम की प्रस्तुति हुई। पंच वाद्यम मुख्य रूप से केरल में मंदिर नृत्य है जिसमें पांच प्रकार के वाद्ययंत्र शामिल होते हैं। पंचवद्यम प्रायः मंदिर में उत्सवों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति वर्तमान एरानाकुलम जिले में हुई थी।

- **संभलपुरी:** पश्चिमी ओड़िशा का संभलपुर जिला अपने सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। इस नृत्य को दशहरा के दौरान बिंझल, सौरा और मिर्धा जनजातियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
- **पंथी:** पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है जिसमें कुछ नर्तक, दूसरी पंक्ति के नर्तकियों के कंधों पर खड़े होते हैं। सफेद धोती पहने ये लोग वाद्ययंत्र भी बजाते हैं और अक्सर गुरु घासीदास के सम्मान में नृत्य करते हैं।
- **ढोल ताशा:** ढोल-ताशा महाराष्ट्र के ड्रम हैं जिन्हें बजाने वाले कलाकार 'पाठक' नाम से जाने जाते हैं। ये गणेश चतुर्थी के समय भी बजाये जाते हैं।
- **कालबेलिया:** यह परंपरागत रूप से सपेरों के एक आदिवासी समुदाय कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। 2010 में कालबेलिया गीतों और नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था।
- **करगम:** करगम तमिलनाडु का एक नृत्य है जो सिर पर पानी के बर्तन को संतुलित करते हुए किया जाता है। यह नृत्य ग्रामीणों द्वारा वर्षा देवी मारी अम्मन और नदी देवी गंगई अम्मा की स्तुति में किया जाता है।

4 गोद लेने संबंधित नए नियम 1 सितम्बर से लागू

चर्चा में क्यों?

गोद लेने संबंधित नए नियम, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 को 1 सितम्बर, 2022 से लागू किया गया। नए नियमों को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत लाया गया है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रावधान:

- जिला मजिस्ट्रेटों और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना।
- डीएम द्वारा बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण करना।
- डीएम द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड आदि के कामकाज का मूल्यांकन करना।

संशोधित नियमों पर चिंता:

- पिछले कई महीनों से अदालतों में पहले से चल रहे मामलों को स्थानांतरित करना होगा और प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करना होगा जिससे गोद लेने के आदेश में देरी होने की संभावना है।
- इस तरह के आदेश में देरी का मतलब यह हो सकता है कि बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं मिल सकेगा क्योंकि माता-पिता के पास अभी तक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है।
- माता-पिता और वकीलों का दावा है

कि न तो जज और न ही डीएम को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव के बारे में पता है, जिससे और देरी हो रही है।

भारत में गोद लेने की प्रक्रिया क्या है?

- भारत में दत्तक ग्रहण, दो कानूनों पहला हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 (HAMA) और दूसरा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 द्वारा शासित हैं। दोनों कानूनों में दत्तक अभिभावकों के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड हैं।

हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 (HAMA):

- हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम के अनुसार, अपरिवर्तनीय दत्तक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक 'दत्तका होम' समारोह या एक गोद लेने का विलेख या अदालत का आदेश पर्याप्त होता है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015:

- माता-पिता को केन्द्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA) के पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है जिसके बाद एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी एक गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करती है। यदि इसके बाद उम्मीदवार को गोद लेने के लिए योग्य पाया जाता है, तब वह बच्चे को गोद ले सकता है।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA):

- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। इसका प्रमुख कार्य देश और अंतर-देश गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी और विनियमन करना है। हेग कन्वेंशन 1993 के प्रावधानों के अनुसार, अंतर-देश गोद लेने से निपटने के लिए CARA को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। 2003 में भारत द्वारा हेग कन्वेंशन को अनुमोदित किया गया था।

कौन गोद ले सकता है?

- भावी दत्तक माता-पिता शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर, आर्थिक रूप से सक्षम हों और उनकी कोई जीवन समाप्ति वाली चिकित्सा स्थिति न हो।
- कोई भी भावी दत्तक माता-पिता, चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो और उसका जैविक पुत्र या पुत्री है या नहीं, निम्नलिखित के अधीन बच्चे को गोद ले सकता है:

1. विवाहित जोड़े के मामले में, गोद लेने के लिए दोनों पति-पत्नी की सहमति आवश्यक होगी।
2. एक अकेली महिला किसी बच्चे (बालक या बालिका) को गोद ले सकती है।
3. एक अकेला पुरुष बालिका को गोद लेने के लिए पात्र नहीं होगा।

दंपत्ति को तब तक कोई बच्चा गोद नहीं दिया जाएगा जब तक कि उनका कम से कम दो साल का स्थिर वैवाहिक संबंध न हो।

हेग कन्वेंशन क्या है?

- हेग कन्वेंशन, 1993 बच्चों और उनके परिवारों को विदेशों में अवैध एवं अनियमित रूप से तथा समय से पहले या गलत तरीके से गोद लेने के जोखिमों से बचाता है।

निष्कर्ष:

अन्य देशों की तरह भारत में भी वैकल्पिक, सक्षम और लिंग-न्यायपूर्ण विशेष दत्तक ग्रहण कानून होना चाहिए। इसके अलावा, कदाचार की जांच करने और गोद लेने से संबंधित नियमों में सुधार करना, समय की मांग है।

5 राष्ट्रपति ने शुरू किया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान

माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को फिर से जीवंत करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है। मार्च 2018 में दिल्ली टीबी शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसडीजी लक्ष्य 2030 से पांच साल पहले देश में टीबी को समाप्त करने का आह्वान किया था।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने के लिए की गई है ताकि टीबी के उपचार में लोगों का समर्थन किया जा सके और टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी लाई जा सके। राष्ट्रपति मुर्मू ने नि-क्षय 2.0 पहल की भी शुरुआत की, जो एक पोर्टल है जो दाताओं को टीबी के उपचार से गुजर रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तीन आयामी समर्थन में पोषण, अतिरिक्त निदान और व्यावसायिक सहायता शामिल है। **दानकर्ता जिन्हें नि-क्षय मित्र कहा जाता है, निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों से लेकर कॉरपोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों तक के हितधारकों की एक विस्तृत शृंखला हो सकती है।**

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य एक सामाजिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करना है जो 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने के

महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जन आंदोलन में सभी पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान रोगी केंद्रित स्वास्थ्य प्रणाली की ओर सामुदायिक समर्थन हासिल करने की दिशा में एक कदम है।

नि-क्षय पोर्टल:
यह राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत टीबी नियंत्रण के लिए वेब सक्षम रोगी प्रबंधन प्रणाली है। यह केंद्रीय टीबी प्रभाग (सीटीडी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और भारत के विश्व स्वास्थ्य संगठन के देश कार्यालय के सहयोग से विकसित और अनुरक्षित है।

इंड टीबी स्ट्रेटेजी:
डब्ल्यूएचओ ने इंड टीबी स्ट्रेटेजी विकसित की, जिसे 2014 में 67 विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। रणनीति टीबी से मुक्त दुनिया की कल्पना करती है, जिसमें टीबी की बीमारी के कारण शून्य मृत्यु, पीड़ा और बीमारी की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, महत्त्वाकांक्षी रूप से 2035 तक 'वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त' करने का प्रस्ताव करती है। रणनीति में टीबी से पीड़ित रोगियों में 90% की कमी और 2035 तक टीबी से होने वाली मौतों में 95% की कमी का लक्ष्य है।

सतत लक्ष्य और टीबी:
लक्ष्य 3.3: 2030 तक, एड्स, टीबी, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारियों को समाप्त करना और हेपेटाइटिस, जल जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों की समाप्ति शामिल है।

क्षय रोग (टीबी):
1. क्षय रोग (टीबी) माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है।
2. टीबी आमतौर पर फेफड़ों (फुफ्फुसीय टीबी) को प्रभावित करता है, लेकिन अन्य भागों (अतिरिक्त फुफ्फुसीय टीबी) को भी प्रभावित कर सकता है।
3. टीबी हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जब टीबी संक्रमण से संक्रमित लोग खांसते, छींकते हैं या हवा के माध्यम से श्वसन तरल पदार्थ संचारित करते हैं।
4. टीबी से जुड़ा सबसे आम जोखिम कारक एचआईवी और अन्य स्थितियां हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को खराब करती हैं।

निष्कर्ष:
ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत में 2020 के दौरान प्रति 1 लाख जनसंख्या पर टी.बी. के सभी रूपों के 188 मामले दर्ज हुए। बच्चों में टीबी की बीमारी एक चौंका देने वाली समस्या बनी हुई है, वहीं एमडीआर टीबी और एक्स-डीआर टीबी भी चिंता का विषय है, जिसका जल्द समाधान होना चाहिए।

6 भारत के 16वें महान्यायवादी होंगे मुकुल रोहतगी

- भारतीय संविधान के तहत अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पद है और इसी पद पर अब वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी एक बार फिर से आसीन होंगे। वह भारत के नए और 16 वें अटॉर्नी जनरल बनने जा रहे हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल हैं जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वेणुगोपाल को वर्ष 2017 में भारत का 15वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया था। उन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। मुकुल रोहतगी इससे पहले जून, 2014 से जून 2017 तक भारत के महान्यायवादी के पद पर रह चुके हैं।
- एक सीनियर एडवोकेट के रूप में हाल के समय में मुकुल रोहतगी ने लखीमपुर खीरी केस और कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग केस लड़ा था।

अटॉर्नी जनरल के बारे में:
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। महान्यायवादी की योग्यता भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश के बराबर होगी। भारत का महान्यायवादी ही भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है जो भारत सरकार को मुख्य कानूनी सलाह भी देता है। इस लिहाज से देश में कानून का शासन स्थापित करने में उसकी अहम भूमिका होती है।
- भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त तक अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को किसी भी समय उसके पद से हटाया जा सकता है जिसके लिए कोई निश्चित आधार निर्धारित नहीं है।

महान्यायवादी के अधिकार और शक्तियां:
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 88 कहता है कि वोट देने के अधिकार के बिना महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की

कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है।

- भारत का महान्यायवादी उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार होता है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं।
- एटॉर्नी जनरल का पद सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है, अत: उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता है।

हालाँकि उसे भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह या संक्षिप्त जानकारी देने का अधिकार नहीं है।

भारत के सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General of India) और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (Additional Solicitor General) आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में महान्यायवादी की सहायता करते हैं।

7 के.के. शैलजा के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के नामांकन में विवाद

चर्चा में क्यों?

- केरल की पूर्व स्वास्थ्यमंत्री के. के. शैलजा ने प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिससे विवाद छिड़ गया। उन्होंने कहा कि उस कार्य के लिए पुरस्कार पर उनके नाम पर विचार किया गया था जो सामूहिक प्रयास का हिस्सा था और उनकी व्यक्तिगत क्षमता में इसे प्राप्त करना सही नहीं है।
- उनको यह पुरस्कार कोरोना काल के दौरान उनके अहम् योगदान के लिए दिया जा रहा था।
- इस वर्ष का पुरस्कार चार व्यक्तियों को मिला है जिसमें कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, जापानी नेत्र विशेषज्ञ तदाशी हटोरी, युवा फ्रांसीसी पर्यावरणविद गैरी बेनचेघी और बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट जे मैड्रिड शामिल हैं।

रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में:

- 1957 ई. में फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की मृत्यु के बाद रॉकफेलर ब्रदर्स फंड (आरबीएफ) ने फिलीपींस सरकार के साथ समझौता किया जिसमें राष्ट्रपति के सम्मान में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाने की बात हुई थी।
- बाद में फंड ने एशिया के सबसे बड़े सम्मान का प्रबंधन करने के लिए एक गैर-लाभकारी संगठन रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन की स्थापना की थी।
- यह एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है जिसे शुरू में सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ में योगदान के लिए दिया जाता था। उभरते नेतृत्व (Emergent Leadership) की श्रेणी को बाद में जोड़ा गया है।

इन प्रमुख भारतीयों को मिला यह पुरस्कार:

- सी. डी. देशमुख को उनकी संबंधित सरकारों की सेवा में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए दिया गया था।
- समाज सुधारक विनोबा भावे ने 1958 में और मदर टेरेसा ने 1962 में यह पुरस्कार जीता था।
- कमलादेवी चट्टोपाध्याय को 1966 में, फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को 1967 में और लेखिका महाश्वेता देवी को 1997 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2006 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था।
- 2015 में गैर-लाभकारी संस्था गूंज के अंशु गुप्ता और 2016 में मानवाधिकार कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन ने इसे जीता था।
- 2019 में, सम्मान पाने वाले वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रवीश कुमार थे।

निष्कर्ष:

राज्य सेवा के लिए मिलने वाले पुरस्कार पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह पुरस्कार किसी एक व्यक्ति का न होकर बल्कि यह पूरे राज्य के लिए अहम पुरस्कार होता है।

8 LGBTQIA+ समुदाय के रूपांतरण थेरेपी पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने सभी राज्य चिकित्सा परिषदों को LGBTQIA+ समुदाय के रूपांतरण चिकित्सा (conversion therapy) पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देशित करते हुए इसे 'पेशेवर कदाचार' कहा है। NMC ने ऐसा मद्रास उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश के अतर्गत किया है।

LGBTQAI+ का तात्पर्य:

लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, एसेक्सुअल और इंटरसेक्स से है। उन्हें सांस्कृतिक रूप से न तो पुरुष और न ही महिला के रूप में परिभाषित किया जाता है बल्कि इन्हें थर्ड जेंडर कहा जाता है।

रूपांतरण चिकित्सा और इससे जुड़े जोखिम:

- रूपांतरण चिकित्सा का उद्देश्य किसी व्यक्ति के लिंग पहचान में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना है।
- इसमें उन युवाओं के मूल पहचान को बदलने की भी प्रक्रिया होती है जिनकी लिंग पहचान शरीर रचना के साथ मेल नहीं खाती है।
- कन्वर्जन थेरेपी मानसिक स्वास्थ्य के जोखिम की स्थिति को उत्पन्न करती है जिसमें चिंता, तनाव और नशीली दवाओं का उपयोग शामिल होता है जो कभी-कभी आत्महत्या का कारण भी बनता है।
- हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने एजेंसियों को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का अनुपालन करने का आदेश दिया था।
- अदालत ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को एक पेशेवर कदाचार के रूप में 'रूपांतरण चिकित्सा' को सूचीबद्ध करके आवश्यक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।

LGBTQIA+ की सुरक्षा के लिए अन्य नियम और निर्णय:

- सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2018 में एक ऐतिहासिक फैसले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-377 के एक हिस्से को सर्वसम्मति से समानता और गरिमा के संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन हेतु खारिज कर दिया था।
- पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के लिए अंतर्निहित मूल अधिकार मानते हुए यौन अभिविन्यास (Sexual Orientation) गोपनीयता का एक अनिवार्य गुण माना था।

वैश्विक परिदृश:

- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद-1 घोषित करता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और गरिमापर्ण अधिकारों में समान पैदा हुए हैं।
- दुनिया के 28 देश समान-लिंग विवाह को मान्यता देते हैं और 34 देश अन्य समान-लिंग वाले जोड़ों के लिए मान्यता प्रदान करते हैं।
- फरवरी 2019 में, कनाडा ने अपना नया LGBTQ अंतर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम घोषित किया था ।
- दिसंबर 2020 तक, 81 देशों में यौन अभिविन्यास के आधार पर कार्यस्थल में भेदभाव के खिलाफ कानून बनाए गए हैं।

LGBTQIA+ समुदाय पर निर्णय से संबंधित मौलिक अधिकार:

- अनुच्छेद-14 (कानून के समक्ष समानता),
- अनुच्छेद-15 (वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध),
- अनुच्छेद-21 (जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण)
- संविधान का अनुच्छेद-19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)

आगे की राह:

- LGBTQIA+ समुदाय के लोगों को उनके लिंग भिन्नता के कारण जिसके लिए वह समुदाय खुद जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि जन्मजात है। समाज में समता का अधिकार प्राप्त न होना एक आधुनिक तथा मानवीय मूल्यों से युक्त समाज के लिए कलंक है।

1 पूर्वी आर्थिक मंच, 2022

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी आर्थिक मंच, 2022 के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। व्लादिवोस्तक में आयोजित सातवें पूर्वी आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भारत की एक्ट फार ईस्ट नीति पर महत्त्व दिया, जिसका अनावरण 2019 में किया गया था। यह नीति अब भारत-रूस की 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है।

भारत-रूस सम्बंधों के कुछ महत्त्वपूर्ण स्तम्भः

1. भारत ने एक्ट फार ईस्ट नीति को बहुत अधिक प्राथमिकता दी है। इस नीति के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र पर द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार किया जा रहा है।
2. कनेक्टिविटी भविष्य में हमारे संबंधों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पहले से ही कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोनों देश इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर, चेन्नई-व्लादिवोस्तक मैरीटाइम कॉरिडोर या नॉर्दर्न सी रूट पर एक साथ काम कर रहे हैं।
3. भारत आर्कटिक मुद्दों पर रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है।
4. भारत ने ऊर्जा के साथ-साथ रूस के सुदूर पूर्व में फार्मा और हीरे के क्षेत्रों में भी महत्त्वपूर्ण निवेश किया है।
5. कोकिंग कोल की आपूर्ति के जरिए रूस भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है।
6. खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन की कमी विकासशील देशों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है।
7. यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करता है।

एक्ट फार ईस्ट भारत की नीतिः

- व्लादिवोस्तक में 2019 में 5वें पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) के पूर्ण सत्र में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के लिए 'एक्ट फार ईस्ट' नीति का अनावरण किया और घोषणा की कि भारत रूसी सुदूर पूर्व के विकास के लिए $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करेगा।

पूर्वी आर्थिक मंचः

- पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 2015 में रूसी राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। यह विश्व अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय एकीकरण, नए औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ रूस और अन्य देशों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्षः

पिछले कई दशकों से रूस, भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त रहा है लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि भारत के साथ रूस के संबंधो में कुछ दूरी आई है जिससे पकिस्तान और चीन की रूस से नजदीकियां बढ़ी है। 'एक्ट फार ईस्ट' नीति के जरिये फिर से इस सम्बंध को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

2 भारत-सऊदी अरब संबंधः साझा विकास, सुरक्षा और स्थिरता

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर तीन दिवसीय सऊदी अरब यात्रा पर गये। इस दौरान सऊदी समकक्ष प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक, और सांस्कृतिक सहयोग समिति (पीएसएससी) की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की। पीएसएससी की स्थापना भारत-सऊदी अरब सामरिक भागीदारी परिषद के तहत की गई थी।
- इस दौरान खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के महासचिव डा. नायेफ फलाह मुबारक अल हजरफ से भी मुलाकात हुई। जीसीसी एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1981ई. में हुई थी और इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। दोनों नेताओं ने भारत और जीसीसी के बीच परामर्श तंत्र के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

भारत-सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंधः

- भारत और सऊदी अरब के सदियों पुराने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुआ था। जनवरी 2006 में किंग अब्दुल्ला की भारत यात्रा एक वाटरशेड मोमेंट

था जिसके परिणामस्वरूप 'दिल्ली घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर हुए ताकि द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति दी जा सके। 2010 में हस्ताक्षरित 'रियाद घोषणा' ने द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया।

हाल के उच्चस्तरीय दौरे:

- किंग सलमान ने 2016 की यात्रा पर पीएम मोदी को किंगडम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान (आर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद) से सम्मानित किया। फरवरी 2019 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत यात्रा के दौरान भारत में लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की। पीएम मोदी की अक्टूबर, 2019 यात्रा के दौरान सामरिक भागीदारी परिषद (एसपीसी) समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। भारत-सऊदी अरब संबंधों को बेहतर करने के लिए एसपीसी को एक उच्च स्तरीय परिषद के रूप में स्थापित किया गया था।

आर्थिक सहयोग:

- सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत लगभग 18% कच्चे तेल का आयात सऊदी अरब से करता है। सऊदी अरब वर्तमान में भारत का इराक और रूस के बाद तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का निर्यातक है। वित्त वर्ष 2022 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 29.28 अरब अमेरिकी डॉलर था। इस अवधि के दौरान, सऊदी अरब से भारत का आयात 22.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और सऊदी अरब को निर्यात 6.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

ऊर्जा क्षेत्र में सऊदी अरब का निवेश:

- प्रमुख प्रस्तावित निवेशों में महाराष्ट्र में 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का 'वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट' शामिल है जिसे सऊदी अरामको, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और एक भारतीय संघ (जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन शामिल) द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में, सऊदी कंपनी अलफनार की भारत में 600 MW पवन ऊर्जा परियोजनाओं में एक नियंत्रित हिस्सेदारी है।

सांस्कृतिक संबंध:

- भारत ने फरवरी, 2018 में प्रतिष्ठित सऊदी नेशनल फेस्टिवल ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर- जनादरियाह के 32वें संस्करण में 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के रूप में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल को 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में मना रहा है वहीं भारत-सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के भी 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं।

सऊदी अरब में भारतीय समुदाय:

- लगभग 2.2 मिलियन भारतीय समुदाय सऊदी अरब में रहता है। इनके बेहतर आवागमन के लिए अक्टूबर 2019 में दोनों देशों ने ई-माइग्रेट प्रणाली (भारत की) को ई-थवथीक प्रणाली (सऊदी अरब) के साथ एकीकृत करने के लिए सहमत हुए थे।

3 यूएनडीपी का मानव विकास सूचकांक 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत को 132वां स्थान मिला जोकि 2020 की तुलना में दो स्थान की गिरावट है। यह गिरावट COVID-19 महामारी के बाद वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है जिसके कारण 90% देशों के मानव विकास में गिरावट देखी गयी है।

मानव विकास रिपोर्ट:

नोबेल पुरस्कार विजेता महबूब उल हक ने इस रिपोर्ट को सर्वप्रथम प्रकाशित किया था। मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) 1990 ई. से जारी की जा रही है। इस वर्ष की थीम: 'अनसर्टेन टाइम, अनसेटल्ड लाइव्स: शेपिंग अवर फ्यूचर इन ए वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन' है।

मानव विकास सूचकांक:

एचडीआई एक समग्र सूचकांक है जो निम्न संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत वृद्धि को मापता है:

- जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (सतत विकास लक्ष्य 3)।
- स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (एसडीजी 4.3)।
- स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष (एसडीजी 4.4)।
- सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) प्रति व्यक्ति (2017 पीपीपी+) (एसडीजी 8.5)।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

वैश्विक परिदृश्य:

- 90% देशों ने 2020 से 2021 में अपने

मानव विकास सूचकांक मूल्य में कमी दर्ज की है जो सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का अवरोधक सिद्ध हो सकता है।

- मानव विकास सूचकांक की हालिया गिरावट में सबसे बड़ा योगदान जीवन प्रत्याशा में वैश्विक गिरावट है जो 2019 में 72.8 वर्ष से घटकर 2021 में 71.4 वर्ष हो गया है।

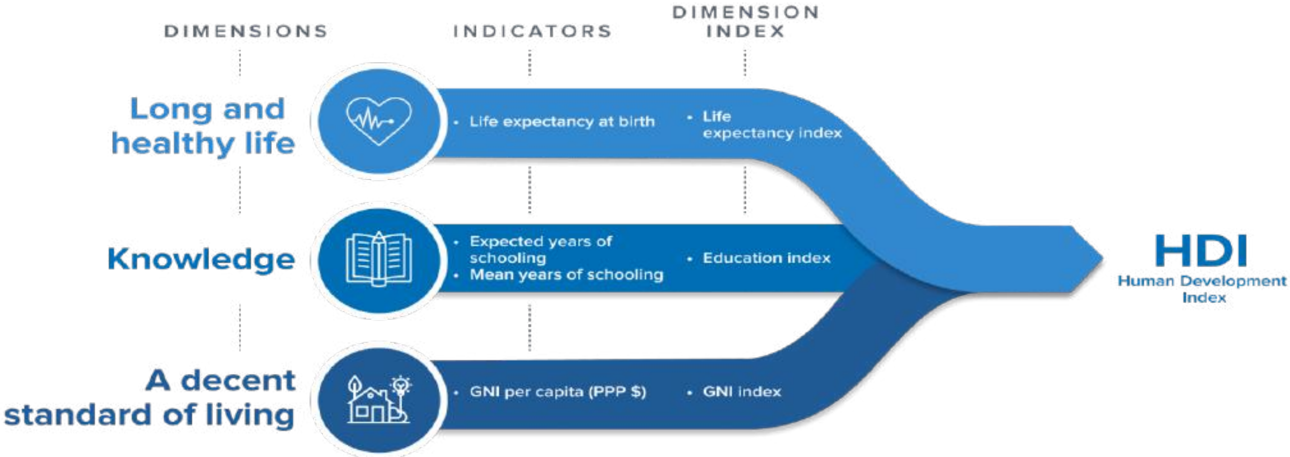

शीर्ष पांच देश	निचले पांच देश:	भारत के पड़ोसी देश:
1. स्विट्ज़रलैंड	187. बुरुंडी	73. श्रीलंका
2. नॉर्वे	188. मध्य अफ्रीकी गणराज्य	79. चीन
3.आइसलैंड	189. नाइजर	127. भूटान
4.हांगकांग	190.चाडी	129. बांग्लादेश
5. ऑस्ट्रेलिया	191. दक्षिण सूडान	143. नेपाल
		161. पाकिस्तान

भारतीय परिप्रेक्ष्य:

2021 में भारत का एचडीआई मूल्य 0.633 है जो विश्व औसत से 0.732 काफी अंतर है। 2020 में भी भारत ने 2019 के पूर्व-कोविड स्तर (0.645) की तुलना में अपने एचडीआई मूल्य (0.642) में गिरावट दर्ज की थी। वैश्विक रुझानों के अनुरूप भारत के मामले में, एचडीआई में 2018 में 0.645 से 2021 में 0.633 तक की गिरावट को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 70.7 वर्ष से 67.2 वर्ष तक की गिरावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

- भारत में स्कूली शिक्षा की अपेक्षित अवधि 11.9 वर्ष है।
- स्कूली शिक्षा की औसत अवधि 6.7 वर्ष है।
- GNI प्रति व्यक्ति आय स्तर +6,590 (PPP) है।

आगे की राह:

कुछ कदम जो भारत को एचडीआई के शीर्ष लिस्ट में जगह पाने के सपने को साकार कर सकते हैं, वे निम्नलिखित हैं:

- **निवेश को बढ़ाना:** शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश की आवश्यकता है।
- **प्रदर्शन मूल्यांकन:** परिणाम आधारित बजट (Outcome Budgeting), सामाजिक लेखा परीक्षा जैसे नवीन तरीकों के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र के विकास में लगी परियोजनाओं और गतिविधियों का प्रभावी प्रदर्शन मूल्यांकन हो।
- **असमानता को कम करना:** असमानता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे विभिन्न रूपों में पाई जाती है जो भारत की एचडीआई रैंकिंग को सबसे अधिक प्रभावित करती है। इसमें सेवाओं के वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है जिसे तत्काल आधार पर सुधारने की आवश्यकता है।
- **शासन और प्रशासन में सुधार:** सुशासन को बढ़ाने के साथ-साथ नई प्रबंधकीय तकनीकों को अपनाने से व्यापक सुधार आ सकते हैं जिससे देश के वास्तविक विकास को प्रभावित करने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकेगा।
- **नवोन्मेषी समाधान:** नई विकासात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए नवोन्मेषी नीतियों, कार्यक्रमों और तकनीकों को तैयार करने के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास पर जोर देने की आवश्यकता है।

4 हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF)

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान भारत ने इंडो-पैसिफिक इकोनामिक फ्रेमवर्क के चौथे स्तंभ नामक समझौते से स्वयं को बाहर रखने का निर्णय लिया।
- भारत ने यह निर्णय अपने डेटा की गोपनीयता एवं संरक्षण और स्वयं के डिजिटल ढांचे और कानूनों को मजबूत करने के लिए लिया है।
- भारत ने चार स्तंभों में से तीन पर सहमति व्यक्त की जिनमें आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी एवं स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं।

इंडो-पैसिफिक इकोनामिक फ्रेमवर्क (IPEF) मंत्रिस्तरीय बैठक:

इस बैठक का आयोजन सितंबर, 2022 में सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स में किया गया जिसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूएसटीआर राजदूत ताई और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो के साथ निम्नलिखित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की:

- भारत और अमेरिका के बीच आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक लचीला बनाना।
- उच्च स्तर की डेटा गोपनीयता बनाए रखने हेतु डिजिटल दुनिया में समकालीन और आधुनिक कानूनों का निर्माण करना।
- राष्ट्रीय हित के आधार पर आईपीईएफ ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर अपने निर्णय लेना।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सतत और न्यायसंगत विकास लाने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना।

इंडो-पैसिफिक इकोनामिक फ्रेमवर्क (IPEF)

- यह अमेरिका द्वारा प्रस्तावित एक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद- प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये भाग लेने वाले देशों के मध्य आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है।
- आईपीईएफ एक बहुपक्षीय आर्थिक ढांचा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से 23 मई, 2022 को टोक्यो में 'क्वाड शिखर सम्मेलन' में लांच किया गया था।
- वर्तमान में यह 14 देशों का समूह है- ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम।
- इन देशों की संयुक्त रूप से वैश्विक जीडीपी में 40% की हिस्सेदारी है। भारत एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है और इस क्षेत्र के विकास और समृद्धि के लिए भागीदारों के बीच आर्थिक सहयोग को गहरा करने की दिशा में काम कर रहा है।
- यह एक गैर-बाध्यकारी समझौता है और इसमें चारों स्तंभों में कोई भी स्तंभ चुनने की स्वतंत्रता है।

इंडो-पैसिफिक इकोनामिक फ्रेमवर्क का भारत के लिए महत्त्वः

- भारत चीन की आक्रामक राष्ट्रवादी और विस्तारवादी नीति के विरुद्ध अपनी एक अलग और मजबूत भू-राजनीतिक स्थिति हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बना सकता है।
- यह आर्थिक निवेश में वृद्धि के साथ स्वच्छ ऊर्जा के लिये प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है।

आगे की राहः

इंडो-पैसिफिक इकोनामिक फ्रेमवर्क ने आत्मनिर्भरता तथा वैश्वीकरण में संतुलन लाने का काम किया है, लेकिन इस समूह में आपसी विश्वसनीयता और जटिल व्यापार प्रकिया जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं।

5 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और नेटफ्लिक्स में विवाद

- खाड़ी देशों और नेटफ्लिक्स के बीच बड़ा विवाद सामने आया है और खाड़ी देशों के सबसे महत्वपूर्ण संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने नेटफ्लिक्स को चेतावनी दी है कि वह इस्लामिक वैल्यू और उसके खिलाफ चलाए जा रहे और दिखाए जा रहे कंटेंट को हटा ले नहीं तो उसे खाड़ी देशों में बैन कर दिया जाएगा।
- दरअसल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि नेटफ्लिक्स कई ऐसे प्रोग्राम दिखा रहा है जिसमें वह इस्लामिक लोगों को गे और लैसबियन के रूप में प्रदर्शित कर रहा है और अगर उसने ऐसा करना जारी रखा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात ने कड़े शब्दों में नेटफ्लिक्स की निंदा की है और कहा है कि विचार और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा

रहा है।

- सऊदी अरब के अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने अलग से वक्तव्य जारी करके नेटफ्लिक्स को चेतावनी दी है कि वह अपने प्लेटफॉर्म से समलिंगी सम्बंध से जुड़े कंटेंट हटा लें। सऊदी अरब के स्टेट टेलीविजन ने तो एक इंटरव्यू में नेटफ्लिक्स को होमोसेक्सुअलिटी का ऑफिशियल स्पॉन्सर भी कह दिया है। कई मुस्लिम बहुल वाले देशों ने समलिंगी सम्बंध को दंडनीय अपराध ठहराया है और ऐसे संबंधों को प्रदर्शित करने वाले फिल्मों और कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया है। कुछ देशों ने तो इस पर डेथ पेनेल्टी का दंड भी रखा है।
- पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात और अन्य मुस्लिम देशों ने वाल्ट डिजनी पिक्चर के एनिमेटेड फीचर फिल्म लाइटईयर को सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग होने से रोक लगा दिया था क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में समलिंगी सम्बंध को दर्शाया गया था।

खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में:

- 6 खाड़ी देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने 25 मई, 1981 को एक समझौता के जरिए खाड़ी सहयोग परिषद का गठन किया था। इसका गठन सऊदी अरब के नेतृत्व में रियाद में किया गया था। रियाद में ही खाड़ी सहयोग परिषद् का मुख्यालय भी स्थित है। 6 खाड़ी देशों ने घोषणा की थी कि खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना उनके बीच विशेष संबंधों को ध्यान में रखते हुए और इस्लामी सिद्धांतों, संयुक्त नियति एवं साझे उद्देश्यों पर आधारित अपनी समान राजनीतिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर की गई है।
- इसके उद्देश्यों की बात करें तो खाड़ी सहयोग परिषद की संकल्पना रक्षा योजना परिषद के साथ-साथ क्षेत्रीय साझा बाजार के रूप में की गई थी । इन देशों की भौगोलिक निकटता तथा मुक्त व्यापार और आर्थिक नीतियों को व्यापक रूप से अपनाए जाने से खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना में सहायता मिली।
- खाड़ी सहयोग परिषद की संरचना में सर्वोच्च परिषद, मंत्रिपरिषद और महासचिवालय शामिल हैं: सर्वोच्च परिषद (खाड़ी सहयोग संगठन की शीर्ष सत्ता) में 6 सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। सर्वोच्च परिषद की वर्ष में एक बार साधारण बैठक होती है। किन्हीं दो सदस्य राष्ट्रों के अध्यक्षों द्वारा किसी भी समय आपात बैठक बुलाई जा सकती है। सर्वोच्च परिषद की अध्यक्षता बारी-बारी से प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को प्राप्त होती है।
- खाड़ी सहयोग परिषद् में संकल्प बहुमत से पारित किए जाते हैं।

6 नौसेना अभ्यास काकाडू 2022

चर्चा में क्यों?

भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा और पी8आई समुद्री गश्ती विमान 12 सितंबर 2022 को रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंचे।

नौसेना अभ्यास काकाडू 2022:

- अभ्यास काकाडू 2022 (KA22) ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना के समर्थन से ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है।
- इस साल 12 से 24 सितंबर तक चलने वाले इस द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास में लगभग 3,000 कर्मियों, 15 युद्धपोतों और 30 से अधिक विमानों, 14 नौसेनाओं को शामिल किया गया है।
- इस वर्ष अभ्यास की थीम 'साझेदारी, नेतृत्व और दोस्ती' है।
- इस अभ्यास के बंदरगाह चरण में पोत के चालक दल भाग लेने वाली नौसेनाओं के साथ परिचालन संबंधी योजना के बारे में संवाद और खेल संबंधी गतिविधियों में संलग्न होंगे।

नौसेना अभ्यास काकाडू के बारे में:

- समुद्री और हवाई क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच अंतर-संचालन क्षमता विकसित करने के साथ ही समुद्री सुरक्षा एवं निगरानी हेतु प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी।
- यह अभ्यास द्विवार्षिक रूप से डार्विन और उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई अभ्यास क्षेत्रों (NAXA) में आयोजित किया जाता है।
- इस अभ्यास का नाम काकाडू राष्ट्रीय उद्यान से लिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में एक संरक्षित क्षेत्र है। यह डार्विन से 171 किमी दक्षिण-पूर्व में है।

आईएनएस सतपुड़ा के बारे में:

- आईएनएस सतपुड़ा एक शिवालिक-क्लास स्टील्थ मल्टी-रोल फ्रिगेट है जिसमें तलवार-क्लास फ्रिगेट की तुलना में बेहतर स्टील्थ और लैंड अटैक क्षमता है।
- स्टील्थ फ्रिगेट को मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया था।
- यह पूर्वी नौसेना कमान (आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मुख्यालय) के तहत संचालित है।

1 रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि आक्रामक और विदेशी साउथ रेड-ईयर्ड स्लाइडर टर्टल्स (Red-Eared Slider Turtles) की उपस्थिति भारतीय कछुओं के विलुप्त होने का कारण बन सकता है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त 356 कछुओं की प्रजातियों में से 29 फ्रेशवाटर के कछुओं का निवास भारत में है जिनमें से लगभग 80% संकटग्रस्त हैं।

रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्स:

इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेकेमीस स्क्रिप्टा एलिगेंस (Trachemys Sscripta Elegans) है। रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्स दक्षिण-पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की मूल प्रजाति है।

सुरक्षा की स्थिति:

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के रेड लिस्ट में कम चिंतनीय (Least Concern) है।
- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) में यह शामिल नहीं है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में यह शामिल नहीं है।
- रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्स को विक्टोरियन कैचमेंट एंड लैंड प्रोटेक्शन एक्ट, 1994 के तहत नियंत्रित परोपजीवी (Pest) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्स की विशेषताएँ:

- इनकी आँख के पीछे एक चौड़ी लाल या नारंगी की पट्टी होती है जिसमें संकीर्ण पीली धारियाँ होती हैं जो शेष काले शरीर, गर्दन, पैरों और पूँछ को चिह्नित करती हैं। उनके सामने और पिछले पैरों पर विशिष्ट लंबे पंजे मादा की तुलना में नर में अधिक लंबे होते हैं।

भारत में रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्स की उपस्थिति:

भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत देशी कछुओं को पालतू जानवर के रूप में पालना प्रतिबंधित है, लेकिन विदेशी नस्लें प्रतिबंधित नहीं हैं और पूरे भारत में कई परिवारों में पालतू जानवरों के रूप में इन्हें पाला जाता है।

- यह छोटी और आसानी से पालतू बनाई जाने वाली प्रजातियाँ हैं, इसीलिये पालतू कछुओं के रूप में ये लोकप्रिय हैं।
- भारत में ये कछुए मुख्य रूप से शहरी आर्द्रभूमि जैसे-चंडीगढ़ में सुखना झील, गुवाहाटी के टेम्पल पोंड्स, बेंगलुरु की झील, मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दिल्ली में यमुना नदी आदि में पाए जाते हैं।

देशी प्रजातियों पर प्रभाव:

रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्स जैसे-जैसे परिपक्व होते हैं, ये बहुत आक्रामक होते जाते हैं। ये भोजन, घोंसले के शिकार और बेसिंग साइटों के लिये देशी कछुओं को प्रभावित करते हैं।

- ये पौधों और जानवरों को खाते हैं जो मछलियों एवं दुर्लभ मेंढकों सहित जलीय प्रजातियों की विस्तृत श्रृंखला को समाप्त कर सकते हैं।
- ये बीमारियों और परजीवियों को देशी सरीसृप प्रजातियों में भी स्थानांतरित कर सकते हैं।
- इस प्रजाति को दुनिया की 100 सबसे अधिक आक्रामक विदेशी प्रजातियों में से एक माना जाता है।

आगे की राह:

प्रजातियों को भारतीय पर्यावरण में प्रवेश करने और इसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करने से रोकने के लिये प्रभावी नियम होने चाहिये जिससे इनके पालने और स्थानीय जलाशयों में छोड़ने पर रोक लगाई जा सके। शहरी आर्द्रभूमि से इन कछुओं को पकड़कर स्थानीय चिड़ियाघरों में रखना चाहिए।

2 PM10 के स्तर में कटौती करने वाले शहरों में वाराणसी अव्वल

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत हुए सर्वे में वाराणसी पीएम 10 की सान्द्रता में सबसे अधिक 53% की गिरावट दर्ज करने वाला शहर बना।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी):

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को 2019 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में 131 उन

शहरों में यह लागू किया जा रहा है जिसमें 123 नॉन-अटैनमेंट सिटी (एनएसी) शामिल हैं। एनएसी ऐसे शहर होते हैं जो लगातार पांच वर्षों से राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के अनुरूप नहीं है। इनका लक्ष्य 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में 20% से 30% की कमी करना है। इन कार्य योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की रिपोर्टिंग एवं निगरानी PRANA नामक पोर्टल के माध्यम से की जाती है। इसका नोडल मंत्रालय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि एनसीएपी के तहत 131 शहरों में से 95 शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। उनमें से 20 शहरों ने राष्ट्रीय स्टैण्डर्ड को प्राप्त किया है।
- जिन शहरों के लिए डेटा उपलब्ध है, उनमें PM2.5 के स्तर में 2019 से 2021 के बीच 43 (NCAP) शहरों में से केवल 14 ने 10% या उससे अधिक की कमी दर्ज किया है।
- पर्याप्त डेटा वाले 46 गैर-एनसीएपी शहरों में से 21 ने अपने वार्षिक PM 2.5 सांद्रता में 5% या अधिक की गिरावट दर्ज किया है।
- वाराणसी, चेन्नई और पुणे शहरों में सबसे अधिक सुधार हुआ है।
- दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में 2017 की तुलना में 2021-22 में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS):

- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत, भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करता है।
- वर्तमान राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) में शामिल प्रदूषक हैं: SO_2, NO_2, PM10, PM2.5, O_3, लेड (Pb), CO, NH_3, बेंजीन (C_6H_6), आर्सेनिक (As) और निकल (Ni), जबकि बेंजो (ए) पाइरेन (BaP) केवल पार्टिकुलेट फेज में शामिल किया जाता है।
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में वायु गुणवत्ता की माप आठ प्रदूषकों, PM10, PM2.5, NO_2, SO_2, CO, O_3, NH_3 और Pb के आधार पर होता है।

- **पार्टिकुलेट मैटर (पीएम):** पार्टिकुलेट मैटर हवा में निलंबित (Suspended) ठोस और तरल कणों का योग होता है जिनमें से कई खतरनाक होते हैं। इस जटिल मिश्रण में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरह के कण शामिल हैं। जैसे- धूल, परागकण, कालिख, धुआं और तरल बूंदें आदि।

- **PM 10:** इसे मोटे कणों (coarse particles) के रूप में भी जाना जाता है। PM10 को 10 माइक्रोन या उससे छोटे कणों के रूप में परिभाषित किया गया है। PM10 आमतौर पर द्वितीयक वायुमंडलीय स्रोतों के बजाय निर्माण कार्य, सड़क की धूल, या प्राकृतिक धूल भरी आंधी जैसे स्रोतों के साथ सीधे उत्पन्न होते हैं।

- **PM 2.5:** इसे उन महीन कणों (fine particles) के रूप में भी जाना जाता है जिसका व्यास 2.5 माइक्रोन या उससे कम होता है। यह फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करने के साथ ही रक्तप्रवाह में प्रवेश करने में सक्षम है। ये सूक्ष्म कण प्राकृतिक या मानव निर्मित स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे- वाहन से, जंगल में आग, पराली जलाने से, फैक्ट्रियों से निकले धुओं से, बिजली संयंत्र उत्सर्जन और अन्य दहन गतिविधियां आदि।

3 लॉबस्टर मछलियों और कुछ अन्य प्रजातियों को 'रेड लिस्ट' में रखा गया

- अमेरिका स्थित पर्यावरण समूह सीफूड वॉच ने लॉबस्टर और कुछ अन्य प्रजातियों को अपनी 'रेड लिस्ट' में शामिल किया है, साथ ही लोगों को इसे अपने खाद्य सूची से हटाने की सलाह दी है। यह भी घोषित किया गया है कि 'उत्तरी अटलांटिक राइट व्हेल' को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- संरक्षण घोषणा में गिलनेट्स, ट्रैप और गमलों में पकड़ी गई प्रजातियों के साथ-साथ स्नो क्रैब और अटलांटिक रॉक क्रैब भी शामिल हैं।

समुद्री भोजन मामलों की स्थिरता की रैंकिंग:

- अमेरिका स्थित पर्यावरण समूह सीफूड वॉच समुद्री भोजन की स्थिरता को रैंक करने के लिए हरे से लाल रंग के चार रंगों के पैमाने का उपयोग करता है। अमेरिकन लॉबस्टर को एक एम्बर कलर रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता था, जो समुद्री भोजन के शौकीनों

को इसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करने में सचेत करता था।

- उत्तर अमेरिकी राइट व्हेल की जनसंख्या में गिरावट के कारण इस चेतावनी को गंभीरता से लिया गया, जिसे अमेरिकी वन्यजीव अधिकारियों ने विलुप्त होने के कगार पर घोषित किया है।

लॉबस्टर मछली के बारे में:

- लॉबस्टर मछली कई समुदायों का मुख्य भोजन है। लॉबस्टर मछली 'क्रसटेशियन' परिवार से संबंधित हैं। वे समुद्री जानवर हैं जिनके पांच जोड़ी पैर होते हैं जिनमें से तीन पंजे होते हैं। दुनिया भर में यह लक्जरी सीफूड के रूप में लोकप्रिय है और कई समुदायों में मुख्य भोजन के रूप में भी इसका सेवन किया जाता है।
- एक लॉबस्टर मछली में शरीर के दो मुख्य भाग होते हैं जो सेफलोथोरैक्स और पेट होते हैं। एक लॉबस्टर मछली के सिर में एंटीना होता है जिसका उपयोग वे अपने परिवेश को महसूस करने के लिए करते हैं। आमतौर पर लॉबस्टर का रंग हरा-नीला से लेकर लाल-नारंगी और भूरा तक हो सकता है, लेकिन ये कई अलग-अलग रंगों में भी पाए जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लॉबस्टर मछली 45 साल या उससे अधिक तक जीवित रह सकती है और लॉबस्टर मछलियों की विभिन्न प्रजातियों की लंबी उम्र की गणना या अनुमान उसके आकार और अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर किया जाता है।

4 तमिलनाडु ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया

- दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु वन्यजीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। हाल ही में, तमिलनाडु सरकार ने तिरुपुर जिले के नंजरायण टैंक में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया।
- इसके साथ ही राज्य सरकार ने तिरुपुर जिले के नंजरायण में तमिलनाडु के 17वें पक्षी अभयारण्य को अधिसूचित किया है।
- तमिलनाडु के वन मंत्री के. रामचंद्रन द्वारा अप्रैल में इस सन्दर्भ में राज्य विधानसभा में एक घोषणा के बाद यह आदेश जारी किया गया कि 7.5 करोड़ रुपये के सरकारी कोष का उपयोग करके नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य में बदल दिया जाएगा।
- इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव वार्डन ने प्रस्ताव दिया था। सावधानीपूर्वक जांच के बाद, तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत क्षेत्र को 'नंजरायण पक्षी अभयारण्य' के रूप में अधिसूचित किया।
- राज्य सरकार ने वन्यजीवों और उनके पर्यावरण की रक्षा, प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से तिरुपुर के क्षेत्र में पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव, वनस्पति, प्राकृतिक और भू-आकृति संबंधी महत्व को माना है।

- उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिसंबर 2021 में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने विल्लुपुरम के पास स्थित काजुवेली आर्द्रभूमि को 'काजुवेली पक्षी अभयारण्य' घोषित किया था।

अभयारण्य घोषित करने की प्रक्रियाः

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 26 ए अभयारण्य की घोषणा को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार एक ऐसे क्षेत्र का गठन करने की घोषणा कर सकती है जिसमें वन्यजीवों के संरक्षण के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, वनस्पति, जीव, प्राकृतिक या प्राणी महत्व हो।

5 गिद्धों के लिए खाद्य केंद्र स्थापित करेगा फंसड़ अभयारण्य

- हाल ही में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित फंसड़ वन्यजीव अभयारण्य में गिद्धों की संख्या कम होने पर उनके लिए 'खाद्य केंद्र' स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- मुंबई से करीब 140 किलोमीटर दूर इस अभयारण्य में सात साल पहले तक 30 से ज्यादा गिद्ध हुआ करते थे लेकिन अब ज्यादातर पक्षी भोजन के अभाव में दूसरे इलाकों में चले गए हैं।
- गैर-लाभकारी संगठन ग्रीन वर्क्स ट्रस्ट ने अभयारण्य द्वारा शुरू की गई गिद्ध संरक्षण परियोजना के तहत एक खाद्य केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ग्रीन वर्क ट्रस्ट के सदस्य शव को भोजन केंद्र तक ले जाएंगे, जहां गिद्धों के आने की संभावना है। गिद्ध मुख्य रूप से कैरियन को खाते हैं जो दुर्लभ हो गया है।
- लगभग 7,000 हेक्टेयर में फैले इस अभयारण्य में पक्षियों की 160 से अधिक प्रजातियां, सरीसृप की कम से कम 30 प्रजातियां और स्तनधारियों की 17 प्रजातियां निवास करती हैं।

भारतीय गिद्धों के विलुप्त होने पर खतरा:

- 1980 के दशक तक गिद्ध काफी सामान्य थे और वर्तमान में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान में, अफ्रीका में सात प्रजातियों और भारत में आठ प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। भारत ने तीन प्रजातियों, सफेद पीठ वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध और पतले-बिल वाले गिद्ध की 99 प्रतिशत आबादी खो दी है।
- लाल सिर वाले और मिस्र के गिद्धों की आबादी में भी क्रमशः 91 प्रतिशत और 80 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस तेजी से आई गिरावट को 1990 के दशक के दौरान पशु चिकित्सा पद्धति में डाइक्लोफेनाक, एक गैर-स्टेरायडल दवा (एनएसएआईडी) के उपयोग को जिम्मेदार माना गया है।
- जब गिद्ध किसी ऐसे जानवर के शव को खाते हैं जिसे उसकी मृत्यु से 72 घंटे पहले डाइक्लोफेनाक से उपचारित किया गया हो, तब वे डाइक्लोफेनाक के संपर्क में आते हैं। यह दवा गिद्धों के लिए अत्यंत विषैली होती है और उनके गुर्दे को प्रभावित करती है। इसके कारण, वे आंत के गठिया से मर जाते हैं।

6 भारत में समुद्री खीरे की स्थिति पर रिपोर्ट

वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के विश्लेषण के अनुसार, तमिलनाडु में 2015 और 2021 के बीच सबसे अधिक समुद्री वन्यजीवों के बरामदी हुई हैं। यह विश्लेषण भारत में समुद्री प्रजातियों के अवैध व्यापार 2015-2021 शीर्षक वाले 2015 और 2021 के बीच भारत में समुद्री वन्यजीवों की बरामदगी के बारे में 187 मीडिया रिपोर्टों के आकलन पर आधारित है। इसमें सात प्रजातियों के समूहों- समुद्री खीरा (sea cucumber), कोरल, समुद्री घोड़े (seahorse) और पाइपफिश, शार्क, रे(ray), सीशेल (seashell), समुद्री पंखे (sea fan) और समुद्री कछुए में अवैध समुद्री व्यापार दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट का निष्कर्ष:

- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 और 2021 के बीच भारत में समुद्री खीरा सबसे अधिक तस्करी की जाने वाली समुद्री प्रजाति थी।
- तमिलनाडु में समुद्री खीरा बरामदगी की सबसे अधिक (105 घटनाएं) इसके बाद लक्षद्वीप (12 घटनाएं) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (5 घटनाएं) दर्ज की गई हैं।

- श्रीलंका (26 घटनाएं), चीन (6 घटनाएं) और मलेशिया (2 घटनाएं) उन देशों के रूप में दर्ज किए गए जो या तो पारगमन स्थान (Transit Locations) हैं या व्यापार के गंतव्य हैं।

समुद्री खीरा के बारे में:

- समुद्री खीरा ईचिनोडर्म्स नामक एक बड़े जीव समूह का हिस्सा हैं, जिसमें स्टारफिश और समुद्री अर्चिन भी शामिल हैं। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अनुसूची 1 की प्रजातियों के तहत लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1 सर्वाइकल कैंसर हेतु पहला भारतीय स्वदेशी टीका-"सर्वावैक"

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी टीका-"सर्वावैक" की घोषणा की।

"सर्वावैक" टीका के बारे में:

यह भारत में सर्वाइकल कैंसर के इलाज हेतु पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, डीबीटी (जैव प्रौद्योगिकी विभाग) और बीआईआरएसी (जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद) के सहयोग से किया गया है।

सर्वाइकल कैंसर के बारे में:

- सर्वाइकल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है, जो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में होता है। इस कैंसर का कारण वायरस होता है जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं जो यौन संबंध के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और बार-बार इस वायरस के संक्रमण से सर्वाइकल कैंसर हो जाता है।
- सर्वाइकल कैंसर से गर्भाशय ग्रीवा के स्तर में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। गर्भाशय ग्रीवा महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है जो गर्भ के निचले हिस्से में स्थित होती है, जो गर्भ से योनि तक खुलती है। इस कैंसर को बच्चेदानी के कैंसर के नाम से भी जाना जाता है।
- सर्वाइकल कैंसर भारत में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है जो विश्व में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है।
- मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, हर साल लगभग 1.25 लाख महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है और इस रोग से भारत में 75 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है।

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण:

- पीरियड्स के दौरान खून आना।
- संभोग के बाद खून बह आना।
- रजोनिवृत्ति के बाद भी खून आना।
- तेज गंध के साथ योनि से स्राव होना।
- पेडू (कोख) में दर्द बना रहना।

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के बारे में:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन यह विभाग कृषि, स्वास्थ्य देखरेख, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योगों के लिए जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं अनुप्रयोगों को बढ़ावा देता है। यह जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने, जैव-प्रौद्योगिकी को एक प्रमुख साधन के रूप में ढालकर भविष्य में सम्पदा निर्माण के साथ ही विशेषकर गरीबों के कल्याण हेतु सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर ध्यान देता है।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने पिछले तीन दशकों में भारतीय टीका अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण पहलों को लागू किया है। इनमें (i) भारत-अमेरिका वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम (ii) नेशनल बायोफार्मा मिशन, (iii) भारत- सीईपीआई मिशन (iv) मिशन कोविड सुरक्षा शामिल हैं। इन पहलों को देश के नागरिकों के लिए जल्द से जल्द सुरक्षित, प्रभावशाली, सस्ती और सुलभ स्वदेशी कोविड-19 टीका लाने के लक्ष्य के साथ आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत शुरू किया गया था।

आगे की राह:

- यह भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इस सस्ते और लागत प्रभावी टीके का निर्माण ही भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकता है और एक स्वस्थ भारत ही एक उत्पादक भारत हो सकता है।
- कैंसर का यह टीका पूरे विश्व और भारत की महिलाओं की बड़ी सहायता करेगा। निकट भविष्य में 'सर्वावैक' के अगले संस्करण 1, 2 और 3 बहुत जल्दी दुनिया को देखने को मिल सकते हैं।

2 भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत बायोटेक ने नाक से ली जाने वाली देश की पहली कोविड वैक्सीन तैयार कर ली है।

वैक्सीन के बारे में:

- इस 'इन्कोवैक' वैक्सीन को भारत बायोटेक ने प्रिसिजन वायरोलोजिक्स और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर तैयार किया है।
- यह कोविड-19 की रोकथाम हेतु बिना इंजेक्शन वाली तैयार की गयी पहली नेजल वैक्सीन है।
- 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को इस वैक्सीन की एक डोज दी जाएगी।
- इस वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है।
- वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर किया जा सकेगा।

कैसे काम करती है नेजल वैक्सीन?

- नेजल स्प्रे वैक्सीन को इंजेक्शन की बजाय नाक से दिया जाता है। यह नाक के अंदरुनी हिस्सों में इम्यून तैयार करती है। इसे ज्यादा कारगर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि कोरोना समेत हवा से फैलने वाली अधिकांश बीमारियों के संक्रमण का मार्ग प्रमुख रूप से नाक ही होता है और उसके अंदरूनी हिस्सों में इम्युनिटी तैयार होने से ऐसे बीमारियों को रोकने में ज्यादा असरदार साबित होती है।

इस वैक्सीन के फायदे:

- इंजेक्शन से छूटकारा मिल जाएगा और इससे फेफड़ों की बेहतर सुरक्षा होगी।
- नाक के अंदरुनी हिस्सों में इम्यून तैयार होने से सांस से संक्रमण होने का खतरा कम हो जाएगा।
- इंजेक्शन सीरिंज के न इस्तेमाल होने के कारण हेल्थवर्कर्स को ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होगी।
- बच्चों और बुजुर्गों का टीकाकरण करना आसान हो जाएगा।
- उत्पादन आसान होने से दुनियाभर में डिमांड के अनुरूप उत्पादन और सप्लाई संभव हो जाएगी।
- कम लागत के कारण छोटे और गरीब देश इसे सस्ते दामों में खरीद सकेंगे।
- इसमें सीरिंज का यूज नहीं होने से मेडिकल कचरे से भी राहत मिलेगी।

भारत बायोटेक:

- भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है जो दवा की खोज, दवाईयां बनाने, टीकों के निर्माण, जैव-चिकित्सीय, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल सम्बंधी उत्पादों का उत्पादन करती है। इसकी स्थापना 1996 में हैदराबाद में कृष्णा एल्ला ने की थी।

3 WEST: एक नयी I-STEM पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं' (WEST) नामक एक नई पहल, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का खाका (I-STEM) द्वारा शुरु किया गया है।

WEST पहल:

- यह कार्यक्रम 'स्टेम' पृष्ठभूमि वाली महिलाओं के लिए है जो उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन इकोसिस्टम में योगदान देने के लिए सशक्त करेगा।
- महिलाएं WEST कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हितधारक बनने के अवसरों का पता लगा सकती हैं।
- इसके सहायता से महिलाएं विभिन्न स्तरों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करियर बना सकती हैं। जैसे- तकनीशियन, प्रौद्योगिकीविद, वैज्ञानिक, उद्यमी इत्यादि।
- यह उन्हें वैज्ञानिक उपकरणों के संचालन और उनकी देखरेख से लेकर, उनके डिजाइन और निर्माण तक में अवसर प्रदान करेगा।
- इसमें WEST को समर्पित महिलाओं की एक टीम होगी।
- इसमें ऑनलाइन चर्चा व किसी भी तरह की सहायता के लिए एक डिजिटल कंसोर्टियम कनेक्ट क्विकली स्थापित किया गया है ताकि तत्काल समस्या का समाधान हो सके।

I-STEM के बारे में:

- भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का खाका (I-STEM) जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है जिसे जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।
- इसके पहले चरण में सम्पूर्ण देश से 1050 संस्थानों को शामिल किया गया था जिसमें 20 हजार से अधिक शोध कर्ता शमिल हैं।
- यह केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की एक पहल है जो प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) मिशन के तहत काम करता है।
- आई-स्टेम परियोजना को 2026 तक पांच साल के लिए विस्तार दिया गया है और इसने अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अपने दूसरे चरण में प्रवेश किया है।
- आई-स्टेम, वैज्ञानिक रूप से इच्छुक महिला शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में बेसिक या अप्लाइड साइंसेज में अनुसंधान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

महत्त्वः

- यह देश की महिलाओं को रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा बुनियादी ढांचे में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने, प्रयोगशाला तकनीशियनों और उसके रखरखाव हेतु इंजीनियरों के रूप में शामिल होने में मदद करेगा।
- यह पहल करियर ब्रेक के बाद महिलाओं को वापस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डोमेन में आने हेतु प्रोत्साहित करेगी।
- I-STEM पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध अनुसंधान और विकास सुविधाओं तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्मों (COMSOL, MATLAB, LABVIEW, AUTOCAD) तक पहुंच से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिला उद्यमियों के लिए एक मजबूत समर्थन नेटवर्क तैयार हो सकेगा।

4 भारत की पहली उच्च-थ्रुपुट उपग्रह (एचटीएस) ब्रॉडबैंड सेवा

चर्चा में क्यों?

ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया (एचसीआई) और इसरो ने संयुक्त रूप से भारत की पहली उच्च-थ्रुपुट उपग्रह (एचटीएस) ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

उच्च-थ्रुपुट उपग्रह (एचटीएस) ब्रॉडबैंड सेवा के महत्त्वपूर्ण बिंदुः

- **एचसीआई-** यूएस आधारित ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम्स और भारतीय दूरसंचार ऑपरेटर भारती एयरटेल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।
- यह सेवा इसरो के GSAT-11 और GSAT-29 उपग्रहों का उपयोग करके भारत के दूरदराज के हिस्सों में उपग्रह इंटरनेट प्रदान करेगी।
- इसरो ने भारतीय ग्राहकों को उच्च बैंडविड्थ उपग्रह कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए GSAT-11 और GSAT-29 को वर्ष 2018 में लांच किया था। GSAT-11 उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से 14 Gbps तक इंटरनेट स्पीड प्रदान करने में सक्षम है।
- नई शुरू की गई एचटीएस ब्रॉडबैंड सेवा का मुख्य उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करना है।
- पिछले एक साल से, इस हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा का परीक्षण जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे कई क्षेत्रों में किया गया था।
- यह ब्रॉडबैंड सेवा 100 एमबीपीएस तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी बैंडविड्थ प्रदान करने में सक्षम है, मतलब प्रति दिन लगभग 2 जीबी डेटा।
- यह सामुदायिक इंटरनेट एक्सेस के लिए वाई-फाई हॉटस्पॉट, एसडी-वैन समाधान, मोबाइल नेटवर्क और छोटे व्यवसायों के लिए सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं भी प्रदान करता है।
- ह्यूजेस की एचटीएस सेवा में पहले से ही रिलायंस जियो और भारतीय स्टेट बैंक जुड़े हुए हैं।
- जिओ अपने स्थलीय दूरसंचार नेटवर्क के लिए दूरस्थ स्थानों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए 4G बैकहॉल (Backhaul) के लिए ह्यूजेस की सेवा का ही उपयोग करता है।
- एसबीआई रिमोट बैंक शाखाओं और स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) आउटलेट्स को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का उपयोग करता है।

हाई-थ्रुपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंडः

- एचटीएस एक संचार उपग्रह है जो पारंपरिक संचार उपग्रहों की तुलना में उच्च डेटा प्रोसेसिंग और डेटा ट्रांसफर क्षमता प्रदान करता है।

एचटीएस की विशेषताएंः

- **बैंडविड्थः** यह कम लागत पर बहुत अधिक बैंडविड्थ प्रदान करता है।
- **स्पॉट-बीमः** एचटीएस के संचालन में स्पॉट-बीम का उपयोग किया जाता है।

इसकी तुलना में पारंपरिक उपग्रह एकल बीम का प्रयोग करते हैं।

- **कनेक्टिविटी:** इनकी कनेक्टिविटी सामान्य संचार उपग्रह से कहीं अधिक बेहतर होती है। प्रेषक और रिसीवर के बीच डेटा बहुत कम समय में स्थानांतरित हो जाता है।

आगे की राह:

- ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया और इसरो की इस पहल से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही देश के दुर्गम क्षेत्रों को हाई स्पीड वाली इंटरनेट सर्विस भी मिलने लगेगी।

5 क्लस्टर्ड रेग्युलरली इंटरस्पेस्ट शार्ट पैलिनड्रामिक रिपीट्स (CRISPR)

चर्चा में क्यों?

क्रिस्पर-कैस 9 एडिटिंग तकनीक का मार्ग प्रशस्त वाले शोध-पत्र के प्रकाशन (सूक्ष्मजीव विज्ञानी इमैनुएल चारपेंटियर और जीव रसायन विज्ञानी जेनिफर डॉडना द्वारा) के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं।

क्या है CRISPR - cas9?

- **CRISPR:** जीवाणुओं में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार आनुवंशिक कोड़ या अनुक्रम है। इन अनुक्रम का निर्माण जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले बैक्टीरियोफेज से होता है। CRISPR अनुक्रम का प्रयोग जीवाणु हमला करने वाले प्रत्येक वायरस को याद रखने के लिए करते हैं; इसके लिए जीवाणु स्वयं के जीनो में वायरस के डीएनए को सम्मिलित कर लेते हैं। CRISPR अनुक्रम याद रखने से यह लाभ होता है कि जीवाणु को सामान वायरस द्वारा दोबारा हमला करने की स्थिति में प्रतिरक्षा प्राप्त होती है।
- Cas 9 एंजाइम एटॉमिक सीज़र के रूप में कार्य करते हैं जो डीएनए के भाग को काटने में सहायक होते हैं। ये स्वयं में एक प्रकार के जीन होते हैं जो क्रिस्पर अनुक्रम के पास स्थित होता है। यह जीन सक्रिय हो जाने पर विशेष एंजाइम का निर्माण करते हैं।

CRISPR - cas9 की क्रियाविधि:

- सर्वप्रथम प्रयोगशाला में गाइड आरएनए बनाया जाता है जो लक्षित जीन को चिन्हित करने में सहायक होता है। इसके उपरांत CRISPR cas9 का प्रयोग कर अवांछित भाग को काट दिया जाता है। डीएनए के वांछित हिस्से को काटे गए स्थान से जोड़ दिया जाता है।

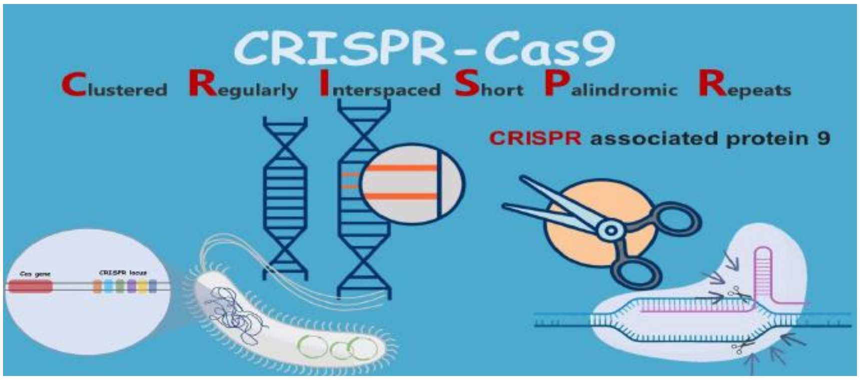

CRISPR तकनीकी के लाभ:

- दुर्लभ आनुवंशिक रोगों से निदान, आनुवंशिक रोगों से संबंधित महामारी विज्ञान के निर्धारण में सहायता, कैंसर सहित कई घातक बीमारियों से निजात में सहायता।
- जीन एडिटिंग के द्वारा जल की कम आवश्यकता वाली फसलों पादपों की उच्च उत्पादक फसलों को तैयार कर खाद्य सुरक्षा को प्रबंधित करना।
- सूखा एवं पर्यावरणीय प्रभाव का सामना करने के लिए अधिक कुशल एवं उत्पादक पौधे प्रदान करना।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन-शीलता में वृद्धि, फसलों को चरम जलवायु को सहन करने में सक्षम बनाने में सहायक, फसलों तथा मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की कार्बन अवशोषण क्षमता को बढ़ा सकता है।
- नवीन दवाओं के अविष्कार द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत कर सकता है।

चुनौतियां:

- डिजाइनर शिशु तथा भ्रूण में अनैतिक आनुवंशिक संशोधन को बढ़ावा मिल सकता है।
- डिजाइनर शिशु से असमानता में वृद्धि हो सकती है।
- इसके द्वारा ऐसे भी पौधों अथवा व्यक्तियों का निर्माण किया जा सकता है जो मानवता के लिए विनाशकारी हो।
- नवीन जीनों के आने से पर्यावरणीय जीन भंडार को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंच सकता है।
- आफ टार्गेटिंग के प्रभाव से उत्परिवर्तन की समस्या जन्म ले सकती है।

वैज्ञानिक उपलब्धियां:

- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पार्किंसन रोग के लिए जीन एडिटिंग थेरेपी का प्रयोग।
- चीन CRISPR के द्वारा कैंसर के इलाज पर कार्य कर रहा है।
- 2015 में चीन के द्वारा इस तकनीक के

प्रयोग से मायोसिन जीन को निष्क्रिय कर एक सुपर मस्कुलर कुत्ते के रूप में विकसित किया गया था।

- जापान में एचआईवी संक्रमित मानव की कोशिकाओं में वायरस को फैलने से रोकने के लिए CRISPR तकनीक का प्रयोग किया गया है।

CRISPR - cas9 क्षेत्र में भारत की प्रगति:

- राष्ट्रीय कृषि खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान इसका प्रयोग केले के डीएनए में वांछनीय परिवर्तन के लिए कर रही है।
- सिकल सेल एनीमिया रोग को रोकने के लिए इंस्टीट्यूट आफ जिनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी इस तकनीक का परीक्षण कर रहा है।
- स्ट्रैप्टॉकोक्कस पायोजेनेस cas9 की जगह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया फ्रांसेलिसा नोविसीड के उपयोग पर शोध किया जा रहा है जिससे आफ टार्गेटिंग की समस्या को दूर किया।

आगे की राह:

- मानव कल्याण को बढ़ावा देने वाले जीन को डिजाइन करना चाहिए।
- मानव जीनोम एडिटिंग का प्रयास तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक प्रभावी शोध द्वारा इसकी पुष्टि न की जाए तथा इसके सामाजिक सहमति को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- कृषि के क्षेत्र में तथा जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए इस पर बहुत तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है।

6 भारत का पहला मानव अंग परिवहन 'ड्रोन'

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने अस्पतालों में मानव अंगों को तुरंत भेजने लिए इंडियन ड्रोन टेक्नोलॉजी के पहले प्रोटोटाइप ड्रोन का उद्घाटन किया है।

मानव अंग परिवहन 'ड्रोन' के सम्बन्ध में अन्य बिंदु:

- हाल ही में इस सुविधा का प्रायोगिक अभ्यास, चेन्नई स्थित एमजीएम हेल्थकेयर अस्पताल द्वारा शुरू की गया है जो इस प्रोटोटाइप ड्रोन तकनीक का सह-निर्माणकर्ता भी है।
- इस ड्रोन द्वारा ऑर्गन बॉक्स को 20 किमी की दूरी तक जाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।
- भारत में हर साल अधिकतम 17,000-18,000 ठोस अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है। इसके लिए इस ड्रोन परिवहन सेवा से समय और धन दोनों की बचत हो सकेगी।

भारत में अंग प्रत्यारोपण:

- दुनियाभर में, अंगदानकर्ताओं की सर्वाधिक दर लगभग 34 प्रति मिलियन स्पेन में है, जबकि भारत में प्रति मिलियन लगभग 0.03 दाता हैं। भारत में तमिलनाडु में अंगदान करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत में सालाना 6 लाख गुर्दा दान की आवश्यकता है और केवल 6,000 गुर्दा प्रत्यारोपण होते हैं। अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की स्थापना 2014 में अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया की देखरेख के लिए की गई थी। इस संगठन के तहत दो संगठन- क्षेत्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (ROTTO) और राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (SOTTO) कार्य करते हैं।

भारत में मानव रहित ड्रोन:

- भारत में ड्रोन संचालन हेतु नियम भारत सरकार के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा बनाए एवं क्रियान्वित किए जाते हैं।
- मानव रहित ड्रोन को वजन के आधार पर चार भागों में वर्गीकृत किया गया है-

1. नैनो ड्रोन
2. माइक्रो ड्रोन
3. मीडियम ड्रोन
4. लार्ज ड्रोन

मानव रहित ड्रोन से सम्बंधित नियम:

- भारत में ड्रोन को केवल दिन में ही उड़ाने की अनुमति दी गयी है।
- ड्रोन का पंजीकरण कराना आवश्यक होता है।
- नो फ्लाई जोन में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गयी है।

आगे की राह:

- भविष्य में यह मानव अंग ड्रोन सुविधा अंगों के निर्बाध परिवहन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी जिससे स्वास्थ्य सेवा में सुधार होने की संभावना बढ़ जाएगी।

अर्थव्यवस्था

1 विंडफॉल टैक्स

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों पर सरकार द्वारा लगाए गए विंडफॉल टैक्स के जवाब में कहा कि इसे कुछ तेल रिफाइनरों कम्पनियों द्वारा प्राप्त किए गए अभूतपूर्व लाभ पर लगाम लगाने के रूप में देखा जाना चाहिए।

विंडफॉल कर (Windfall Tax):

- विंडफॉल टैक्स एक उच्च दर कर है। यह तब लगाया जाता है जब किसी विशेष कंपनी या उद्योग ने अचानक अधिक लाभ प्राप्त किया हो। चूंकि लाभ आंशिक रूप से बाहरी परिवर्तन से प्राप्त हुआ है, इसलिए कई विश्लेषकों ने इसे विंडफॉल लाभ कहा है। उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन युद्ध के समय ऊर्जा मूल्य में वृद्धि।

विंडफॉल टैक्स लगाने के पीछे देशों का तर्क:

- महामारी से उबरने के बाद ऊर्जा मांग में वृद्धि और रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप आपूर्ति में बाधा के चलते, ऊर्जा की वैश्विक कीमतों में वृद्धि हुई है। उर्जा की बढ़ती कीमतों का अर्थ है कि सऊदी अरामको, एक्सॉन मोबिल और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी ऊर्जा कंपनियों के लिए अधिक मुनाफा।
- जहां संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सभी सरकारों से इन अत्यधिक मुनाफे पर कर लगाने और इस कठिन समय में सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करने के लिए धन का उपयोग करने का आग्रह किया था, वहीं आईएमएफ, ओईसीडी जैसे संगठनों ने विंडफॉल करों को लागू करने का समर्थन किया है।
- भारत के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों जैसे-यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी ने ऊर्जा कंपनियों के सुपर नॉर्मल मुनाफे पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाया है या लगाने पर विचार कर रहे हैं। जुलाई में, भारत ने घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों पर विंडफॉल कर की घोषणा की जो तेल की ऊंची कीमतों का लाभ उठा रहे थे। इसके तहत डीजल, पेट्रोल और वायु टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगाया गया।

व्यक्तियों पर विंडफॉल कर:

- विंडफॉल कर उन व्यक्तियों पर भी लागू हो सकते हैं जो अचानक उपहार, विरासत, गेम शो, जुआ या लॉटरी जीतकर महत्त्वपूर्ण राशि प्राप्त करके समृद्ध हो जाते हैं।

ऐसे करों को लगाने में आने वाली समस्या:

- विंडफॉल कर भूतलक्षी (Retrospective) रूप से लगाए जाते हैं और अक्सर अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित होते हैं जो भविष्य के करों में अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं।
- आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि एक अस्थायी विंडफॉल लाभ कर शुरू करने से भविष्य के निवेश में कमी आती है क्योंकि संभावित निवेशक निवेश के समय इन करों से प्रभावित हो सकते हैं।
- वास्तविक विंडफॉल लाभ के निर्धारण को लेकर विवाद है। मुद्दा यह है कि केवल बड़ी कंपनियों पर ही विंडफॉल लाभ टैक्स लगाना उचित है या फिर छोटी कंपनियां भी इसमें शामिल होंगी।
- अधिकतर कंपनियां यह तर्क देती हैं कि यह वह लाभ है जो उन्होंने उद्योग में जोखिम लेने के कारण प्रतिफल के रूप में प्राप्त किया है।

2 विश्व डेयरी सम्मेलन-2022

चर्चा में क्यों?

- भारत के प्रधानमंत्री ने 12 सितंबर, 2022 को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन-2022 का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस सम्मेलन का विषय 'पोषण और आजीविका के लिए डेयरी' है।
- 12 से 15 सितंबर तक होने वाले इस सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा सहित 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।
- भारत में यह सम्मेलन 48 साल बाद दूसरी बार आयोजित हो रहा है जबकि पहली बार यह वर्ष 1974 में आयोजित हुआ था।
- इस सम्मेलन में देश के लगभग 800 किसान शामिल हुए।

भारत में डेयरी सेक्टर:

- भारत का डेयरी मॉडल दुनिया के लिए एक मिसाल है। भारत में डेयरी सेक्टर की प्रमुख योगदान छोटे किसानों का है। डेयरी सेक्टर से 70 प्रतिशत महिलाएं जुड़ी हैं। यह क्षेत्र देश में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार प्रदान करता है।
- भारत में दूध का उत्पादन 2 प्रतिशत वैश्विक विकास दर के मुकाबले 6 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रहा है। भारत में दूध का उत्पादन वर्ष 2014 में 146 मिलियन टन से बढ़कर वर्तमान में 209 मिलियन टन हो गया है। इसमें 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। दूध के वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा 23 प्रतिशत है। वर्तमान में, देश में प्रतिव्यक्ति दुग्ध उपलब्धता विश्व की 330 ग्राम की तुलना में 427 ग्राम है। भारत, चीन से तीन गुना ज्यादा दूध का उत्पादन करता है वहीं अमेरिका से 50 प्रतिशत अधिक।
- भैंस की उन्नत नस्लें- गुजरात के कच्छ क्षेत्र की बन्नी भैंस, मुर्राह, मेहसाणा, जाफराबादी, नीली रवि और पंढरपुरी एवं गाय की उन्नत नस्लें- गिर, साहिवाल, राठी, कांकरेज, थारपारकर और लाल सिंधी आदि ने भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाया है।

दूध उत्पादन में भारत के शीर्ष राज्य:

- उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और कर्नाटक।

डेयरी सेक्टर में चुनौतियां:

- पर्यावरण के लिहाज से यह क्षेत्र चुनौतियों से भरा है- डेयरी उद्योगों में संगठन का अभाव, प्रबंधन में कमी, मीथेन गैस उत्सर्जन की समस्या, पशुओं में जानलेवा बीमारियों का प्रभाव, न्यूनतम समर्थन मूल्य का आभाव, बजट के आवंटन में कमी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तकनीकी का अभाव आदि।

भारत सरकार के प्रयास:

भारत सरकार डेयरी सेक्टर की चुनौतियों के समाधान हेतु एक संतुलित डेयरी इको-सिस्टम विकसित करने पर काम कर रही है, जैसे-

- गांवों में हरित और सतत विकास के लिए पशुपालन और डेयरी को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन योजना, डेयरी क्षेत्र का डिजिटलीकरण और मवेशियों के सार्वभौमिक टीकाकरण के साथ-साथ सिंगल-यूज वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जैसी योजनाओं को लागू करना।
- डेयरी सेक्टर से जुड़े हर पशु की टैगिंग (बायोमीट्रिक पहचान) 'पशु आधार' नाम से की जा रही है।
- पशुओं में लम्पी स्किन बीमारी को समाप्त करने के लिए स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण करना।
- 2025 तक पशुओं में होने वाली फुट एंड माउथ और ब्रूसीलोसिस डिजीज को जड़ से खत्म करना।

आगे की राह:

पिछले कुछ दशकों में डेयरी क्षेत्र भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में उभरा है, इसलिए डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मानकीकृत करना और डेयरी सेक्टर के लिए समग्र तंत्र स्थापित करना वक्त की आवश्यकता है।

3 इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला एचडीफसी बना देश का पहला बैंक

- एचडीएफसी बैंक, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक, नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया।
- ई-बीजी कागज आधारित समय लेने वाली प्रक्रिया की आवश्यकता को समाप्त करता है।
- ई-बीजी दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाता है, जबकि लाभार्थी को तुरंत एनईएसएल पोर्टल पर बैंक गारंटी देखने में सक्षम बनाता है।
- ई-बीजी एनईएसएल पोर्टल पर एपीआई आधारित डिजिटल वर्कफ्लो के माध्यम से जारी किया जाएगा।
- समग्र बैंक गारंटी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण एमएसएमई के लिए व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करता है, जो बैंक गारंटी के लिए प्रमुख आवेदक होते हैं।
- ई-बीजी को एनईएसएल, सीवीसी-सीबीआई समिति और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के परामर्श से विकसित किया गया है।

प्रमुख लाभ:

- बैंक गारंटी अब सहज और डिजिटल हो गया है। मैन्युअल हस्ताक्षर के पुन: प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।
- प्रक्रिया के बारे में आवेदक और लाभार्थी दोनों के पास तुरंत सूचना जाएगी।
- रिकॉर्ड का कोई भौतिक रखरखाव नहीं है जिससे इसे संचालित करना आसान हो जाता है और आवेदक की कार्यशील

पूंजी दक्षता में भी वृद्धि होती है।

- सुरक्षित इंटरफेस इसे धोखाधड़ी वाले उपकरणों से जोखिम मुक्त बनाता है।

बैंक गारंटी का अर्थः

- बैंक गारंटी, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से भुगतान जोखिम लेने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से किया गया वादा है। बैंक गारंटी बैंक और उसके ग्राहकों के बीच एक संविदात्मक दायित्व पर दी जाती है। तीसरे पक्ष को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस तरह की गारंटियों का व्यापक रूप से व्यापार और व्यक्तिगत लेनदेन में उपयोग किया जाता है। यह गारंटी एक कंपनी को उन चीजों को खरीदने में मदद करती है जो वह आमतौर पर नहीं कर सकती थी, इस प्रकार व्यवसाय को बढ़ाने और उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देने में मदद करती है।

बैंक गारंटी के उपयोगः

- जब बड़ी कंपनियां छोटे विक्रेताओं से खरीददारी करती हैं, तो उन्हें आम तौर पर ऐसे व्यावसायिक अवसर प्रदान करने से पहले विक्रेताओं को बैंकों से गारंटी प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- मुख्य रूप से क्रेडिट आधार पर माल की खरीद और बिक्री में उपयोग किया जाता है, जहां खरीददार द्वारा डिफॉल्ट के मामले में विक्रेता को बैंक से भुगतान का आश्वासन दिया जाता है।
- व्यक्तियों की विश्वसनीयता को प्रमाणित करने में मदद करता है, जो बदले में, उन्हें ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और व्यावसायिक गतिविधियों में भी सहायता करता है।

लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी):

- एलओसी एक वित्तीय दस्तावेज है जो आवेदक द्वारा आवश्यक कुछ सेवाओं के पूरा होने पर लाभार्थी को भुगतान करने के लिए बैंक पर दायित्व डालता है। एलओसी बैंक द्वारा जारी किया जाता है जब खरीददार अपने बैंक से कुछ सामान या सेवाओं की प्राप्ति पर विक्रेता को भुगतान करने का अनुरोध करता है।

नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल):

- एनईएसएल भारत की पहली सूचना उपयोगिता है और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तत्वावधान में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ पंजीकृत है। कंपनी की स्थापना प्रमुख बैंकों और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा की गई है। एनईएसएल की प्राथमिक भूमिका किसी भी ऋण/ दावे से संबंधित जानकारी रखने वाले कानूनी साक्ष्य के भंडार के रूप में कार्य करना है।

निष्कर्षः

इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी एचडीएफसी बैंक द्वारा उठाया गया एक बहुत अच्छा कदम है। इससे छोटे उद्योग लाभान्वित होंगे। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और देश का विकास हो सकेगा। अब समय के अनुसार हर बैंक को इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए।

4 सभी कानूनी ऐप्स की एक 'व्हाइट लिस्ट' तैयार करेगा आरबीआई

अवैध लोन ऐप के खिलाफ कार्यवाही करना संगठित आर्थिक अपराधों से निपटने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण है। अवैध लोन एप न केवल उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं बल्कि देश में अपराधियों के एक समानांतर अर्थव्यवस्था को स्थापित करने में मददगार साबित होते हैं। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक सभी वैध ऐप्स की एक 'व्हाइट लिस्ट' तैयार करेगा और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ये 'व्हाइट लिस्ट' ऐप ही ऐप स्टोर पर होस्ट किए जाएं। **यह निर्णय 15 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अवैध लोन ऐप्स से संबंधित मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।**

बैठक के अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयः

- भारतीय रिजर्व बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वाले वर्ण संकर या किराए के खातों की निगरानी करेगा और निष्क्रिय गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की समीक्षा करेगा एवं समीक्षा के बाद उनको रद्द भी करेगा ताकि इन कंपनियों का दुरुपयोग ना हो सके। वर्ण संकर (Mule) खाते सामान्तयाः चोरी के खाते होते है जिनमें अपराधियों द्वारा गैर-कानूनी पैसा डाला जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि एक समय सीमा के अंदर भुगतान एग्रीग्रेटरों का पंजीकरण हो और उसके बाद किसी भी गैर-पंजीकृत भुगतान एग्रीग्रेटर को कार्य करने की अनुमति न हो। भुगतान एग्रीगेटर एक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता है जो व्यापारियों को अपनी वेबसाइटों या ऐप्स में एकीकृत करके ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देता है। उदाहरण – गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम आदि।
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मुखौटा कम्पनियों (shell company) को चिन्हित करेगा और दुरुपयोग रोकने के लिए उनका

पंजीकरण समाप्त करेगा। मुखौटा कंपनी वो कंपनी होती है जो सिर्फ कागज पर होती है जिनका वास्तव में उपयोग अनियमित धन के लेन देन के लिए किया जाता है।

- ऐसे अवैध लोन ऐप के संचालनों को रोकने के लिए सभी मंत्रालय/ एजेंसियां सभी संभव कदम उठाएंगे।
- वित्त मंत्रालय नियमित आधार पर परिपालन के लिए कार्यवाही करने योग्य बिन्दुओं की निगरानी करेगा।

निष्कर्ष:

वर्तमान समय में, भारतीय अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, डेटा का उल्लंघन, अनियमित भुगतान एग्रीगेटर्स, शेल कंपनियों का चलन आदि। हालांकि भारत सरकार ने इसके लिए कई प्रयास किये हैं। जैसे धन शोधन निवारण अधिनियम, डिजिटल इंडिया, आधारकार्ड, पेनकार्ड, आयकर अधिनियम में बदलाव, विमुद्रीकरण, एमसीए 21, जीएसटी और गैर-सरकारी संगठनों को विनियमित करना इत्यादि शामिल है। इन पहलों से भारतीय वित्तीय प्रणाली में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।

5 नॉर्वेजियन केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा

चर्चा में क्यों?

- नॉर्वे के केंद्रीय बैंक ने एथेरियम तकनीक पर आधारित देश की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) सैंडबॉक्स के लिए ओपन सोर्स कोड प्रकाशित किया है जो डिजिटल मुद्रा विकसित करने के प्रयास में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। नॉर्वे के केंद्रीय बैंक द्वारा एथेरियम तकनीक का उपयोग राष्ट्रीय मुद्रा के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देगा। यह विकास क्रिप्टोग्राफिक तकनीक को अपनाने से संभव हुआ है। सैंडबॉक्स को टेस्ट नेटवर्क के साथ संचार करने के लिए बनाया गया है। यह आरसी-20 टोकन को माइनिंग नष्ट और स्थानांतरित करने जैसी सुविधाओं को सक्षम करेगा।
- एथेरियम एक विकेन्द्रीकृत ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो एक पीयर-टू-पीयर नेटवर्क स्थापित करता है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नामक एप्लिकेशन कोड को सुरक्षित रूप से निष्पादित (execute) और सत्यापित करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रतिभागियों को एक विश्वसनीय केंद्रीय प्राधिकरण के बिना एक दूसरे के साथ लेनदेन करने की अनुमति देते हैं।
- क्रिप्टोग्राफी तकनीक एक सुरक्षित संचार के उपयोग के लिए विकसित तकनीक है जो केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता को इसकी सामग्री देखने की अनुमति देती है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) क्या है?

- सीबीडीटी एक कागजी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है जो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित कानूनी निविदा हैं। यह फिएट मुद्रा के समान है। ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल फिएट मुद्रा या सीबीडीसी का लेन-देन किया जा सकता है। बहामा अपनी राष्ट्रव्यापी सीबीडीसी सैंड डॉलर लॉन्च करने वाला पहला देश है।
- हालांकि सीबीडीसी की अवधारणा सीधे बिटकॉइन से प्रेरित थी, फिर भी यह विकेन्द्रीकृत आभासी मुद्राओं और क्रिप्टो संपत्तियों से अलग है जो राज्य द्वारा जारी नहीं की जाती हैं जिनमे कानूनी निविदा का अभाव होता है।

उद्देश्य:

- वास्तविक मुद्रा में आने वाली जोखिम को कम करना।
- नोटों के रख रखाव, परिवहन और फटे नोटों को बदलने में आने वाली लगत को कम करना।
- यह मनी ट्रांसफर के साधन के रूप में लोगों को क्रिप्टोकरेंसी से भी दूर करेगा।

लाभ:

- मुद्रा प्रबंधन लागत को कम करके सीबीडीसी धीरे-धीरे आभासी मुद्रा की ओर एक सांस्कृतिक बदलाव ला सकता है।
- सीबीडीसी एक विश्वसनीय संप्रभु समर्थित घरेलू भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए एक आसान साधन प्रदान कर सकता है।
- इसका उपयोग सीमा पार से भुगतान के लिए भी किया जा सकता है, यह सीमा पार भुगतानों को निपटाने के लिए संवाददाता बैंकों के महंगे नेटवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।
- यह वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।

निष्कर्ष:

डिजिटल क्रांति और उद्योग 4.0 के युग में, भारत सहित कई देश सीबीडीसी विकसित कर रहे हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सीबीडीसी को अपनाने से पहले साइबर खतरे और निजता जैसी चुनौतियों के मुद्दे को सुलझा लिया जाए।

कला और संस्कृति

1 करमा पूजा उत्सव

चर्चा में क्यों?

6 सितंबर, 2022 को करमा पूजा उत्सव झारखंड, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम आदि राज्यों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

करमा पूजा उत्सव के बारे में:

- यह भाई-बहन का त्यौहार है जिसमे बहनें सजी हुई थाली लेकर करमा (एक प्रकार का पेड़) पेड़ की पूजा करके भाइयों के लिए सुख समृद्धि और उनके दीर्घायु की कामना करती हैं।
- करमा त्यौहार के कुछ दिन पहले युवतियां नदी या तालाब से बालू उठाकर एक डाली में भरती हैं और इसमें सात प्रकार के अनाज जौ, गेहूं, मकई, धान, चना, उरद, कुलथी आदि भी बोती हैं। दूसरे दिन से युवतियां रोज उसकी पूजा करती हैं और हल्दी पानी से सींचती हैं। इसके बाद युवतियां विशेष गीत गाती हैं और 'मांदर' ढोल बजने के साथ नृत्य भी करती हैं। पूजा के दिन गांव के बुजुर्ग और युवा नाचते-गाते हुए करमा पेड़ की तीन शाखाएं काट कर लाते हैं। इन शाखाओं को घर के आंगन में गाड़ते हैं। इसके बाद रात भर उत्सव होता है और अगले दिन इन शाखाओं को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है।

"मांदर" ढोल के बारे में:

- यह झारखंड का एक लोक वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से झारखंड के लोक संगीत में ताल के लिए किया जाता है। यह झारखंड में बहुत ही लोकप्रिय है जो हाथ से बजाने वाले ड्रम के रूप में जाना जाता है। इसकी बनावट बेलनाकार होती है जिसमें इसका केंद्र उभरा हुआ होता है। इसका एक सिरा दूसरे सिरे से बड़ा होता है।

करमा पूजा उत्सव से संबंधित लोक कथा:

- प्राचीन कथाओं के अनुसार, कर्मा-धर्मा नाम के दो भाई थे जो अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करते थे। मेहनत करने के बाद भी वे काफी गरीब थे। उनकी बहन भगवान की भक्त थी और करमा पौधे की पूजा करती थी। एक बार जब दुश्मनों ने गांव पर हमला कर दिया तो दोनों भाइयों ने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी बहन को बचाया तब बहन ने खुश होकर करमा पौधे की पूजा की और अपने भाइयों के लिए धन मांगा। इससे वे काफी अमीर हो गए। तभी से करमा पौधे की पूजा भाई और बहनों के द्वारा होती आ रही है।
- **मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनजातीय त्यौहार:** मडई त्यौहार, भगोरिया त्यौहार, बस्तर का आदिवासी दशहरा, नागाजी का त्यौहार।
- **नागालैंड और मिजोरम के जनजातीय त्यौहार:** 1. भोगली बिहू (जनवरी) – असोम 2. वांगला (नवंबर) – मेघालय और असोम 3. का पम्बलांग नोंगक्रम (नवंबर) – मेघालय झारखंड।
- **ओडिशा के आदिवासी त्यौहार:** कोरापुट जनजाति द्वारा बाली जात्रा। हो, किसान, कोल, भूमिज, उरांव, भुइयां और बिंझाल जनजातियों द्वारा करमा उत्सव।
- कोरापुट की बोंडा जनजाति द्वारा सुमे-गेलीरक उत्सव, बीजा पांडु उत्सव, फूलबनी के कोंधों का केडू त्यौहार। कोरापुट और भुइयां की जनजातियों द्वारा चैता पर्व।

दक्षिणी भारत के जनजातीय त्यौहार:

आंध्र प्रदेश - समक्का त्यौहार और तेलंगाना-कोया जनजाति का मेदराम जात्रा उत्सव।

- 1. ओणम (अगस्त) - केरल 2. पोंगल (जनवरी) - तमिलनाडु 3. उगाडी (मार्च) - आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 4. तवशु (अप्रैल) - केरल और कर्नाटक
- लद्दाख- 'दर्द आर्यन' जनजाति का दर्द आर्यन त्यौहार।

2 भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुआ 'मोहनजोदड़ो' स्थल

चर्चा में क्यों?

पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग के अनुसार सिंध प्रांत में स्थित हड़प्पाई स्थल "मोहनजोदड़ो" को प्राप्त विश्व धरोहर का दर्जा भारी वर्षा और बाढ़ के कारण खतरे में पड़ गया है।

विश्व धरोहर को खतरा:

- 16 से 26 अगस्त, 2022 के दौरान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भीषण वर्षा (779.5 मि.मी.) होने के कारण, मोहनजोदड़ो तथा इसके आस-पास के पुरातात्विक स्थलों को काफी नुकसान हुआ है। ये स्थल हैं- मुनीर क्षेत्र, स्तूप, वृहद स्नानागार आदि।
- पाकिस्तान को यह आशंका है कि मोहनजोदड़ो के महत्त्वपूर्ण स्थलों को विश्व विरासत सूची से हटाया जा सकता है, इसलिये इन स्थलों के संरक्षण और बचाव पर विशेष ध्यान देने

की आवश्यकता है।

- इस स्थल के खंडहरों को वर्ष 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी।
- वर्ष 2007 में ओमान में अरब ओरिक्स अभयारण्य को अवैध शिकार और प्रजातियों के निवास स्थानों के विनाश के कारण और वर्ष 2009 में जर्मनी के ड्रेसडेन में एल्बे घाटी को एल्बे नदी के पार रोड पर ब्रिज के निर्माण के कारण यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया था।

मोहनजोदड़ो के बारे में:

- मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ 'मृतकों का टीला' है। यह एक कांस्ययुगीन शहरी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ऐसा माना जाता रहा है कि इस सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों से हुआ है।
- इस प्रागैतिहासिक स्थल की खोज वर्ष 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। यह स्थल ईंट से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी, शौचालयों, विशाल अन्नागार और स्नानागार एवं स्मारक भवनों के साथ और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कों तथा विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली के लिये प्रसिद्ध है।

- इस स्थल से गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरें, वाद्य यंत्र, चाक पर बने बड़े-बड़े मिट्टी के मटके, तांबे का शीशा, दो पाटों वाली चक्की, माप-तोल के पत्थर, चौपड़ की गोटियां, मिट्टी के कंगन, रंग-बिरंगे मनके आदि मिले हैं।

यूनेस्को:

यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है जिसकी स्थापना 16 नवंबर, 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है।

आगे की राह:

भारी वर्षा, बाढ़ आपदा और मानवीय गतिविधियों ने भारत सहित अन्य देशों के प्राकृतिक स्थलों को क्षतिग्रस्त किया है इसलिए इनके संरक्षण तथा बचाव हेतु सभी देशों को मिलकर एक ठोस रणनीति पर काम करने की आवश्यकता है।

3 भारतीय संगठन ने जीता यूनेस्को इंटरनेशनल लिट्रेसी प्राइज 2022

- कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंससेज को साक्षरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार यूनेस्को इंटरनेशनल लिट्रेसी प्राइज 2022 मिला है। इसके तहत कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को 20 हजार डॉलर, एक मेडल और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है।
- 8 सितंबर, 2022 को अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में आयोजित वैश्विक अवॉर्ड समारोह में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंससेज को यह अवॉर्ड दिया गया है।
- कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंससेज को यह पुरस्कार मिलने से भारत को अब तक 5 बार यह पुरस्कार मिल चुका है और ओड़िशा के किसी संस्था को पहली बार ये पुरस्कार मिला है।
- कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंससेज तीसरा भारतीय गैर-लाभकारी संगठन और पहला आदिवासी आधारित संगठन है जिसे यह अवॉर्ड मिला है। यह भारत के लिए निश्चित रूप से एक गौरव का क्षण है।
- कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंससेज के संस्थापक डॉ अच्युत सामंता ने इस पुरस्कार प्राप्ति की घोषणा अपने संस्थान के कैम्पस में की।
- ओड़िशा के भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस स्कूल दुनिया में आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा आवासीय स्कूल है। इसकी शुरुआत 1993 में एक आवासीय आदिवासी स्कूल के रूप में हुई थी। 26 अगस्त 2017 को यह विश्व का पहला विशिष्ट आदिवासी विश्वविद्यालय बना था।
- इस संस्थान में अधिकतर आदिवासी परिवारों के बच्चों को लाया जाता है। यहां बच्चों को नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई, खाने, रहने, वस्त्रों और रोजगार परक तक बनाने का खर्च संस्थान स्वयं उठाता है। मौजूदा समय में किस में ओड़िशा के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के भी सुदूर क्षेत्रों के आदिवासी परिवारों के बच्चे शिक्षित किए जा रहे हैं। यह उन परिवारों के बच्चे हैं जिनके पास अपनी आजीविका के लिए भी कोई साधन नहीं है।
- यहां बच्चों को मुफ्त में भोजन, अध्ययन सामग्री, वस्त्र सहित वो तमाम जरूरी साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके।
- इस संस्थान के छात्रों ने 2015 में विश्व शांति के लिए सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनाई थी। सबसे बड़ा मानव वाक्य बनाने के साथ इसने गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया था।

1. तेजस मार्क-2 परियोजना

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने तेजस मार्क -2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। सीसीएस ने प्रोटोटाइप, उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के साथ तेजस मार्क-2 लड़ाकू जेट के डिजाइन और विकास के लिए 6,500 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। तेजस एलसीए के उन्नत संस्करण में इसकी उड़ान और लड़ने की क्षमताओं में कई परिवर्धन शामिल होंगे। तेजस 2.098 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास में अधिक शक्तिशाली GEF-414 इंजन से लैस होगा, जो इसे अपनी उड़ान रेंज का विस्तार करने और मौजूदा संस्करण की तुलना में अतिरिक्त पेलोड और हथियार ले जाने की अनुमति देगा। इसके अलावा, नया जेट स्वदेशी रूप से विकसित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे (एईएसए) रडार से भी लैस होगा, जो मौजूदा ईएलटीए के ईएल/एम-2032 मल्टी-मोड रडार से बड़ा अपग्रेड होगा। इस निर्णय से अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के स्वदेशी डिजाइन विकास को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। यह विमान निर्माण के क्षेत्र में आत्मानिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाएगा।

2. विकिरण विरोधी गोलियां

यूक्रेन के जापोरिज्जिया बिजली संयंत्र में एक परमाणु आपदा की आशंका के कारण, यूरोपीय संघ ने आसपास के निवासियों के बीच वितरण के उद्देश्य से 5.5 मिलियन विकिरण विरोधी गोलियों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। विकिरण रिसाव के बाद, रेडियोधर्मी आयोडीन हवा में मिलकर भोजन, पानी और मिट्टी को दूषित करता है। पोटेशियम आयोडाइड (KI) में विकिरण-विरोधी आयोडीन होता है और यह थायरॉयड ग्रंथि में रेडियोधर्मी आयोडीन के अवशोषण और एकत्रीकरण को अवरुद्ध करने में मदद कर सकता है। विकिरण के संपर्क में आने से कुछ घंटे पहले या उसके तुरंत बाद ली गई केआई गोलियां यह सुनिश्चित करती हैं कि दवा में गैर-रेडियोधर्मी आयोडीन थायराइड को पूर्ण बनाने के लिए जल्दी से अवशोषित हो जाए। पोटैशियम आयोडाइड (KI) की गोलियां 'थायरॉयड ब्लॉकिंग' हासिल करने में सहायक होती हैं। केआई गोलियां केवल निवारक हैं और विकिरण द्वारा थायरॉयड ग्रंथि को हुए किसी भी नुकसान को समाप्त नहीं कर सकती हैं तथा 100% सुरक्षा भी प्रदान नहीं करती हैं।

3. हरिद्वार आकांक्षी जिला घोषित

नीति आयोग ने उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में:

इसे नीति आयोग द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। आकांक्षी जिले भारत में वे जिले हैं, जो खराब सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। यह प्रत्येक जिले के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, तत्काल सुधार के लिए आसानी से सुधारने लायक मामलों की पहचान करता है और मासिक आधार पर जिलों की रैंकिंग करके प्रगति को मापता है। आकांक्षी जिलों के रूप में कुल 117 जिलों की पहचान की गई थी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम पांच प्रमुख मानकों के आधार पर जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

1. स्वास्थ्य और पोषण (30%), 2. शिक्षा (30%), 3. कृषि और जल संसाधन (20%), 4. वित्तीय समावेशन और कौशल विकास (10%), 5. इंफ्रास्ट्रक्चर (10%)।

सत्यमेव जयते

NITI Aayog

4. स्टॉकहोम जूनियर जल पुरस्कार

स्टॉकहोम में आयोजित विश्व जल सप्ताह के समारोह में एक कनाडाई छात्रा ने 2022 का स्टॉकहोम जूनियर जल पुरस्कार जीता।

- विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर एक सम्मेलन है।
- स्टॉकहोम जूनियर वाटर एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है जहां 15 से 20 वर्ष की आयु के छात्र प्रमुख जल चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं।
- हानिकारक शैवाल के प्रस्फुटन के उपचार और रोकथाम पर उसके शोध के लिए छात्र को पुरस्कार दिया गया।
- छात्रा ने बायोमैनिपुलेशन की अवधारणा को नियोजित किया और बताया कि जूप्लंकटन की कौन सी प्रजाति शैवाल के उपचार और रोकथाम के लिए सबसे अच्छी है।
- बायोमैनिपुलेशन किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जानबूझ कर किया गया परिवर्तन है जिसमें प्रजातियों को विशेष रूप से शिकारी प्रजातियों को शामिल करना या बाहर करना शामिल है।

5. एचआईपी 65426बी ग्रह की पहली तस्वीर

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, एक्सोप्लैनेट यानी सौर मंडल से परे ग्रह एचआईपी 65426 बी की पहली तस्वीर ली है।

प्रमुख बिंदु:

यह गैस का विशाल ग्रह है, जिसका अर्थ है कि इसकी कोई चट्टानी सतह नहीं है, और रहने योग्य नहीं हो सकता है। यह बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग छह से 12 गुना है। यह संभवत: लगभग 14 मिलियन वर्ष पुराना है, जो इसे 'छोटा बृहस्पति' बनाता है। इसे खगोलविदों ने 2017 में चिली में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी वेरी लार्ज टेलीस्कोप पर स्पेक्ट्रो पोलारिमेट्रिक हाई-कॉन्ट्रास्ट एक्सोप्लैनेट रिसर्च (SPHERE) इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके खोजा था। यह अब तक की लंबी अवरक्त तरंगदैर्घ्य पर ली गई पहली एक्सोप्लैनेट छवि है जो खगोलविदों को किसी ग्रह की चमक की पूरी श्रृंखला का अध्ययन करने की अनुमति देती है।

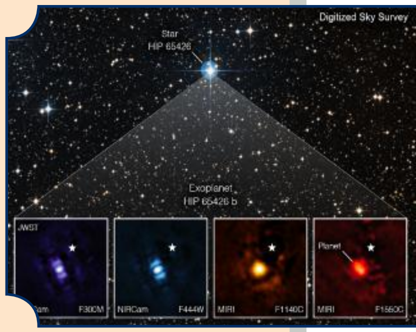

6. निवारक निरोध हिरासत में वृद्धि

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी नवीनतम अपराध आंकड़ों के अनुसार, 1.1 लाख से अधिक लोगों को निवारक हिरासत में रखने के साथ, एक साल पहले की तुलना में 23.7% से अधिक की वृद्धि देखी गई। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या 2017 के बाद से लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निवारक निरोध 2020 में 741 के उच्चतम पर पहुंच गया था जो 2021 में गिरकर 483 हो गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अनुसार, पुलिस को निवारक गिरफ्तारी करने का अधिकार है। निवारक निरोध के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है। इसके तहत गिरफ्तारी में अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त 'गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण' का अधिकार और अनुच्छेद-19 तथा अनुच्छेद-21 के तहत प्रदान की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है।

7. मेनू लेबलिंग मानदंड

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मेनू लेबलिंग मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए 16 खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- आतिथ्य उद्योग के लिए अनिवार्य मेनू लेबलिंग मानदंड 1 जुलाई, 2022 को लागू हुए।
- मेनू लेबलिंग मानदंड केंद्रीय लाइसेंस वाले रेस्तरां और होटल खिलाड़ियों पर लागू होते हैं।
- इसके अलावा, दस या अधिक स्थानों पर आउटलेट चलाने वाली रेस्तरां श्रृंखलाओं को इन मानदंडों का पालन करना होगा।
- ऐसे रेस्तरां के खाद्य उत्पादों को बेचने वाले ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पर खाद्य पदार्थों के मेनू लेबलिंग की घोषणा करनी होगी।
- मानदंडों के तहत, ऑपरेटरों को कैलोरी की संख्या, सेवारत आकार, एलर्जी संबंधी जानकारी और शाकाहारी/मांसाहारी लोगो प्रदर्शित करना होगा।

fssai
Food Saftey and Standards Authority of India

8. विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा सामाजिक सुरक्षा पर नवीनतम रिपोर्ट (वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020 22: एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सहयोगी रिपोर्ट) के अनुसार, केवल 24.4% भारतीय, यहां तक कि बांग्लादेश से भी कम (28.4%), किसी भी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत हैं।

प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट ILO की 'वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2021-22' की सहयोगी है, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्रीय अवलोकन करती है।
- इसके अनुसार मंगोलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में 100% सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क है, जबकि म्यांमार और कंबोडिया में यह संख्या 10% से कम है।
- रिपोर्ट के अनुसार, एशिया प्रशांत क्षेत्र में चार में से तीन श्रम काम के दौरान बीमारी या चोट लगने की स्थिति में सुरक्षित नहीं हैं।

9. इंग्लैंड के नए सम्राट बने "किंग चार्ल्स-III"

11 सितंबर, 2022 को आधिकारिक रूप से 73 वर्षीय किंग चार्ल्स-III को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ-II के निधन के बाद इंग्लैण्ड का नया सम्राट बनाया गया। इनकी ताजपोशी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में की गयी। अब किंग चार्ल्स राष्ट्रमंडल के प्रमुख के अतिरिक्त यू.के. और 14 राष्ट्रमंडल देशों के भी राजा कहलाए जाएंगे। ये किंग चार्ल्स नाम से इंग्लैण्ड के तीसरे सम्राट बने हैं। 4 नवंबर, 1948 को जन्मे किंग चार्ल्स-III का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जार्ज है और ये महारानी एलिजाबेथ-II के सबसे बड़े पुत्र हैं। इंग्लैण्ड के डोरचेस्टर में पाउंडबरी नामक शहर की स्थापना करने वाले चार्ल्स फिलिप एक कुशल चित्रकार भी हैं। वर्तमान में इनकी पत्नी कैमिला पार्कर बाउल्स हैं।

किंग चार्ल्स-I वर्ष 1625 में अपने पिता जेम्स-I के बाद इंग्लैण्ड तथा स्काटलैंड के राजा बने जबकि किंग चार्ल्स-II वर्ष 1660 से 1685 के दौरान ब्रिटेन और आयरलैंड के राजा बने थे।

10. साइबोर्ग कॉकरोच

जापान के वैज्ञानिक संस्थान, रिकेन के क्लस्टर फॉर पायनियरिंग रिसर्च (सीपीआर) के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने एक ऐसी प्रणाली तैयार की है जो साइबोर्ग कॉकरोच बना सकती है, जो कि आंशिक रूप से कीट और आंशिक रूप से मशीन हैं।

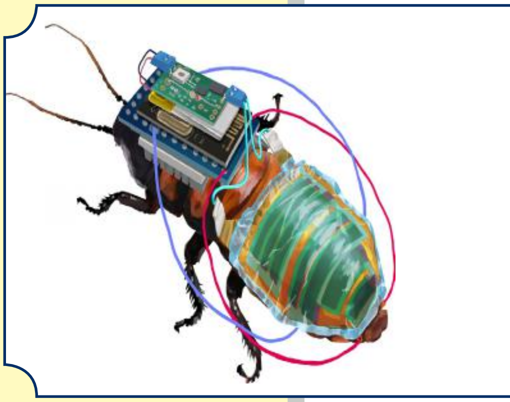

- दावा है कि ये कॉकरोच, जिनकी गतिविधियों को छोटे एकीकृत सर्किट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, शहरी खोज और बचाव, पर्यावरण निगरानी और मनुष्यों के लिए खतरनाक क्षेत्रों के निरीक्षण जैसी प्रक्रियाओं में निगरानी करने में सक्षम होंगे।
- कॉकरोच को छोटे वायरलेस नियंत्रण मॉड्यूल से लैस करके, हैंडलर लंबे समय तक कीट को दूर से नियंत्रित करने में सक्षम होंगे।
- शोधकर्ताओं ने कॉकरोच के पेट के पृष्ठीय हिस्से पर स्थापित एक सुपर पतले 0.004 मिमी सौर सेल मॉड्यूल के साथ इसे शक्ति प्रदान करके, प्रणाली को रिचार्जेबल होने के लिए डिजाइन किया है।

11. डायमंड ट्रॉफी

हाल ही में नीरज चोपड़ा, पुरुषों की डायमंड लीग श्रृंखला के भाला फेंक प्रतियोगिता में प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने।

प्रमुख बिंदु:

- टोक्यो के ओलंपिक चैंपियन ने पोडियम के शीर्ष पर आने के लिए 88.44 मीटर का थ्रो किया।
- चेक गणराज्य के ओलंपिक रजत पदक विजेता जैकब वाडलेज्च 86.94 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे।
- डायमंड लीग में चैंपियनशिप-शैली के मॉडल का अनुसरण करते हुए 32 डायमंड डिसिप्लिन शामिल हैं।
- एथलीट अपने संबंधित विषयों के फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए 13-श्रृंखला की बैठक में अंक अर्जित करते हैं।

12. सौर ऊर्जा से चलने वाला मानवरहित हवाई वाहन

चीन ने अपने पहले पूर्ण सौर-संचालित मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो महीनों तक उड़ सकता है और यदि आवश्यक हो तो उपग्रह के रूप में भी कार्य कर सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- Qimingxing-50, 50 मीटर के पंखों के साथ, एक उच्च ऊंचाई वाला ड्रोन है जो उच्च ऊंचाई वाले हवाई टोही में सक्षम है, जंगल की आग का आकलन कर सकता है और संचार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- यह तकनीक अंतरिक्ष और समुद्र में चीनी सुरक्षा को मजबूत करेगी। इसका उपयोग अक्षय ऊर्जा, नई सामग्री और वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जा सकता है।
- इसे 'उच्च ऊंचाई वाले प्लेटफार्म स्टेशन' या छद्म उपग्रह के रूप में भी जाना जाता है।

13. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई)

पीएमएसवाई ने हाल ही में अपनी दूसरी सफल वर्षगांठ पूरी की है।

कार्यान्वयन एजेंसी: मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना को लागू कर रही है।

इस योजना के तहत मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है। पिछले 2 वर्षों में मत्स्य विकास दर, 2019-20 से 2021-22 तक 14.3% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाती है। इसके अलावा, मछली उत्पादन 2019-20 के दौरान 141.64 लाख टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। इसे वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024 25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। मत्स्य पालन क्षेत्र में PMMSY का मुख्य आदर्श वाक्य 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' है।

14. ICOMOS का होयसल मंदिर का दौरा

स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (ICOMOS) के एक प्रतिनिधि सहित एक विशेषज्ञ टीम और अधिकारियों ने बेलूर, हलेबिड और सोमनाथपुर में होयसल मंदिरों का दौरा किया।

होयसल वास्तुकला:

- यह 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के शासन के तहत विकसित हिंदू मंदिर वास्तुकला में निर्माण शैली है, जिसे आज कर्नाटक के रूप में जाना जाता है।
- यह भगवान शिव या भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि जैन मंदिर तीर्थंकरों को समर्पित हैं जो आध्यात्मिक शिक्षक थे।
- होयसल मंदिरों को वेसर कहा जाता है क्योंकि उनकी अनूठी शैली द्रविड़ और नागर शैलियों के बीच लगती है।
- होयसल वास्तुकला में खुले और बंद दोनों मंडप पाए जाते हैं। होयसल मंदिरों के मंडपों में गोलाकार स्तंभ हैं।
- ICOMOS मुख्यालय फ्रांस के चेरेंटन-ले-पोंट, फ्रांस में है। इसके स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी।

15. दारा शिकोह की मज्म उल-बहरैन पुस्तक के अरबी अनुवाद का विमोचन

- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दारा शिकोह के मज्म उल-बहरैन के अनूदित अरबी संस्करण का विमोचन किया। पुस्तक के अनुवादक अमर हसन हैं। मज्म उल-बहरैन पुस्तक धर्मों के बीच एकता और विविधता के रहस्योद्घाटन के लिए समर्पित थी।
- दारा शिकोह को एक उदार मुसलमान के रूप में माना जाता है जिन्होंने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानताएं खोजने की कोशिश की। वह शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे।
- उन्हें भारत में अंतरधार्मिक समझ के लिए अकादमिक आंदोलन के अग्रणी के रूप में जाना जाता है।
- उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण कृतियाँ मज्म उल-बहरैन (दो महासागरों का मिलन) और सिर्र-ए-अकबर (महान रहस्य) है जो हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए समर्पित थी।
- उन्होंने उपनिषदों और हिंदू धर्म और आध्यात्मिकता के अन्य महत्त्वपूर्ण स्रोतों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. सर्वावेक (CERVAVAC), सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमावायरस (क्यूएचपीवी) वैक्सीन है।
2. सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (सीसीआरएएस) ने स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन (स्पार्क) योजना विकसित करके एक अनूठी पहल की शुरुआत की है।
3. सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी (सीएसए) के सहयोग से भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) ने हाल ही में 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास 'सिनर्जी' का आयोजन किया।
4. दक्षिण अफ्रीकी अदालत ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वाइल्ड तटों पर तेल और गैस की खोज करने से प्रतिबंधित कर दिया है।
5. उत्तरी श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप से दूर पुंगुदुतिवु में समुद्री ककड़ी फार्म में निवेश करने वाली चीनी फर्म, स्थानीय मछुआरों ने अपनी आजीविका, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और भूमि पर इसके संभावित प्रभाव पर चिंता जताई है।
6. सिंगापुर की एक फर्म द्वारा समर्थित दो वर्षीय स्टार्ट-अप ब्लू एनर्जी मोटर्स ने पुणे के पास चाकन में भारत के पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया।
7. इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) द्वारा डिजाइन और विकसित, आईएडी का थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (टीईआरएलएस) से रोहिणी परिज्ञापी रॉकेट में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
8. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने श्रीलंका के साथ चार साल के 2.9 बिलियन अमेरिकी डालर के बेलआउट पैकेज पर एक प्रारंभिक समझौते को मंजूरी दी।
9. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने हाल ही में नई राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की।
10. केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री ने यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल एवं यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, दक्षिण एशिया द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज समिट में भाग लिया।
11. वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने हाल ही में अपनी यूएसए यात्रा के दौरान सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र में यूएस स्टार्टअप सेतु कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
12. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 और संबंधित नियम 1 सितंबर 2022 से लागू हुआ।
13. हाल ही में, हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने ऑपरेशन गियर बॉक्स शुरू किया और कोलकाता बंदरगाह से 39.5 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया।
14. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) ने संयुक्त रूप से वैश्विक पर्यावरण सुविधा लघु अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है।
15. हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
16. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान समरकंद में 15 और 16 सितंबर, 2022 को आयोजित किया जाएगा।
17. एक नए शोध से पता चला है कि पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 की वृद्धि कई जलवायु टिपिंग बिंदुओं को ट्रिगर करेगी।
18. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार, भारत 2021 की अंतिम तिमाही में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
19. सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठतम जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है।
20. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal – NGT) ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के मानदंडों का उल्लंघन करने के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार पर 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
21. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य (Night Sky Sanctuary) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

तारागिरी

1. चर्चा मे क्यों?

- प्रोजेक्ट 17(ए) के तहत युद्धपोत तारागिरी, 11 सितंबर 2022 को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई से लॉन्च किया गया।

2. 'तारागिरी' के बारे में:

- तारागिरी का नाम उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला पर रखा गया है।
- प्रोजेक्ट 17(ए) युद्धपोत का यह पांचवां जहाज है।
- ये जहाज प्रोजेक्ट-17 फ्रिगेट्स (शिवालिक वर्ग) के उन्नत संस्करण हैं।
- जहाज का प्रक्षेपण भार लगभग 3510 टन है।
- जहाज निर्माण के दौरान एकीकृत निर्माण पद्धति का प्रयोग हुआ है।
- इसमें विभिन्न ज्योग्राफिकल लोकेशन में हल (HULL) ब्लॉकों का निर्माण और एमडीएल में स्लिपवे (SLIPWAY) पर एकीकरण शामिल है।
- जहाज को भारतीय नौसेना के इन-हाउस डिजाइन संगठन, ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है।

3. तारागिरी में शामिल होगा:

- अत्याधुनिक हथियार
- सेंसर
- उन्नत सूचना प्रणाली
- इंटिग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम
- विश्व स्तरीय मॉड्यूलर लिविंग स्पेस
- परिष्कृत पावर वितरण प्रणाली
- अन्य उन्नत सुविधाओं की व्यवस्था
- इसे सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा।
- **वायु रक्षा क्षमता:** दुश्मन के विमानों से खतरे का मुकाबला करने हेतु इसे डिजाइन किया गया है। इसमें जहाज-रोधी क्रूज मिसाइलें ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के चारों ओर घूमेंगी।
- दो 30 मिमी रैपिड-फायर बंदूकें जहाज को निकट-रक्षा क्षमता प्रदान करेंगी।
- एसआरजीएम (सुपर रैपिड गन माउंट) बंदूक इसे प्रभावी नौसैनिक गनफायर सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।

4. प्रोजेक्ट-17 (ए) के बारे में:

- प्रोजेक्ट-17 अल्फा फ्रिगेट्स (P-17A) को भारतीय नौसेना द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था।
- इस परियोजना को 7 स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट की श्रृंखला बनाने के लिए लॉन्च किया गया था।
- इसका निर्माण दो कंपनियां मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा किया जायेगा।
- P-17A कार्यक्रम के तहत जिन 5 जहाजों को लॉन्च किया गया है उनमें नीलगिरि, उदयगिरि, तारागिरी, हिमगिरि और दूनागिरी शामिल हैं।
- 'आत्मनिर्भर भारत' को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट 17(ए) जहाजों के, उपकरणों के निर्माण संबंधी 75% ऑर्डर एमएसएमई सहित स्वदेशी फर्मों को दिए जा रहे हैं।

5. जहाज निर्माण उद्योग के लाभ:

- एक 'रणनीतिक उद्योग' जो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ-साथ औद्योगीकरण और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह देश की महासागर आधारित 'नीली अर्थव्यवस्था' को बढ़ावा देगा।
- 'नागरिक-सैन्य एकीकरण' का अर्थ है कि आधुनिक बुनियादी ढांचे और नागरिक शिपयार्ड के कुशल जनशक्ति का उपयोग नौसेना कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है।

6. भारतीय जहाज निर्माण उद्योग के लिए चुनौतियां:

- मुख्य चुनौतियों में वैधानिक भार होना, लेवी, बैंक गारंटी, कार्यशील पूंजी और शैक्षणिक संस्थानों का अभाव शामिल है।

7. भारतीय जहाज निर्माण उद्योग के लिए अवसर:

1. कम श्रम लागत
2. मजबूत घरेलू मांग
3. कुछ घटकों के लिए उद्योग के बुनियादी ढांचे का समर्थन करना
4. लंबी तटरेखा
5. प्रतिस्थापन की मांग
6. नए भवन की कीमतें

भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व

1. चर्चा में क्यों?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने हानले, लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की।

2. हानले डार्क स्काई रिजर्व के बारे में:

- हानले, समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
- यह दूरबीनों को होस्ट (Host) करता है जिसे खगोलीय प्रेक्षणों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है।
- प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हानले में स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य का भाग होगा।

3. डार्क स्काई रिजर्व के बारे में:

- डार्क स्काई रिजर्व सार्वजनिक या निजी संरक्षित क्षेत्र है जो एक विशिष्ट तारों वाली कृत्रिम रात जैसा वातावरण होता है जिसका निर्माण प्रकाश प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है।
- इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन (आईडीएसए) की वेबसाइट के अनुसार, न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने वाला कोर क्षेत्र में शामिल है।
- आकाश की गुणवत्ता और प्राकृतिक अंधेरे के लिए एक परिधीय क्षेत्र- जो कोर में डार्क स्काई संरक्षण का समर्थन करता है।

4. कोई साइट डार्क स्काई रिजर्व कैसे बनती है?

- आईडीएसए के प्रमाणन के लिए व्यक्ति या समूह किसी साइट को नामांकित कर सकते हैं जिसमें इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क, समुदाय, रिजर्व, अभयारण्य और अर्बन नाइट स्काई प्लेस शामिल हैं।
- प्रमाणन प्रक्रिया ठीक वैसे ही है जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल टैग या बायोस्फीयर रिजर्व हेतु मान्यता देता है।
- 2001 से जनवरी 2022 के बीच, 195 साइटों को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई स्थानों के रूप में मान्यता दी गई है।

5. डार्क स्काई प्लेस के लिए आईडीएसए मानदंड:

- यह सार्वजनिक या निजी दोनों स्वामित्व में हो सकता है।
- यह आंशिक रूप से या पूरी तरह से जनता के लिए सुलभ है।
- यह क्षेत्र वैज्ञानिक, प्राकृतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, या सार्वजनिक आनंद हेतु कानूनी रूप से संरक्षित है।
- यह मुख्य क्षेत्र समुदायों और इसके आसपास के शहरों के सापेक्ष, एक असाधारण डार्क स्काई संसाधन प्रदान करता है।
- यह पार्क, रिजर्व या अभयारण्य को डार्क स्काई ब्राईटनेस प्रदान करता है।

6. भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कौन विकसित कर रहा है?

- लद्दाख देश के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना का नेतृत्व कर रहा है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) बेंगलुरू के विशेषज्ञ इसको विकसित करने में वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं।
- इस पर औपचारिक निर्णय आईआईए बेंगलुरु, लद्दाख प्रशासन और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से हुआ।

7. परियोजना के लिए लद्दाख को क्यों चुना गया?

- लद्दाख समुद्र तल से लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक अनोखा ठंडा मरुस्थल है जहां ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं।
- सर्दियों के समय वहां का न्यूनतम तापमान शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है जिससे अधिकतर भू-भाग रहने योग्य नही होता है।
- अधिक ठंडी, कम जनसँख्या घनत्व आदि इसे दीर्घकालिक खगोलीय वेधशालाओं और डार्क स्काई वाले स्थानों के लिए आदर्श स्थान बनाता है।
- प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व का प्राथमिक उद्देश्य स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल दृष्टि से खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- यह ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा-रे (Ray) दूरबीनों के लिए, दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक होगा।

पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने हेतु रेलवे की भूमि नीति

1. चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए (कार्गो संबंधी गतिविधियों, जन उपयोगिताओं और रेलवे के विशेष इस्तेमाल हेतु) रेलवे की भूमि नीति को संशोधित करने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

2. इसका प्रभाव:

- इससे रेलवे को और ज्यादा कार्गो आकर्षित करने में मदद मिलेगी, माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ेगी और इससे इस उद्योग की लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी।
- इससे रेलवे को अधिक राजस्व मिलेगा।
- ये पीएम गति शक्ति कार्यक्रम में सोची गई जन उपयोगिताओं के लिए मंजूरियों को सरलीकृत करेगा।
- इससे निम्न जन उपयोगिताओं के एकीकृत तरीके से विकास में मदद मिलेगी–
  - » बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति
  - » दूरसंचार केबल, सीवेज निपटान
  - » नालियां, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी)
  - » पाइपलाइन, सड़क, फ्लाईओवर
  - » बस टर्मिनल, क्षेत्रीय रेल परिवहन, शहरी परिवहन।
- इस नीतिगत संशोधन से लगभग 1.2 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

3. लाभ:

- इस नीतिगत संशोधन से लगभग 1.2 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

4. वित्तीय नतीजे:

- इसका कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।
- भूमि पट्टे पर देने की नीति को उदार बनाने से सभी हितधारकों/सेवा प्रदाताओं/ऑपरेटरों के लिए ज्यादा कार्गो संबंधी सुविधाएं स्थापित करने के रास्ते खुलेंगे।
- रेलवे के लिए अतिरिक्त कार्गो यातायात एवं माल ढुलाई राजस्व पैदा करने में उनकी भागीदारी की राह भी बनेगी।

6. कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य::

- कैबिनेट की मंजूरी के 90 दिनों के भीतर व्यापक नीतिगत दस्तावेज तैयार और लागू किया जाएगा।
- पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के तहत सोची गई जन उपयोगिताओं की स्थापना के लिए मंजूरियों को सरल किया जाएगा।
- अगले पांच वर्षों में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।

5. विवरण:

- रेलवे की ये संशोधित भूमि नीति बुनियादी ढांचे और ज्यादा कार्गो टर्मिनलों के एकीकृत विकास को सक्षम करेगी।
- ये नीति, भूमि के प्रति-वर्ष बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष तक की अवधि हेतु, कार्गो से संबंधित गतिविधियों के लिए रेलवे की भूमि को लंबी अवधि के पट्टे पर प्रदान करती है।
- कार्गो टर्मिनलों के लिए रेलवे भूमि का उपयोग कर रही मौजूदा संस्थाओं के पास, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद नई नीति व्यवस्था अपनाने का विकल्प होगा।
- अगले पांच वर्षों में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और लगभग 1.2 लाख रोजगार सृजित होंगे।
- इससे माल ढुलाई में रेल की हिस्सेदारी बढ़ेगी और देश में कुल लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी।
- ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (ओएफसी) और अन्य छोटे व्यास वाली भूमिगत उपयोगिताओं के लिए, रेलवे ट्रैक पार करने के लिए 1000 रुपये का एकमुश्त शुल्क लिया जाएगा।
- इस नीति में रेलवे की जमीन पर सोलर प्लांट लगाने के लिए नाममात्र की लागत पर रेलवे की जमीन के इस्तेमाल का प्रावधान है।
- ये नीति प्रति वर्ष 1 रुपया प्रति वर्गमीटर के मामूली वार्षिक शुल्क पर रेलवे भूमि पर सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्रोत्साहित करती है।

1. चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना- पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) को मंजूरी दी है ।

2. पीएम श्री स्कूलों के बारे में:

- यह देश भर के 14500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित करने के लिए एक नई योजना होगी।
- पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों का प्रदर्शन करेंगे।
- पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेंगे।
- 21 वीं सदी के महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण-विकसित व्यक्तियों का निर्माण और उनका पोषण करने का प्रयास करेंगे।
- पीएम श्री स्कूलों की योजना (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया – उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा।
- परियोजना की कुल लागत 27360 करोड़ रुपये है, जिसमें वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 18128 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।

3. प्रमुख विशेषताएं:

- पीएम श्री स्कूल एक समान, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेंगे
- यह विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरतों और बच्चों की विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखेगी ।
- यह एनईपी 2020 के विजन के अनुरूप उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाएगी।
- पीएम श्री स्कूल मार्गदर्शन प्रदान करके अपने संबंधित क्षेत्रों के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करेंगे।
- निम्नलिखित पर्यावरण के अनुकूल पहलुओं को शामिल करते हुए पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा:
  - » सौर पैनल और एलईडी लाइट,
  - » प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान,
  - » अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त,
  - » जल संरक्षण और जल संचयन,
  - » पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित परंपराओं/ प्रथाओं का अध्ययन,
  - » जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैकथॉन
  - » जैविक जीवन शैली को अपनाने के लिए जागरूकता

4. योजना की प्रमुख विशेषताएं:

- गुणवत्ता और नवाचार
- आरटीई अधिनियम के तहत लाभार्थी उन्मुख पात्रता वाले 100% पीएम श्री स्कूलों को विज्ञान और गणित के किट मिलेंगे।
- वार्षिक अनुदान।
- बालवाटिका और मूलभूत साक्षरता और प्रारंभिक बचपन की देखभाल व शिक्षा।
- लड़कियों और सीडब्ल्यूएसएन के लिए सुरक्षित एवं उपयुक्त बुनियादी ढांचे के प्रावधान सहित समानता और समावेशा।
- छात्रों के लिए प्रस्तावित विषयों के चुनाव में लचीले रुख को प्रोत्साहित करना।
- शिक्षकों और छात्रों के बीच भाषा की बाधाओं को पाटने में मदद करने के लिए तकनीकी उपायों का उपयोग करते हुए मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रोत्साहित करना।
- मौजूदा अवसंरचना को मजबूत करना
- ग्रीन स्कूल पहल

पीएम श्री स्कूल

5. पीएम श्री स्कूल का गुणवत्ता आश्वासन

- एनईपी 2020 का प्रदर्शन।
- नामांकन और सीखने की प्रक्रिया में प्रगति पर निगरानी के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्री।
- प्रत्येक बच्चे के सीखने के स्तर में सुधार करके राज्य और राष्ट्रीय औसत से ऊपर के स्तर को प्राप्त करना।
- मध्यम श्रेणी के प्रत्येक छात्र, अत्याधुनिक और 21वीं सदी के कौशल से अवगत/उन्मुख।
- माध्यमिक कक्षा का प्रत्येक छात्र कम से कम एक कौशल के साथ उत्तीर्ण होता है।
- हर बच्चे के लिए खेल, कला, आईसीटी।
- इन स्कूलों को बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवंत स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

6. लाभार्थी:

- इस योजना से 18 लाख से अधिक छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके अलावा पीएम श्री स्कूलों के आसपास के स्कूलों पर भी मार्गदर्शन और सहयोग के माध्यम से प्रभाव पड़ेगा।

भारत का राष्ट्रीय पोर्टल

1. पोर्टल के बारे में:

- केंद्र, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर कई सरकारी संस्थाएं ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रही हैं जिससे नागरिकों का जीवन आसान तो हुआ ही है, पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ी है।
- ये सेवाएं कई वेबसाइटों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
- इन सेवाओं को एक अच्छी तरह से वर्गीकृत और खोज योग्य इंटरफेस में सूचीबद्ध करने के लिए, राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल को भारत पोर्टल परियोजना के दायरे में विकसित किया गया है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।
- एनआईसी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक अग्रणी आईसीटी संगठन है।
- इस पोर्टल का उद्देश्य एक मंच के तहत विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं की सूची बनाना, सामग्री संरचना और सेवाओं के वर्गीकरण के संबंध में मानकीकरण सुनिश्चित करना है।

2. इतिहास:

- इस पोर्टल का विकास सरकार की राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना के रूप में किया गया है।
- यह पोर्टल नवंबर 2005 में शुरू किया गया था।

3. विजन:

- इस पोर्टल को बनाने का उद्देश्य नागरिकों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सूचना और सेवाओं तक एकल बिंदु अभिगम्यता प्रदान करना है।
- इस पोर्टल के माध्यम से भारत और इसके विभिन्न पहलुओं के विषय में सूचना का एक व्यापक, शुद्ध, विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने का प्रयास किया गया है।
- भारत सरकार के अन्य पोर्टलों/वेबसाइटों के लिए इसमें विभिन्न लिंक्स दिए गए हैं।

4. पोर्टल प्रबंधन:

- इस पोर्टल की सामग्री का प्रबंधन राष्ट्रीय पोर्टल सचिवालय के सामग्री प्रबंधन दल द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाता है।
- प्रबंधन दल का प्रयास इस पोर्टल की विषय वस्तु विस्तार क्षेत्र, अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी को एक नियमित आधार पर समृद्ध और भरपूर बनाने का है।

5. श्रेणियाँ:

- शिक्षा और अधिगम
- स्वास्थ्य और कल्याण
- बिजली, पानी और स्थानीय सेवाएं
- मुद्रा और कर
- रोजगार
- न्याय, कानून और शिकायत
- यात्रा एवं पर्यटन
- व्यवसाय तथा स्वरोजगार
- जन्म, मृत्यु, विवाह और बाल देखरेख
- पेंशन और लाभ
- परिवहन और आधारिक संरचना
- नागरिकता, वीजा और पासपोर्ट
- कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण
- विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार
- युवा, खेल और संस्कृति

5. वेबसाइट में प्रयुक्त महत्वपूर्ण संक्षिप्ति:

BRAF: Bio-informatics Resource and Application facility

CARE: Centre for Advanced Computing Research and Education

G2B: Government-to-Business

G2C: Government-to-Citizen

G2E: Government-to-Employees

C-DAC: Centre for Development of Advanced Computing

CEG: Centre for e-Governance

CMS: Content Management System

DEA: Department of Economic Affairs

DOEACC: Department of Electronics Accredited Computer Course

FIPB: Foreign Investment Promotion Board

हैदराबाद मुक्ति दिवस

1. चर्चा में क्यों?

संस्कृति मंत्रालय 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद मुक्ति दिवस के वर्षभर चलने वाले स्मरण उत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन करेगा। भारत सरकार ने 17 सितंबर, 2022 से 17 सितंबर, 2023 तक चलने वाले 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' के वर्षभर लंबे स्मृति उत्सव को मंजूरी दी है।

2. उत्सव का उद्देश्य:

- वर्षभर चलने वाले इस स्मृति उत्सव का उद्देश्य उन सभी को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने संस्थान की मुक्ति और भारत में इसके विलय के लिए अपनी जान कुर्बान की थी।

3. इतिहास:

- भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने के एक साल से भी अधिक समय बाद, 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजाम के शासन से आजाद हुआ।
- अंग्रेजों के खिलाफ रामजी गोंड के संघर्ष समेत स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास संघर्ष की कहानियों से भरा पड़ा है। जैसे कोमाराम भीम की लड़ाई, 1857 में तुर्रेबाज खान की बहादुरी की कहानी, जो हैदराबाद शहर के कोठी में ब्रिटिश रेजिडेंट कमिश्नर के घर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते थे।
- भारत की आजादी के बाद यह संघर्ष मुखर हो गया। वंदे मातरम् गाते हुए लोगों की अपने आप बढ़ती भागीदारी और संस्थान के भारतीय संघ में विलय की मांग के साथ, यह संघर्ष एक विशाल जन आंदोलन में तब्दील हो गया।

4. सरदार पटेल की भूमिका:

- हैदराबाद की मुक्ति भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के ऑपरेशन पोलो के तहत त्वरित और समय पर की गई कार्यवाही के कारण संभव हुई थी।

5. ऑपरेशन पोलो के बारे में:

- ऑपरेशन पोलो भारत के तत्कालीन स्वतंत्र डोमिनियन द्वारा हैदराबाद राज्य के खिलाफ सितंबर 1948 'पुलिस कार्यवाही' का कोड नाम था।
- यह एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत पर कब्जा कर लिया था।
- भारत ने गृह मंत्री सरदार पटेल के निर्देश पर हैदराबाद में ऑपरेशन को अंजाम दिया।
- ऑपरेशन 13 सितंबर, 1948 को शुरू किया गया था और 5 दिन बाद 17 सितंबर को पूरा हुआ।
- सरदार पटेल को राज्य के भौगोलिक स्थिति के कारण हैदराबाद के निजाम के इरादों पर संदेह था।
- हैदराबाद राज्य भारत के मध्य में था, जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ था।
- निजाम को भारत के साथ संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसका अर्थ था कि उसके मन में अन्य विचार थे।
- परिणामस्वरूप, सरदार पटेल ने निजाम के इरादे जानने के लिए एक जांच दल का गठन किया।
- हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान के साथ दोस्ताना था परन्तु भारत के खिलाफ था।
- भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की सेना के निजाम के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने के बाद 18 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो को समाप्त कर दिया गया था।

6. मुक्त किए गए क्षेत्र:

निजाम के अधीन हैदराबाद राज्य में शामिल थे:

- आज का पूरा तेलंगाना।
- महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र जिसमें औरंगा. बाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद, परभणी आदि।
- आज के कर्नाटक के कलबुर्गी, बेल्लारी, रायचूर, यादगिर, कोप्पल, विजयनगर और बीदर जिले।

7. मान्यता:

- महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारें आधिकारिक तौर पर 17 सितंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाती हैं।
- केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। संस्कृति मंत्रालय ने हैदराबाद में उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था।

1. चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गाँधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का आरम्भ किया गया है।

2. योजना के विषय में:

- यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा 9 सितम्बर 2022 को राजस्थान में लागू कर दिया गया है।
- इस योजना का नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार है।
- इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है।
- वर्ष में 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार देकर पात्र परिवार की आजीविका को सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

3. कौन होंगे पात्र:

- आवेदक राजस्थान प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब तथा जरूरतमंद इच्छित परिवार के लोग इस योजना के पात्र होंगे। विशेष रूप से महामारी के दौरान अपनी आजीविका खो चुके गरीब और निराश्रित लोगों को वरीयता दी जाएगी।

4. इस योजना के अंतर्गत कौन से कार्य किये जा सकेंगे?

पर्यावरण संरक्षण कार्य:

- सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करना तथा पौधों का संरक्षण करना ।
- उद्यान संधारण तथा उद्यानिकी से सम्बन्धी काम।
- नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करना।

जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य:

- जल निकायें निकालना, सफाई करना, सुधार सम्बन्धी काम करना।
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, तथा जल स्त्रोतों के मरम्मत का कार्य।

स्वच्छता सम्बंधित कार्य:

- ठोस कचरा प्रबंधन
- नगरीय अपशिष्ट के घर-घर संग्रहण एवं पृथक्कीकरण हेतु श्रमिक कार्य।
- डम्पिंग साइट/एम.आर.एफ सेन्टर पर कचरे का पृथक्कीकरण का कार्य।
- सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय व मूत्रालय, नाला/नालियों की सफाई व रखरखाव।
- संपत्ति विरूपण रोकना, अतिक्रमण हटाने से सम्बन्धी कार्य।

कन्वर्जेन्स कार्य:

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) व मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स।
- केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स।

सेवा सम्बन्धी कार्य:

- कायन हाउस/गौशाला में श्रमिक कार्य।
- नगरीय निकाय कार्यालयों में मल्टी टास्क सर्विसेज के कार्य जैसे रिकॉर्ड कीपिंग आदि।
- हेरिटेज संरक्षण से सम्बंधित कार्य करना।

अन्य कार्य:

- नगरीय निकायों व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा/चारदीवारी/गार्ड इत्यादि से सम्बंधित कार्य।
- नगरीय क्षेत्र में पार्किंग विकास व पार्किंग स्थल के प्रबंधन के कार्य।

इंदिरा गाँधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम

5. इस योजना का लाभ:

- आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, रोजगार न मिल पाने वाले असहाय परिवार, बेरोजगार परिवारो को आय का साधन।
- राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले स्ट्रीट वेंडर्स, ढाबा या रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग, व अन्य वर्ग के लोगों के लिए यह योजना आरम्भ की है। यह योजना शहरी गरीबों के कोविड-19 के बाद की स्थिति को सुधारने का प्रयास करेगी।
- यह योजना शहरी गरीब की आजीविका में सुधार कर उन्हें आर्थिक रूप सशक्त बनाएगा ।
- इस योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य सतत विकास, स्वच्छता, सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

6. योजना से सम्बद्ध चिंताएं:

- वर्तमान समय में राज्य राजकोषीय घाटे में चल रहे हैं ऐसे में यह योजना उनके वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करेगी।
- लोक-लुभावन वाद का सिद्धांत स्थायी नहीं है तथा इसका प्रभाव श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है।
- इस योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन है इस स्थिति में डाटा संरक्षण की चिंताए भी होंगी।

प्रारम्भिक परीक्षा आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. इंटरपोल द्वारा जारी 'पर्पल नोटिस' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर और आसन्न खतरे का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया की चेतावनी देने के लिए जारी किया जाता है।
2. इसे पिछले साल डेटिंग एप्लिकेशन के जरिए निवेश धोखाधड़ी के खिलाफ चेतावनी देने के लिए जारी किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह तीस्ता और महानंदा नदी के बीच स्थित है।
2. पक्षियों और उनके आवास के संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे 'महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र' के रूप में नामित किया गया है।
3. रूफस-नेक्ड हॉर्नबिल पक्षियों को देखने वालों के लिए मुख्य आकर्षणों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

3. वित्तीय अनुबंधों के लिए बेंचमार्क दरों, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (SOFR) और लंदन इंटर-बैंक ऑफर रेट (LIBOR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. SOFR सुरक्षित इंटरबैंक ओवरनाइट ब्याज दर पर आधारित है और LIBOR लंदन में अग्रणी बैंकों द्वारा प्रस्तुत अनुमानों से गणना की गई ब्याज दर औसत पर आधारित है।
2. LIBOR, SOFR का प्रतिस्थापन (विकल्प) है।
3. LIBOR फारवर्ड लुकिंग (अग्रगामी) है जबकि SOFR बैकवर्ड लुकिंग (पश्चगामी) है।
4. SOFR ओवरनाइट रेट है जबकि LIBOR की अवधि लंबी है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

4. मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका वैज्ञानिक नाम 'डैनॉस प्लेक्सीपस' है।
2. IUCN रेड लिस्ट के तहत इसकी आधिकारिक स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है।
3. यह मौसमी प्रवास के लिए प्रसिद्ध है।
4. मिल्कवीड निवास का विनाश, इसकी जनसंख्या में गिरावट में योगदान करने वाले कारकों में से एक है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

5. निम्नलिखित स्वदेशी मार्शल आर्ट और उनके मूल राज्यों पर विचार कीजिए:

मार्शल आर्ट	:	**मूल राज्य**
1. कलारीपयट्टू	:	तमिलनाडु
2. गतका	:	पंजाब
3. थांग-ता	:	मिजोरम

उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

6. STARS परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है।

2. इसे विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से लॉन्च किया गया है।
3. इस परियोजना में 10 राज्य शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

7. निम्नलिखित प्रकार के फैटी एसिडों पर विचार कीजिए:

1. मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड
2. पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड
3. सैचुरेटेड फैटी एसिड

उपर्युक्त में से किस प्रकार का/के फैटी एसिड ट्रांस वसा का गठन करता/करते है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

8. निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों और उनके मुख्य प्रावधानों पर विचार कीजिए:

संवैधानिक संशोधन	:	**मुख्य प्रावधान**
1. 77वां	:	अनुच्छेद 16(4A) समाविष्ट किया गया
2. 81वां	:	अनुच्छेद 16(4B) समाविष्ट किया गया
3. 82वां	:	अनुच्छेद 332 में एक शर्त डाली गयी
4. 85वां	:	पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान

उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

9. भारत में मानहानि कानूनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मानहानि, दीवानी अपकृत्य होने के साथ-साथ आपराधिक अपकृत्य भी हो सकती है।
2. आपराधिक मानहानि को विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 के तहत परिभाषित किया गया है।
3. आईपीसी की धारा 499 में आपराधिक मानहानि की सजा का प्रावधान है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

10. निम्नलिखित दर्रो और उन स्थानों पर विचार कीजिए जिन्हें ये दर्रे लिंक करते हैं:

1.	बनिहाल दर्रा	:	लद्दाख में कारगिल के साथ लेह
2.	लिपु लेख दर्रा	:	कश्मीर घाटी के साथ बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाका
3.	नाथू ला दर्रा	:	चीन के स्वायत्त क्षेत्र, तिब्बत के साथ सिक्किम
4.	रोहतांग दर्रा	:	हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटियों के साथ कुल्लू घाटी

उपर्युक्त में से कौन सा/से युग्म सही सुमेलित **नहीं** है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 3 और 4

11. निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट/रिपोर्टें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है/हैं?

1. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट।
2. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट।
3. भारतीय बैंकिंग उद्योग रिपोर्ट।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

12. 'रूथेनियम-106' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह यूरेनियम 235 के संलयन से उत्पन्न होता है।

2. इसे 'ओकुलर ट्यूमर' में एक थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
3. यह खर्च किए गए परमाणु ईंधन के अवशेषों में पाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

13. भारत में 'ई-कोर्ट' परियोजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 2019 में गठित एक ई-समिति की सिफारिशों पर इस परियोजना की कल्पना की गई थी।
2. इस परियोजना को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय है।
2. भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है जो राष्ट्रीय बाघ जनगणना का संचालन करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

15. ढोकरा कला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ''ढोकरा'' शब्द का नाम, ढोकरा डामर जनजातियों के नाम पर रखा गया है, जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पारंपरिक धातुकार हैं।
2. यह फेरस मेटल कास्टिंग स्टाइल है जो सिरे-पर्ड्यू तकनीक का उपयोग करती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

16. निम्नलिखित में से कौन से ASHAs के प्राथमिक कर्तव्य हैं?

1. यह जन्म की तैयारियों, सुरक्षित प्रसव के महत्व, स्तनपान और पूरक आहार, टीकाकरण, गर्भनिरोधक और आम संक्रमण की रोकथाम पर महिलाओं को परामर्श देती है।
2. ASHA, स्वास्थ्य के निर्धारकों जैसे पोषण, बुनियादी स्वच्छता और स्वास्थ्यकर प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और समुदायों को जानकारी प्रदान करने के लिए कदम उठाती है।
3. यह ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति के साथ मिलकर एक व्यापक ग्राम स्वास्थ्य योजना विकसित करने के लिए काम करती है।
4. ASHA छोटी-मोटी बीमारियों जैसे कि दस्त, बुखार और मामूली चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

17. संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संसदीय विशेषाधिकार, संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, प्रतिरक्षा और छूट हैं।
2. संसदीय विशेषाधिकार भारत के राष्ट्रपति तक विस्तृत हैं।
3. संसद अजनबियों को अपनी कार्यवाही से बाहर कर सकती है और कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए गुप्त बैठकें आयोजित कर सकती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

18. सांभर झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है।
2. यह विंध्य श्रेणी में अवनमन को प्रदर्शित करती है।
3. यह केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना में रेगिस्तान सर्किट का हिस्सा है।
4. यह देश की सबसे बड़ी नमक विनिर्माण इकाइयों में से एक है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

19. थार रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाता है।
2. इसके दक्षिण-पश्चिम में अरावली पर्वतमाला सीमा बनाती है।
3. इसकी जलवायु समशीतोष्ण रेगिस्तानी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

20. निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए:

1. कोलैकैंथ (Coelacanth)
2. अश्वनाल केकड़ा (Horseshoe crab)
3. जिन्कगो का पेड़ (Ginkgo tree)

उपर्युक्त में से कौन से जीव जीवित जीवाश्मों के उदाहरण हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

21. स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
2. यह केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वित्तपोषित है।
3. 'नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज' इस मिशन से जुड़ा हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

22. मंदारिन बतख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह दक्षिण एशिया की मूल प्रजाति है।
2. IUCN रेड लिस्ट में इसकी स्थिति 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) कोई नही

23. भारत के निम्नलिखित नियामक निकायों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय रिजर्व बैंक
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
3. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण
4. बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण उपर्युक्त निकायों में से किसके खिलाफ अपील को सुन और निस्तारित कर सकता है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

24. भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा निम्नलिखित में से सरकार की कौन सी योजना/कार्यक्रम प्रदान करती हैं?

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
2. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
3. आयुष्मान भारत
4. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

25. निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों पर विचार कीजिए:

1. SIMBEX-20 : भारतीय नौसेना, सिंगापुर नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास।
2. SITMEX-20 : भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास।

उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

26. अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस (AITUC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका गठन 1921 में हुआ था।
2. लाला लाजपत राय इसके पहले महासचिव थे।
3. इसे नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन (NTUF) और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (RTUC) के रूप में विभाजित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

27. निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए:

1. अचनकमार-अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व- छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
2. अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व- केरल और तमिलनाडु
3. खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान- सिक्किम
4. पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व- मध्य प्रदेश
5. मानस राष्ट्रीय उद्यान- असम

उपर्युक्त में से कौन से स्थान यूनेस्को की 'वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स' सूची में शामिल हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1, 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

28. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक संवैधानिक निकाय है।
2. NCPCR के लिए, 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों का संरक्षण समान महत्व का है।
3. यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

29. निम्नलिखित वायु प्रदूषकों पर विचार कीजिए:

1. सल्फर डाइऑक्साइड
2. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
3. कार्बन डाइऑक्साइड
4. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड
5. कार्बन मोनोऑक्साइड
6. अमोनिया

उपर्युक्त में से कौन से प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में शामिल हैं?

(a) केवल 1, 2, 3 और 4
(b) केवल 2, 3, 5 और 6
(c) केवल 1, 2, 5 और 6

(d) केवल 3, 4, 5 और 6

30. करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह ओडिशा के कालाहांडी जिले में अवस्थित है।
2. उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इस अभ्यारण्य की महत्त्वपूर्ण/प्रमुख वनस्पति है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

31. मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वह भारत के दूसरे केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे।
2. उनकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
3. वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

32. भारतीय नौसेना की निम्नलिखित पनडुब्बियों पर विचार कीजिए:

1. अरिहंत
2. चक्र
3. कलवरी
4. वेला
5. शाल्की

उपर्युक्त पनडुब्बियों में से कौन सी, परियोजना-75 का हिस्सा हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 और 4
(d) केवल 4 और 5

33. जांच एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पॉलीग्राफ टेस्ट, सोडियम पेंटोथल के इंजेक्शन पर आधारित होता है।
2. नार्को परीक्षण टेस्ट में व्यक्ति कृत्रिम निद्रावस्था में पहुँच जाता है।
3. पी -300 टेस्ट एक संदिग्ध के मस्तिष्क की गतिविधि को मैप (पहचान) करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

34. निम्नलिखित में से कौन सा/से गुण स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POPs) की विशेषता है?

1. सजीवों के फैटी एसिड में जैव संचयन
2. पानी में अधिक घुलनशील
3. कम दूरी का पर्यावरण परिवहन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

35. कपास की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह खरीफ की फसल है।
2. यह जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से वृद्धि करती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

36. जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गयी थी।
2. यह शुरुआत में अलीगढ़ में स्थित थी।
3. डॉ मुख्तार अहमद अंसारी इसके पहले चांसलर थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

37. नाग मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत की तीसरी-पीढ़ी की, एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है।
2. इसकी परिचालन सीमा, 100 मीटर से 500 मीटर तक है।
3. यह सभी मौसमों में प्रयुक्त होने वाली मिसाइल है।
4. इसकी एकल-शॉट हिट संभावना 50% है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

38. निम्नलिखित संकेतकों पर विचार कीजिए:

1. अल्पपोषण
2. बाल दुबलापन
3. बाल वृद्धिरोध
4. बाल रुग्णता
5. बाल मृत्यु दर

उपर्युक्त संकेतकों में से कौन से वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) के घटक हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1, 2, 3 और 4
(d) केवल 1, 2, 3 और 5

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अटल सुरंग, औसत समुद्रतल से 10,000 फीट ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है।
2. यह जम्मू और कश्मीर में बनिहाल दर्रे के नीचे बनायी गयी है।
3. सुरंग की कुल लंबाई 9.02 किमी है।
4. इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

40. निम्नलिखित में से किन भारतीय पुलिनो को 'ब्लूफ्लैग' टैग प्राप्त है?

1. पदुबिद्री और कासरकोड पुलिन (कर्नाटक)
2. कप्पड़ पुलिन (केरल)
3. इडेन पुलिन (पुडुचेरी)
4. मरीना पुलिन (तमिलनाडु)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

41. निम्नलिखित हेपेटाइटिस वायरसों पर विचार कीजिए:

1. हेपेटाइटिस ए
2. हेपेटाइटिस बी
3. हेपेटाइटिस सी
4. हेपेटाइटिस डी
5. हेपेटाइटिस ई

उपर्युक्त में से कौन से वायरस दूषित पानी या भोजन के सेवन के माध्यम से प्रसारित होते हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 5
(c) केवल 2 और 3

(d) केवल 2, 3 और 4

42. निम्नलिखित में से किन जल निकायों को रामसर स्थल घोषित किया गया है?
1. लोनार झील- महाराष्ट्र
2. सूर सरोवर- उत्तर प्रदेश
3. काबरताल वेटलैंड- बिहार
4. आसन कंजर्वेशन रिजर्व- उत्तराखंड

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

43. भारत में पाए जाने वाले गिद्धों की निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार कीजिए:
1. ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड गिद्ध
2. लॉन्ग-बिल्ड गिद्ध
3. स्लेंडर-बिल्ड गिद्ध
4. रेड-हेडेड गिद्ध
5. इजिप्टियन गिद्ध

उपर्युक्त प्रजातियों में से कौन सी गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1, 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

44. चापरे वायरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक दुर्लभ इबोला जैसी बीमारी का कारण है जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले बोलीविया में हुई थी।
2. यह एरेनावीरिडे (Arenaviridae) परिवार से संबंधित है।
3. चूहे इस वायरस के प्रमुख रोगवाहक हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

45. मधुमेह के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करियेः
1. इंसुलिन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया कम होने के कारण, टाइप 1 मधुमेह होता है।
2. टाइप 2 मधुमेह, शरीर में इंसुलिन के स्राव की कमी के कारण होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

46. उन्होंने बंगाल के विभाजन के विरोध में सक्रिय रूप से भाग लिया; कम उम्र में अनुशीलन समिति में शामिल हुए; एक ब्रिटिश जज पर बम फेंकने का प्रयास किया; वह थे:
(a) लाला हरदयाल
(b) शचीन्द्र सान्याल
(c) खुदीराम बोस
(d) भगत सिंह

47. निम्नलिखित में से कौन-सा/से, मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है/बढ़ाते हैं?
1. जन्तुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन
2. मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना
3. वनस्पति की मृत्यु

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

48. निम्नलिखित बीमारियों में से कौन-सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती हैं?
1. चिकनगुन्या
2. हेपेटाइटिस B
3. HIV-AIDS

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

49. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्चतर अक्षांशों की तुलना में, निम्नतर अक्षांशों में जीव

विविधता सामान्यत: अधिक होती है।

2. पर्वतीय प्रवणताओं (ग्रेडिएन्ट्स) में, उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जीव विविधता सामान्यत: अधिक होती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

50. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जैव-विविधता हॉटस्पॉट, केवल उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों में अवस्थित हैं।
2. भारत में चार, जैव-विविधता हॉटस्पॉट अर्थात् पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर

1.	(b)	16.	(d)	31.	(c)	46.	(c)
2.	(d)	17.	(c)	32.	(c)	47.	(c)
3.	(c)	18.	(c)	33.	(c)	48.	(b)
4.	(c)	19.	(a)	34.	(a)	49.	(c)
5.	(b)	20.	(d)	35.	(a)	50.	(d)
6.	(a)	21.	(d)	36.	(b)		
7.	(b)	22.	(a)	37.	(b)		
8.	(c)	23.	(c)	38.	(d)		
9.	(a)	24.	(d)	39.	(b)		
10.	(b)	25.	(d)	40.	(c)		
11.	(d)	26.	(b)	41.	(b)		
12.	(c)	27.	(c)	42.	(d)		
13.	(d)	28.	(c)	43.	(c)		
14.	(c)	29.	(c)	44.	(d)		
15.	(a)	30.	(a)	45.	(d)		

1. 'गयाजी बांध' (Gayaji Dam) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह बांध **IIT** (रुड़की) के निर्देशन में फाल्गु नदी पर बनाया गया है।
2. यह भारत का सबसे लंबा रबर बांध है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2
D- न तो 1, न ही 2

उत्तर: C

2. भारत का महान्यायवादी (Attorney General for India) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और प्रधान अधिवक्ता होता है।
2. इसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. 1 अक्टूबर, 2022 को मुकुल रोहतगी दूसरी बार भारत के लिए अटॉर्नी जनरल बनने जा रहे हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1 और 2
B- केवल 2 और 3
C- केवल 2
D- 1, 2 और 3

उत्तर: D

3. 'आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (National List of Essential Medicines – NLEM)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस सूची में 384 दवाओं को शामिल किया गया है।
2. यह सूची देश के प्रधानमंत्री ने लांच की है।
3. इन दवाओं का मुफ्त वितरण सुनिश्चित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से असत्य है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2 और 3
C- केवल 2
D- 1, 2 और 3

उत्तर: B

4. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का मुख्यालय, देश में कहां स्थित है?

A- नई दिल्ली
B- जयपुर
C- कानपुर
D- पुणे

उत्तर: A

5. मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 122 वें स्थान पर है।
2. वर्ष 2021 में भारत की जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष थी।
3. भारत की रैंक वर्ष 2020 में 128 थी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से असत्य है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2 और 3
C- केवल 3
D- 1, 2 और 3

उत्तर: C

6. विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में, भारत विश्व में कौन से स्थान पर है?

A- 6 वां
B- 5 वां
C- 8 वां
D- 7 वां

उत्तर: A

7. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत इथेनॉल उत्पादन हेतु कसावा, गेहूं, टूटे चावल, सड़े आलू आदि का उपयोग करता है।
2. भारत विश्व में 40 प्रतिशत से अधिक चावल का निर्यात करता है।
3. विश्वभर में थाईलैंड चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है।

A- केवल 1 और 2
B- केवल 2 और 3
C- केवल 3
D- 1, 2 और 3

उत्तर: A

8. सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत में महिलाओं को दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है।
2. भारत ने इसके लिए पहला स्वदेशी टीका–"सर्वावैक" विकसित

कर लिया है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2
D- न तो 1, न ही 2

उत्तर: C

9. इंग्लैंड के नए सम्राट 'किंग चार्ल्स-III' के संदर्भ में, सही कथन का चयन कीजिए:

A- आधिकारिक रूप से 13 सितंबर, 2022 को इन्हें सम्राट बनाया गया।
B- वर्तमान में इनकी उम्र 75 वर्ष है।
C- इनकी ताजपोशी लंदन के बकिंघम पैलेस में की गयी।
D- ये महारानी एलिजाबेथ-II के सबसे बड़े पुत्र हैं।

उत्तर: D

10. 36वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में, गलत कथन का चयन कीजिए:

A- 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी केरल कर रहा है।
B- इन खेलों की थीम "खेल से एकता का उत्सव" है।
C- इन खेलों का शुभंकर सावज है।
D- इस बार इन खेलों में मल्लखंब और योगासन जैसे स्वदेशी खेल भी शामिल हैं।

उत्तर: A

11. निम्नलिखित में से कौन-सा खिलाड़ी 'डायमंड लीग-2022' का फाइनल जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है?

A- नीरज चोपड़ा
B- देवेंद्र झझारिया
C- शिवपाल सिंह
D- अचिंत शिउली

उत्तर: A

12. मोहनजोदड़ो (मृतकों का टीला) के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस स्थल की खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गयी थी।
2. यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
3. इस स्थल से विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, बुने हुए कपडे के साक्ष्य मिले हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1 और 2
B- केवल 1 और 3
C- केवल 2 और 3
D- 1, 2 और 3

उत्तर: D

13. करमा पूजा उत्सव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह उत्सव झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम आदि राज्यों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
2. इसका मुख्य उद्देश्य बहनों द्वारा भाइयों के लिए सुख समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना करना।
3. इस उत्सव में 'मांदर' ढोल बजाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1 और 2
B- केवल 2 और 3
C- केवल 2
D- 1, 2 और 3

उत्तर: D

14. विश्व डेयरी सम्मलेन-2022 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सम्मेलन 'पोषण और आजीविका के लिए डेयरी' विषय पर केंद्रित है।
2. यह सम्मलेन भारत में पहली बार वर्ष 1974 में हुआ था।
3. भारत के प्रधानमंत्री ने 12 सितंबर, 2022 को ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1 और 2
B- केवल 1 और 3
C- केवल 2 और 3
D- 1, 2 और 3

उत्तर: D

15. 5 सितंबर, 2022 को किस देश ने पहली नेजल स्प्रे कोविड वैक्सीन तैयार की है?

A- ब्रिटेन
B- भारत
C- चीन
D- रूस

उत्तरः B

16. 'पीएम-श्री' योजना के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्वारा इस योजना की घोषणा की गयी
2. 'पीएम-श्री' स्कूल, नई शिक्षा नीति, 2020 के लिए एक प्रयोगशाला की तरह कार्य करेंगे
3. इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1 और 2
B- केवल 2 और 3
C- केवल 1 और 3
D- 1, 2 और 3

उत्तरः B

17: सितंबर, 2022 में इंडो-पैसिफिक इकोनामिक फ्रेमवर्क समूह की मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से शहरों में किया गया?

A- सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स
B- न्यूयॉर्क और वाशिंगटन
C- वाशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को
D- लॉस एंजिल्स और न्यूयॉर्क

उत्तरः A

18. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के नए प्रमुख कौन हैं?

A- वोल्कर टर्क
B- एंटोनियो गुटेरेस
C- मैरी रॉबिन्सन
D- मिशेल बैचेलेट जेरिया

उत्तरः A

19. न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है?

A- उत्तर प्रदेश
B- उत्तराखंड
C- कर्नाटक
D- मध्य प्रदेश

उत्तरः B

20. निम्नलिखित संस्थानों में से किसने MRI मशीनों में प्रयुक्त भारत की पहली सुपरकंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित किया है?

A- आईयूएसी, नई दिल्ली
B- आईआईटी, मद्रास
C- आईआईटी, दिल्ली
D- आईआईटी, मुंबई

उत्तरः A

21. हाल ही में खबरों में रहा 'ऑपरेशन लंदन ब्रिज' किससे संबंधित है?

A- भारत और इंग्लैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास से।
B- ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु से संबंधित कार्यक्रमों की योजना से।
C- ब्रिटेन के रक्षा बल अभियान से।
D- भारत और ब्रिटेन के मध्य आर्थिक समझौते से।

उत्तरः B

22. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में निम्नलि. खित कथनों पर विचार कीजिए ?

1. इस योजना के तहत, भारत 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2. सीएसआर गतिविधियों का लिवरेज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- दोनों 1 और 2
D- न तो 1 और न ही 2

उत्तरः C

23. कुर्की के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका संबंध उपजाऊ जमीन की बिक्री से है।
2. कुर्की को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वैध दस्तावेज नहीं माना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- दोनों 1 और 2
D- न तो 1 और न ही 2

उत्तरः D

डॉ. वर्गीज कुरियन

डॉ. वर्गीज कुरियन स्वतंत्र भारत के उन गिने चुने लोगों में थे जिन्होंने देश के आर्थिक विकास, कृषि, रोजगार, सहकारिता आंदोलन की मजबूती में अभूतपूर्व योगदान दिया था। वे भारतीय श्वेत क्रांति के जनक थे। प्रत्येक वर्ष 9 सितम्बर को डॉ. वर्गीज कुरियन की पुण्यतिथि होती है। 1965 से 1998 तक वे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत में श्वेत क्रांति की लहर लायी थी, जिससे भारत, विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में उभर कर सामने आया।

1960 के आखिरी दशक में डॉ. कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक परियोजना की शुरूआत की। 25 वर्षों तक चलने वाली परियोजना में रू 1700 करोड़ के निवेश के माध्यम से, ऑपरेशन फ्लड ने प्रतिवर्ष रू 55000 करोड़ मूल्य तक भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने में मदद दी जो कि विश्व के किसी अन्य विकास कार्यक्रम द्वारा प्राप्त उत्पादन से कहीं अधिक था।

ऑपरेशन फ्लड भारत के सबसे बड़े ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में उभरा तथा इससे डेयरी विकास के संस्थागत, तकनीकी, आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक गतिविधियों के बड़े आयाम खुले।

डॉ. कुरियन के नवीन विचार तथा नेतृत्व से न केवल डेयरी विकास के कार्यों में मदद मिली बल्कि अन्य क्षेत्रों जैसे-खाद्य तेलों, फलों एवं सब्जियों के क्षेत्रों में भी मदद मिली।

भारत सरकार के अनुरोध पर उन्होंने 90 के मध्य दशक में दिल्ली में फलों एवं सब्जियों की प्राप्ति एवं विपणन के लिए एक पॉयलट परियोजना की शुरूआत की। यह परियोजना विभिन्न राज्यों के फल एवं सब्जी के उत्पादकों तथा दिल्ली के उपभोक्ताओं के मध्य सीधा संबंध उपलब्ध कराने पर केंद्रित थी।

डॉ. कुरियन ने 1979 में 'धारा' सहकारी परियोजना लांच करके खाद्य तेलों के व्यवसाय में भी क्रांति ला दी। तिलहन उत्पादकों की सहकारी परियोजना से उत्पादकों एवं तेलों के उपभोक्ताओं के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित हुआ जिससे तेल व्यापारियों की भूमिका घटी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य तेल की कीमतों में स्थिरता लाना, खाद्य आयातों पर भारत की निर्भरता कम करना तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए तिलहन उत्पादकों को प्रोत्साहित करना था।

डॉ. कुरियन एक दूरदर्शी व्यक्ति थे तथा वे संस्थान निर्माता के रूप में विख्यात हुए। पूरे देश में स्थापित होने वाली सहकारिताओं को प्रबंधन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने 1979 में आणंद में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट (इरमा) की स्थापना की। देश की राज्य सहकारी डेयरी महासंघों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने 1988 में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के पुनर्गठन को सहायता प्रदान की। आणंद के विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तायुक्त स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने आनंदालय शिक्षा समिति की स्थापना की।

1994 में, उन्होंने विद्या डेयरी स्थापित करने में मदद की ताकि डेयरी प्रौद्योगिकी में स्नातक होने वाले विद्यार्थियों को डेयरी संयंत्र प्रबंधन का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा सके। वे 1973 से 2006 तक गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कार्यरत रहे।

संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं को व्यवस्थित आकार देने में डॉ. कुरियन का मुख्य योगदान रहा है, जिससे लोगों ने स्वयं को विकसित किया। उनका मानना था कि लोगों के हाथों में विकास के उपकरण उपलब्ध करा कर मानव का विकास किया जा सकता है। उनका यह भी मानना था कि इस देश की सबसे श्रेष्ठ सम्पत्ति इस देश के लोग हैं, जिन्होंने इस प्रकार से अपना पूरा जीवन लोगों की शक्ति को काम में लाने के कार्य में समर्पित किया जिनसे उनके व्यापक हितों को बढ़ावा मिले।

डॉ. वर्गीज कुरियन ने अपने कार्यकाल के दौरान कई सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त किए जिनमें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रमन मेग्सेसे पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, कृषि रत्न पुरस्कार, वाटेलर शांति पुरस्कार, कार्नेगी फाउंडेशन पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व डेयरी एक्सपो पुरस्कार, विस्कॉन्सिन पुरस्कार, यूएसए द्वारा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति का सम्मान शामिल हैं।

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

ANNUAL SUBSCRIPTION OF PERFECT 7 CURRENT AFFAIRS MAGAZINE (FORTNIGHTLY)

About Perfect 7:

The role of Current Affairs in Civil Services has tremendously increased, in all the subjects of General Studies like Economy, Polity, Science and Technology, International Relations, Environment, etc.

Need: Knowledge of Current Affairs

Inadequate Solution: Monthly Magazines available in the Market.

Why Inadequate?

- All magazines are monthly: This means that you get to know about the event after more than one month and students are unable to match the pace with newspaper and other media.
- Not suitable for Civil Services: Events are not analyzed as these magazines also cater to the one day exams and hence they provide only factual information's.
- Too much to read in one go: A student is suddenly burdened to cover too many events in a short time which leads to stress.

Solution to all the above three issues is PERFECT 7 Magazine by Dhyeya IAS.

- Released Fortnightly: A student is abreast with the current events of the month, near real time.
- Detailed Analysis of every event: Civil Services demands a deeper understanding of events, concepts and its analyses and not just know the event and its date.
- Easy to study: Since the magazine is fortnightly, a student is saved from Information overload and can relate with the newspaper, TV and other media coverages with a profound understanding of the current happenings.

Features of PERFECT 7

Important conditions for an IAS/PCS centered magazine		PERFECT 7	OTHERS
• Fortnightly	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Civil Services Exam centered	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Micro-Analysis of current issues & not a mere compilation of facts	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Brain boosters for important issues	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Multiple choice questions & their solution based on brain boosters	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Case studies with model answers for Ethics	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Explanation of important theories through pictures & graphics.	Hindi	✓	×
	English	✓	×

(* some institutes)

Annual Subscription Fee along with Courier Charges:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Courier Charges:	30 X 24 = Rs 720
Total Charges:	**Rs 1530**

Annual Subscription Fee for Student Collecting Magazine form Mukherjee Nagar Centre:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Total Charges:	**Rs 810**

BANK ACCOUNT DETAILS

Account Holder:-	**Trueword Publication Private Limited**
Bank A/C -	**50200032675602**
IFSC:-	**HDFC0000609**

Terms and Condition:

1. Fee submitted one will not be refunded or adjusted in any condition.
2. Dhyeya IAS ensures no damage or delay during transit however some unavoidable circumstances are beyond our control. responsibility for the delay in delivery,
3. W put best efforts to make the Magazine reach to the subscribers by 10th & 25th of every month.
4. If due to COVID-19 Pandemic or any unforeseen natural disaster or by an act of God, Dhyeya IAS is not able to print the Magazine then the duration of subscription will be increased to compensate for the same.

Whatsapp: ***9205184003***

dhyeyaias.com

AN INTRODUCTION

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Dhyeya IAS, two decades old institution, was founded by Mr.Vinay Singh and Mr. Q. H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential aspirants realize their dreams which is evident from the success stories of the previous years.

As the nation progresses, the young generations become more conscious and aware about their career options. There is plethora of jobs and one among them is civil services, the most prestigious service in the country, which needs no introduction. It attracts many young minds hailing from almost all spectra of academic disciplines. The popular belief that the examination for this service is only meant for the brilliant lots has become a taboo as it also attracts the hardworking, sincere and disciplined minds. The saying- "In the end passion and hard work can substitute natural talent" holds true. It gives immense power and opportunity for young folks to bring about the positive changes in the society which would bring harmony and development. It inculcates values, moral, ethos and feeling of national integrity.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move may invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals' capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything, you can only help him find it within himself.

We feel that despite brilliance and diligence, most of the students are lacking proper guidance and aptitude needed to clear Civil Services Examination. This is why, we at Dhyeya IAS amalgamated the traditional as well as modern approach of teaching by incorporating best educators of the industry ably supported by Academic Associates, Class Notes and printed Study Material, routine as well as surprise Tests. Due to its arduous efforts, Dhyeya IAS is able to carve a niche among all the civil services coaching institutes in India. Access to an institution is as important as the quality of Institution. Our faith in this philosophy made us grow. With 12 Face to Face Centers located in different parts in India, Distance Learning Program , Live Streaming Centers and Residential Academy, we have made truly pan India presence. Ever since the foundation the institute has produced a heavy pool of bureaucrats both at central and state level. Dhyeya IAS not only aims at imparting the content of civil services in best way but also nurturing the aspirants as leaders of tomorrow who have a responsibility of fulfilling the dreams of around 1.4 billion Indians. Dhyeya IAS has guided over 50,000 aspirants with more than 4500 selections in civil services. Our journey is a small contribution for the development of the society and nation by nurturing the potential civil services aspirants.

Considering the toughness of Civil Services Exam, where success rate is a meager 0.1 percent, Dhyeya IAS has continuously produced phenomenal results over the years. Year after Year Dhyeya IAS is being recognized for imparting guidance to civil services aspirants using benchmarked quality practices. On the basis of scalability, innovation, achievements, impact potential our efforts and contribution have been acknowledged and rewarded with Education Excellence Awards by ET NOW, Brands Academy, Times of India, etc. This has enhanced motivation, pride and self-esteem of entire Dhyeya family.

₹ 45

For feedback write to us at :-
perfect7magazine@gmail.com

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I B**hubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744